



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 2017/श्रावण 6, 1939

No. 187]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2017/SRAVANA 6, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2017

अंतिम जांच परिणाम

विषय: चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स, चाहे वह उप व्यवस्था के भाग के रूप में अथवा पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स के उद्देश्य से एक उपकरण/संघटक का एक भाग के रूप में कच्चे, तैयार अथवा उप व्यवस्थित रूप में मशीन किया गया हो अथवा न किया गया हो, के लिए कास्टिंग" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 14/28/2013-डीजीएडी: समय-समय पर यथा संशोधित, सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात यहां अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. जबकि मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लि. (जिन्हें इसके बाद याचिकाकर्ता भी कहा गया है) ने चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु भी कहा गया है), चाहे वह उप व्यवस्था के भाग के रूप में अथवा पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स के उद्देश्य से एक उपकरण/संघटक का एक भाग के रूप में कच्चे, तैयार अथवा उप व्यवस्थित रूप में मशीन किया गया हो अथवा न किया गया हो, के लिए कास्टिंग" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने के लिए इस अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष पाटन और परिणामी क्षति का आरोप लगाते हुए

एक आवेदन दायर किया है और उपर्युक्त संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। मैसर्स पटेल अलॉयज स्टील प्रा. लि. (जिसे एतदपश्चात् "पटेल अलॉयज" के रूप में भी कहा गया है) ने इस याचिका का समर्थन किया है।

3. और जबकि प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 01 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 14/28/2013-डीजीएडी द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की सिफारिश करने, यदि कोई लगाया जाता है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, पर्याप्त रूप से समाप्त हो जाएगी, के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार उपर्युक्त देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में इस पाटनरोधी जांच को शुरू किया गया।
4. मैसर्स ब्रेडकेन इंडिया प्रा. लि. ने एक वर्तमान चिंता के रूप में दिनांक 03 मार्च, 2016 के इस जांच के प्रारंभ होने के पश्चात् मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लि. से कोयंबटूर में संबद्ध वस्तुओं की विनिर्माण सुविधाओं की खरीद की है और वर्तमान जांच में याचिकाकर्ता के रूप में तर्क दिया है। संगत दस्तावेजों को हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइल में रखा गया है।

ख. सामान्य प्रक्रिया

5. यहां नीचे उल्लेख की गई प्रक्रिया का पालन प्राधिकारी द्वारा इस विषयगत जांच के संबंध में किया गया है:
 - i. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के पैरा के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही से पूर्व पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने के लिए अनुरोध करते हुए घरेलू उद्योग से वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
 - ii. नई दिल्ली में संबद्ध देश के दूतावासों/प्रतिनिधियों को भी नियम 6(2) के अनुसार, जांच प्रारंभ करने के बारे में सूचना दी गई थी।
 - iii. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच आरंभन अधिसूचना की एक प्रति भेजी है और उनसे जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से परिचित कराने का अनुरोध किया है।
 - iv. प्राधिकारी द्वारा ऊपर नियमावली के नियम 6(3) के अनुसरण में भारत में संबद्ध देश के दूतावास और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय रुपांतरण की एक प्रति उपलब्ध कराई गई है।
 - v. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए चीन के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र/प्रश्नावली की एक प्रति चीन जन गण के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ-साथ उन्हें भी भेजी गई थी।
 - vi. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसरण में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संगत जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यातक प्रश्नावली भेजी:
 - क. बीजिंग बेलिंग फाउंड्री कं. लि.
 - ख. बीजिंग ग्लोबल टेक्नोटेड ग्रुप (बीजीटीजी)
 - ग. चांगझोऊ शुआंगे मशीनरी एंड इलैक्ट्रिक कं. लि.
 - घ. चांगझोऊ सिनोजीत विंड एनर्जी टेक कं. लि., चीन जन गण
 - ङ. सीएसआर सिफांग कं. लि.
 - च. डलियन विंगशान ग्रुप रेफ्रिजिरेटिंग इक्विपमेंट कं. लि.
 - छ. डलियन हुआरुई हैवी इंडस्ट्री स्टील कास्टिंग कं. लि.
 - ज. डलियन हुआरुई हैवी इंडस्ट्री कास्टिंग कं. लि.
 - झ. डलियन हुआरुई हैवी इंडस्ट्री इंटरनेशनल कं. लि.
 - ञ. डलियन हुआरुई हैवी इंडस्ट्री स्टील कास्टिंग ज्वाइंट स्टॉक कं. लि.
 - ट. दिंगझोऊ दोंगफांग फाउंड्री कं. लि.

- ठ. जेक्सप्रो इंडस्ट्री सप्लाय शंघाई कं. लि.
- ड. गोंगझोऊ हिनर्जी कं. लि.
- ढ. हाइड्रा ग्रेन हाइड्रोलिक्स इक्विपमेंट एसेसरी (तियांजिन) कं. लि.
- ण. जियांगिन फेंगदियान फ्लेंज मैनुफैक्चर कं. लि.
- त. जियांगसू जिक्सिन विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कं. लि.
- थ. जियांगसू वेनहुई सील इंजीनियरिंग कं. लि.
- द. जियांगसू फॉ फाउंड्री कं. लि.
- ध. जिनान डबल विन यूनिटी मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कं. लि.
- न. लियान फ्लाइंग इंडस्ट्री कं. लि.
- प. जियांगिन हेंग्रन रिंग फॉर्जिंग कं. लि.
- फ. नानजिंग यिसुमान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग कं. लि.
- ब. नानटोंग होंगडे मैकेनिकल कं. लि.
- भ. निंगबो गिनलोंग टेक्नोलॉजीस कं. लि.
- म. निंगबो सेव्स मशीनरी कं. लि.
- य. किंगदाओ एयोलस विंग एनर्जी कं. लि.
- कक. किंगदाओ अनहुआ न्यून एनर्जी इक्विपमेंट कं. लि.
- खख. किंगदाओ आर. एच. एस. इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लि.
- गग. किंगदाओ प्रिसिसन मशीनरी कं. लि.
- घघ. शांक्सी किंचन मशीनरी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.
- ङङ. सतराम चाइना कं. लि.
- चच. शेनझेन शेंगक्सन ट्रेडिंग कं. लि.
- छछ. शानडोंग लाइवू जिनलेई विंड पावर टेक्नोलॉजी कं. लि.
- जज. शंघाई सिलिक ई एंड ए इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि.
- झझ. शंघाई झोंग झु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.
- ञञ. शेनयांग हुआली एनर्जी इक्विपमेंट मैनुफैक्चरिंग कं. लि.
- टट. शेनझेन हेजिया ट्रेडिंग कं. लि.
- ठठ. किंगदाओ सिनोट्रांस बाउंडेड वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स कं. लि.
- डड. शी जिया झुआंग दानझोऊ ट्रेड कं. लि.
- ढढ. सिनोवेल विंड ग्रुप कं. लि.
- णण. तियानजिन कैलोंग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कं. लि.
- तत. तियानजिन म्युनिसिपल हाईवे फैसिलिटीज इंजीनियरिंग कं. लि.
- थथ. टेक्टोन (एचके) एनर्जी टेक्नोलॉजी कं. लि., चीन जन गण
- दद. वफांगदियान मोस-डब्ल्यूआरसी बियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं. लि.
- धध. वेनझोऊ कैचेंग फाउंड्री कं. लि.
- नन. वुजी टेकेंग स्टील स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कं. लि.
- पप. यिआंग गुआं एनर्जी टेक. ग्रुप – जियांगसू ब्राइट स्टील फाइन मशीनरी कं. लि., चीन जन गण

- फफ. यिओंग गुआं एनर्जी टेक. ग्रुप – डोंगुआं यिओंग गुआं माउलड फैक्ट्री, चीन जन गण
- बब. यिओंग गुआं एनर्जी टेक. ग्रुप – यिओंग घेन एशिया पेसिफिक कं. लि., चीन जन गण
- भभ. यिओंग गुआं एनर्जी टेक. ग्रुप – निंगबो लु लिन मशीन टूल फाउंड्री कं. लि., चीन जन गण
- मम. यिओंग गुआं एनर्जी टेक. ग्रुप – निंगबो यिओंग शांग कास्टिंग आयरन गो. लि., चीन जन गण
- यय. झुझोऊ टाइम्स न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कं. लि.
- कक. झुझोऊ जियाबांग फोटोइलैक्ट्रिक मैटेरियल कं. लि.
- खख. झेजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी कं. लि.
- vii. संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातकों की प्रश्नावली का उत्तर दायर किया:
- क. डलियन हैवी इंडस्ट्री कास्टिंग कं. लि.
- ख. जियांग्सू फॉ फाउंड्री कं. लि.
- ग. झेजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी कं. लि.
- घ. जियांग्सू सिनोजीत विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कं. लि.
- चांगझोऊ विंड सिनोजीत विंड एनर्जी टेक. कं. लि.
- जिंजिन हेंघुआ मशीनरी कं. लि., जिंजिन सिटी
- जिंजिन क्विक्सिंग टेक्नोलॉजी कं. लि., जिंजिन सिटी
- जिंजिन चांगलिंग न्यू एनर्जी कं. लि., वुक्सी सिटी, जियांग्सू
- टेकटोन एचके लि.
- ङ. नानटोंग होंडगे मैकेनिकल कं. लि. एंड कोईजुमी मशीनरी कं. लि.
- च. युओंग गुआं एनर्जी टेक. ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- डोंगुआं यिओंग गुआं माउलड फैक्ट्री कं. लि.
- जियांग्सू ब्राइट स्टील फाइन मशीनरी कं. लि.
- निंगबो लु लिन मशीन टूल फाउंड्री कं. लि.
- निंगबो यिओंग कास्टिंग आयरन कं. लि.
- यिओंग एसिया पेसिफिक कं. लि.
- viii. युओंग गुआं एनर्जी टेक ग्रुप कं. लि., और इसकी सहायक कंपनियों को छोड़कर, चीन जन गण के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव (एमईटी) की प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इस कारण से अन्य सहयोगी निर्यातकों को वर्तमान जांच में गैर बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव दिया गया है। युओंग गुआं एनर्जी टेक ग्रुप कं. लि., चीन जन गण और इसकी सहायक कंपनियों ने बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव का दावा किया है और बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव (एमईटी) प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।
- ix. चीन चैंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ मशीनरी एंड इलैक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट (सीसीसीएमई), जो उपर्युक्त जांच के विषयगत मर्चेन्डाइज के उत्पादकों/निर्यातकों का एक संघ है, ने इस जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में अनुरोध किया है।
- x. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसरण में आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातकों की प्रश्नावली भेजी:
- क. मैसर्स चिरजीवी विंड एनर्जी लिमिटेड, कोयंबटूर
- ख. मैसर्स गमेसा विंड टरबाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
- ग. मैसर्स जीई इंडिया इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर
- घ. मैसर्स ग्लोबल विंड पावर लिमिटेड, चेन्नई

- ड. मैसर्स इनोक्स विंड लिमिटेड, नोएडा
- च. मैसर्स लीटविंड श्रीराम मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड, थिरुवल्लूर
- छ. मैसर्स पायोनियर विनकोन प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
- ज. मैसर्स रेजेन पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
- झ. मैसर्स आरआरबी एनर्जी लिमिटेड, चेन्नई
- ञ. मैसर्स श्रीराम ईपीसी लिमिटेड, चेन्नई
- ट. मैसर्स सिवा विंड टरबाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इरोड
- ठ. मैसर्स साउदर्न विंड फार्म्स लिमिटेड, चेन्नई
- ड. मैसर्स विंड वर्ल्ड (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई
- ढ. मैसर्स सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, पुणे
- xi. मैसर्स इनोक्स विंड लि. को छोड़कर ऊपर में सूचीबद्ध किसी भी आयातक ने आयातक की प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।
- xii. इंडियन विंड टरबाइन मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडब्ल्यूटीएमए), जो उपर्युक्त जांच के विषयगत मर्चेन्डाइज के आयातकों का एक संघ है, ने इस जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में अनुरोध किया है।
- xiii. जांच प्रारंभन अधिसूचना संबद्ध वस्तुओं के भारत में निम्नलिखित अन्य घरेलू उत्पादकों को भेजी गई थी। हालांकि, किसी भी अन्य उत्पादक ने उसका उत्तर नहीं दिया है।
- क. लक्ष्मी मशीन वर्क्स
- ख. वक्ष स्टील प्रा. लि.
- ग. वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लि.
- xiv. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
- xv. आवेदक ने आईबीआईएस स्रोत से लेन-देन वार आयात आंकड़े प्रस्तुत किए थे और प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के लिए उस पर प्रथम दृष्टया विश्वास किया था।
- xvi. वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) को अनुरोध किया गया था कि वह पिछले तीन वर्षों तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देन वार ब्यौरा उपलब्ध कराए जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है और लेन-देन की उचित जांच के बाद विश्लेषण की अपेक्षा जताई है तथा इस जांच परिणाम में उस पर भरोसा किया है। डीजी सिस्टम आंकड़ों का उपयोग जहां भी लागू हो, विश्लेषण को पूरा करने के लिए किया गया है।
- xvii. सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की आदर्शतम लागत तथा उन्हें बनाने और बेचने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क लगाना क्या घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xviii. तदनुसार, घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत पीसीएन के रूप में निर्धारित की गई है।
- xix. निर्दिष्ट प्राधिकारी पद्धति में परिवर्तन के कारण तथा एटीएमए मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुरूप, नए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 16 दिसंबर, 2016 को दूसरी मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी जिसमें घरेलू उद्योग और चीन जन गण के निर्यातक, निर्यातक संघ, आयातक, आयातक संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह सुनवाई नए याचिकाकर्ता के स्थान तथा ब्रेडकेन को मैसर्स एलएंडटी से कास्टिंग बिजनेस प्रभाग का स्वामित्व के परिवर्तन के मुद्दे तक ही सीमित था। हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई के समय मौखिक रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, को उक्त मामले के अनुसरण में मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में दायर करने की सलाह दी गई थी तथा उन्हें

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को प्रस्तुत करने के लिए प्रत्युत्तर पेश करने के लिए अवसर दिया गया था।

- xx. प्राधिकारी ने इस मामले के गुण दोष के संबंध में नियम 6(6) के अनुसरण में, 03 मई, 2017 को हुई तीसरी मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से संगत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर उपलब्ध कराया था जिनमें घरेलू उद्योग, चीन जन गण के निर्यातक, निर्यातक संघ, आयातक और आयातक संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई के समय मौखिक रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में दायर करने की सलाह दी गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को प्रस्तुत करने के लिए प्रत्युत्तर पेश करने के लिए अवसर दिया गया था।
- xxi. राजस्व विभाग ने नियम 17(1) के संबंध में, 30 जुलाई, 2017 तक इस जांच को पूरा करने के लिए समयावधि बढ़ाई है।
- xxii. घरेलू उद्योग तथा सहयोगी निर्यातकों के आंकड़ों का मौके पर जाकर सत्यापन आवश्यक सीमा तक किया गया था। केवल आवश्यक संशोधन, जहां भी लागू हो, के साथ इस प्रकार की सत्यापित सूचना पर इस जांच परिणाम के उद्देश्य से भरोसा किया गया है।
- xxiii. इस जांच परिणाम की अवधि के दौरान जहां भी संगत पाया गया, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध का समाधान प्राधिकारी द्वारा इस जांच परिणाम में किया गया है।
- xxiv. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतोषजनक पाए जाने पर, प्राधिकारी ने जहां भी जरूरत थी, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय समझा गया है तथा इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
- xxv. जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान पहुँच से इंकार किया है या अन्यथा रूप से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या उल्लेखनीय रूप से जांच को बाधित किया है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकटन विवरण को दर्ज किया है।
- xxvi. नियमावली के अनुसरण में प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के लिए 11 जुलाई, 2017 को इस मामले के सभी आवश्यक तथ्यों को शामिल करते हुए एक प्रकटन विवरण जारी किया। जिस सीमा तक टिप्पणियां संगत थीं, उस सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों का समाधान उपयुक्त स्थानों पर इस जांच परिणाम में कर दिया गया है।
- xxvii. *** इस अधिसूचना में हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है और नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इसी प्रकार विचार किया जाता है।
- xxviii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 62.66 रुपए = 1 अमेरिकी डॉलर है।

ख. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

- 6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स, चाहे वह उप व्यवस्था के भाग के रूप में अथवा पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स के उद्देश्य से एक उपकरण/संघटक का एक भाग के रूप में कच्चे, तैयार अथवा उप व्यवस्थित रूप में मशीन किया गया हो अथवा न किया गया हो, के लिए कास्टिंग" है। पवन चालित विद्युत जेनरेटर के लिए कास्टिंग को "विंड मिल" अथवा "विंड टरबाइन" के रूप में भी जाना जाता है।
- 7. एक विंड मिल में अनेक कास्टिंग पार्ट्स अपेक्षित हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - i. हब, रोटो हब, रोटर नेब
 - ii. मैन फ्रेम, बेस फ्रेम, मैन फाउंडेशन, नेसेल, नेसेल फ्रेम, नेसेल फाउंडेशन
 - iii. बियरिंग हाउसिंग, बियरिंग सपोर्ट
 - iv. हॉलो शॉफ्ट
 - v. मैन एक्सल, कोटर, शॉफ्ट, मैन शॉफ्ट, रोटर कपलिंग, एक्सल पिन
 - vi. लेक्टेरल सस्पेंडर

- vii. पिच स्टॉप, स्टेटर
- viii. जेनरेटर कास्टिंग्स, पार्ट ऑफ जेनरेटर्स, रोटार
- ix. टोर्की आर्म सपोर्ट, गियर बॉक्स

8. उत्पाद के कार्य क्षेत्र में विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र के भीतर सिर्फ विंड टरबाइन कास्टिंग शामिल है। कास्टिंग को यदि कच्चे/तैयार न किए गए/अर्ध तैयार के रूप में आयात किया जाता है अथवा उप व्यवस्था उपकरणों के भाग के रूप में आयात किया जाता है तो ये विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र के भीतर होते हैं। इसी कास्टिंग का मूल कार्य कुछ अन्य गैर कास्टिंग पार्ट्स और संघटकों जैसे ब्लेड आदि के साथ-साथ विंड मिल में उपयोग किए जाने के लिए विंड टरबाइन में होता है जिसके फलस्वरूप बिजली पैदा होती है।
9. संबद्ध वस्तु को सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमा शुल्क उप शीर्षक संख्या 8503 में मिला दिया जाता है, उनका आयात भी अन्य प्रशुल्क शीर्षक अर्थात् अध्याय 84 और 85 में 84834000, 85030090, 85030010 के अंतर्गत आयात किया जा रहा है। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
10. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयात की गई संबद्ध वस्तुओं में भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विविधीकरण, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं का शुल्क का वर्गीकरण जैसे मानदंडों के मामले में तुलनीय विशेषताएं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयात की गई वस्तु इस नियमावली के अनुसार समान वस्तु हैं।

निर्यातक, आयातक, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

11. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के कार्य क्षेत्र के संबंध में निर्यातकों/आयातकों/हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किया गया है:
 - i. शामिल उत्पाद पवन चालित विद्युत जेनरेटर के लिए कास्टिंग है जिसे विंड मिल अथवा विंड टरबाइन के लिए कास्टिंग के रूप में भी जाना जाता है। इस उत्पाद में ग्राहकों के अनुरोध के आधार पर विभिन्न आकारों जैसे मशीन किए गए उत्पाद, तैयार अथवा उप व्यवस्थित उत्पाद, उप व्यवस्था का पार्ट्स अथवा उपकरण/संघटक का एक भाग के रूप में, जो पवन चालित विद्युत जेनरेटरों के लिए बनाया जाता है, शामिल है।
 - ii. भारत सहित अन्य देशों में निर्यात किए गए तथा घरेलू बाजार में बेची गई वस्तुओं के बीच भौतिक/तकनीकी/रासायनिक विशेषताओं में कोई अंतर नहीं है।
 - iii. मैसर्स एलएंडटी ने चीन जन गण से "पवन चालित विद्युत जेनरेटर के लिए कास्टिंग" के आयात के विरुद्ध जांच प्रारंभ करने की मांग की है। हालांकि, वर्तमान जांच "पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स, चाहे वह उप व्यवस्था के भाग के रूप में अथवा पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स के उद्देश्य से एक उपकरण/संघटक का एक भाग के रूप में कच्चे, तैयार अथवा उप व्यवस्थित रूप में मशीन किया गया हो अथवा न किया गया हो, के लिए कास्टिंग" के विरुद्ध जांच प्रारंभन अधिसूचना के माध्यम से शुरू की गई है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कहीं भी इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि किस प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया है। प्राधिकारी के लिए यह सही नहीं है कि वे अपने आप विचाराधीन उत्पाद को उसके लिए बिना किसी तार्किक कारण दिए बिना उसमें उसके पार्ट्स को शामिल करें तथा बिना औचित्य दिए इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया है। जांच प्रारंभन संबंधी अधिसूचना मैसर्स एलएंडटी के अधिकार से बाहर चला गया है – निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि किस प्रकार से विचाराधीन उत्पाद का कार्य क्षेत्र का दिनांक 24 जुलाई, 2015 के पत्र के अनुसार विस्तार किया गया है और संगत कारणों के साथ इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का उद्देश्य किया है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

12. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स, चाहे वह उप व्यवस्था के भाग के रूप में अथवा पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स के उद्देश्य से एक उपकरण/संघटक का एक भाग के रूप में कच्चे, तैयार अथवा उप व्यवस्थित रूप में मशीन किया गया हो अथवा न किया गया हो, के लिए कास्टिंग" है।

- ii. विंड मिल में हब, रोटो हब, रोटर नेब, मैन फ्रेम, बेस फ्रेम, मैन फाउंडेशन, नेसेल, नेसेल फ्रेम, नेसेल फाउंडेशन, बियरिंग हाउसिंग, बियरिंग सपोर्ट, होलोसाफ्ट, मैन एक्सल, रोटर शॉफ्ट, रोटर कपलिंग, एक्सल पिन, मैन शॉफ्ट, लेटरल सस्पेंडर, पिच स्टॉप, स्टेटर, जेनरेटिंग कास्टिंग, जेनरेटर्स का पाटर्स, रोटर, टोर्क आर्म सपोर्ट आदि सहित अनेक कास्टिंग पाटर्स अपेक्षित हैं।
- iii. यह उत्पाद प्राथमिक रूप से संख्या/पीस में बेची जाता है। कीमत किसी विशेष कास्टिंग में शामिल डिजाइन, आकार, वजन एवं प्रसंस्करण पर निर्भर करती है। दो अलग-अलग विंड मिलों के हब जैसे समान प्रकृति के दो कास्टिंग शामिल प्रक्रिया और संबद्ध भार, डिजाइन, मशीनरी के संबंध में समान नहीं हो सकती है। इस कारण से लागत एवं कीमत के संबंध में इन दोनों बहुत अधिक अंतर हो सकता है।
- iv. किसी कास्टिंग का मूल कार्य कुछ अन्य गैर कास्टिंग पाटर्स और संघटकों जैसे ब्लेड आदि के साथ-साथ विंड मिल में उपयोग किए जाने के लिए विंड टरबाइन में होता है जिसके फलस्वरूप बिजली पैदा होती है।
- v. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 के अंतर्गत किया गया है जिसमें "इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण तथा उसका पाटर्स; साउंड रिकार्ड और रि-प्रोड्यूसर, टेलीविजन इमेज और साउंड रिकार्ड और रि-प्रोड्यूसर तथा इस प्रकार की वस्तुओं के पाटर्स एवं एसेसरीज" शामिल है। इस उत्पाद का समर्पित वर्गीकरण नहीं होता है।
- vi. याचिकाकर्ता ने एक पीसीएन पद्धति का सुझाव दिया था जिसका उपयोग पाटन मार्जिन, कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए उत्पाद प्रकार की पहचान करने के लिए किया जाता है। जब निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसको अपनाया भी गया है और किसी पक्षकार ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।
- vii. इस पीसीएन प्रणाली का उपयोग सीबीडी मामले में क्षति के मार्जिन के निर्धारण के लिए भी किया गया था जिसमें अंतिम जांच परिणाम को पहले ही अधिसूचित किया गया है।
- viii. विचाराधीन उत्पाद की औसत कीमत भ्रामक है। वास्तव में पाटन मार्जिन, कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन का निर्धारण केवल इस कारण से पीसीएन के आधार पर किया गया है कि औसत कीमत विश्लेषण भ्रामक है।
- ix. याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयात की गई संबद्ध वस्तुओं में भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विविधीकरण, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं का शुल्क का वर्गीकरण जैसे मानदंडों के मामले में तुलनीय विशेषताएं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं और चीन जन गण से आयात की गई वस्तु आवश्यक उत्पाद लक्षणों के मामले में तुलनीय हैं। वास्तव में, संबद्ध वस्तुओं का व्यापक तौर पर उत्पादन विशिष्ट ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा दी जाने वाली वस्तु चीन जन गण से आयात की गई वस्तुओं के समान वस्तु है। सभी पाटर्स को ग्राहक के विनिर्देशनों के अनुसार ही बनाया जाता है।
- x. इस जांच का कार्य क्षेत्र वही है जो इस याचिका में विचाराधीन उत्पाद का कार्य क्षेत्र है। इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

13. विचाराधीन उत्पाद का अभिप्राय एवं कार्य क्षेत्र की परिभाषा प्राधिकारी द्वारा जांच प्रारंभन संबंधी अधिसूचना में नीचे दिए गए अनुसार दी गई है:

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स, जिसे विंड मिल अथवा विंड टरबाइन के लिए कास्टिंग के रूप में भी जाना जाता है, चाहे वह उप व्यवस्था के भाग के रूप में अथवा पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स के उद्देश्य से एक उपकरण/संघटक का एक भाग के रूप में कच्चे, तैयार अथवा उप व्यवस्थित रूप में मशीन किया गया हो अथवा न किया गया हो, के लिए कास्टिंग' है।"

4. विंड मिल में हब, रोटो हब, रोटर नेब, मैन फ्रेम, बेस फ्रेम, मैन फाउंडेशन, नेसेल, नेसेल फ्रेम, नेसेल फाउंडेशन, बियरिंग हाउसिंग, बियरिंग सपोर्ट, होलोसाफ्ट, मैन एक्सल, रोटर शॉफ्ट, रोटर कपलिंग, एक्सल पिन, मैन शॉफ्ट, लेटरल सस्पेंडर, पिच स्टॉप, स्टेटर, जेनरेटिंग कास्टिंग, जेनरेटर्स का पाटर्स, रोटर, टोर्क आर्म सपोर्ट आदि सहित अनेक कास्टिंग पाटर्स अपेक्षित हैं। इन कास्टिंग का उपयोग कुछ अन्य गैर कास्टिंग पाटर्स और संघटकों जैसे ब्लेड आदि के साथ-साथ विंड टरबाइन में होता है जिसके फलस्वरूप बिजली पैदा होती है। इस प्रकार के सभी कास्टिंग्स, चाहे वह उप व्यवस्था के भाग के रूप में अथवा पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स के उद्देश्य से एक

उपकरण/संघटक का एक भाग के रूप में कच्चे, तैयार अथवा उप व्यवस्थित रूप में मशीन किया गया हो अथवा न किया गया हो, के लिए कास्टिंग" को वर्तमान जांच में शामिल किया गया है।

14. हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच याचिकाकर्ता कंपनियों के परिसरों में मौके पर सत्यापन करते हुए तथा इन पक्षकारों से संगत सूचना की मांग करते हुए की गई है।

15. प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

- i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स, चाहे वह उप व्यवस्था के भाग के रूप में अथवा पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स के उद्देश्य से एक उपकरण/संघटक का एक भाग के रूप में कच्चे, तैयार अथवा उप व्यवस्थित रूप में मशीन किया गया हो अथवा न किया गया हो, के लिए कास्टिंग" है।
- ii. विंड मिल में हब, रोटो हब, रोटार नेब, मैन फ्रेम, बेस फ्रेम, मैन फाउंडेशन, नेसेल, नेसेल फ्रेम, नेसेल फाउंडेशन, बियरिंग हाउसिंग, बियरिंग सपोर्ट, होलोसाफ्ट, मैन एक्सल, रोटार शॉफ्ट, रोटार कपलिंग, एक्सल पिन, मैन शॉफ्ट, लेटरल सस्पेंडर, पिच स्टॉप, स्टेटर, जेनरेटिंग कास्टिंग, जेनरेटर्स का पाटर्स, रोटार, टोर्क आर्म सपोर्ट आदि सहित अनेक कास्टिंग पाटर्स अपेक्षित हैं। इन कास्टिंग का उपयोग कुछ अन्य गैर कास्टिंग पाटर्स और संघटकों जैसे ब्लेड आदि के साथ-साथ विंड टरबाइन में होता है जिसके फलस्वरूप बिजली पैदा होती है। इस प्रकार के सभी कास्टिंग्स, चाहे वह उप व्यवस्था के भाग के रूप में अथवा पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स के उद्देश्य से एक उपकरण/संघटक का एक भाग के रूप में कच्चे, तैयार अथवा उप व्यवस्थित रूप में मशीन किया गया हो अथवा न किया गया हो, के लिए कास्टिंग" को वर्तमान जांच में शामिल किया गया है।
- iii. यद्यपि, विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 के अंतर्गत सीमा शुल्क उप शीर्षक संख्या 8503 के अंतर्गत किया गया है जैसी कि घरेलू उद्योग द्वारा सूचना दी गई है और डीजीसीआईएंडएस से भरोसा किए गए प्राप्त आयात संबंधी आंकड़ों में दर्शाया गया है, विचाराधीन उत्पाद का आयात विभिन्न अन्य शीर्षों के अंतर्गत भी किया जाता रहा है। हालांकि, सीमा शुल्क का वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
- iv. विचाराधीन उत्पाद को भी सामूहिक रूप से पवन चालित विद्युत जेनरेटर (डब्ल्यूओईजी) के लिए कास्टिंग के रूप में उल्लेख किया गया है। इन कास्टिंग का मूल कार्य कुछ अन्य गैर कास्टिंग पाटर्स और संघटकों जैसे टावर, ब्लेड आदि के साथ-साथ विंड मिल में उपयोग किए जाने के लिए है जिसके फलस्वरूप बिजली पैदा होती है। विंड मिल में हब, रोटो हब, रोटार नेब, मैन फ्रेम, बेस फ्रेम, मैन फाउंडेशन, नेसेल, नेसेल फ्रेम, नेसेल फाउंडेशन, बियरिंग हाउसिंग, बियरिंग सपोर्ट, होलोसाफ्ट, मैन एक्सल, रोटार शॉफ्ट, रोटार कपलिंग, एक्सल पिन, मैन शॉफ्ट, लेटरल सस्पेंडर, पिच स्टॉप, स्टेटर, जेनरेटिंग कास्टिंग, जेनरेटर्स का पाटर्स, रोटार, टोर्क आर्म सपोर्ट आदि सहित अनेक कास्टिंग पाटर्स अपेक्षित हैं।
- v. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का यह मानना है कि जांच प्रारंभ की सूचना में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद का कार्य क्षेत्र उपयुक्त नहीं है और यह नीचे दिए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र को प्रभावित करता है:

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स, जिसे विंड मिल अथवा विंड टरबाइन के लिए कास्टिंग के रूप में भी जाना जाता है, चाहे वह उप व्यवस्था के भाग के रूप में अथवा पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स के उद्देश्य से एक उपकरण/संघटक का एक भाग के रूप में कच्चे, तैयार अथवा उप व्यवस्थित रूप में मशीन किया गया हो अथवा न किया गया हो, के लिए कास्टिंग" है।"

16. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में नीचे दिए गए अनुसार प्रावधान है:

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

- vii. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि इन वस्तुओं का उत्पादन ग्राहक/क्रेता द्वारा दी गई आवश्यकताओं और विनिर्देशनों के अनुसार किया जाता है और इस कारण से घरेलू उद्योग तथा चीन के आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं को ग्राहकों द्वारा निर्धारित विनिर्देशनों के अनुरूप होना पड़ता है।
- viii. यह उत्पाद प्राथमिक रूप से संख्या/पीस में बेचा जाती है। कीमत किसी विशेष कास्टिंग में शामिल डिजाइन, आकार, वजन एवं प्रसंस्करण पर निर्भर करती है। दो अलग-अलग विंड मिलों के हब जैसे समान

प्रकृति के दो कास्टिंग शामिल प्रक्रिया और संबद्ध भार, डिजाइन, मशीनरी के संबंध में समान नहीं हो सकती है। इस कारण से लागत एवं कीमत के संबंध में इन दोनों बहुत अधिक अंतर हो सकता है।

- ix. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का यह मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु इस नियमावली के संबंध में चीन से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।
- x. यह उत्पाद मॉडल विशिष्ट है जो विंड मिल के उत्पादकों द्वारा अपेक्षित विंड मिल के डिजाइन और क्षमता पर निर्भर करता है। घरेलू उत्पादक और निर्यातक, दोनों भारत में उसी विंड मिल उत्पादकों को आपूर्ति करते हैं।

प्राधिकारी द्वारा निकाली गई पीसीएन:

- xi. याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों में अंतर करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों द्वारा आवेदन के समय पाटन मार्जिन, कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया था।
- xii. जांच प्रारंभ करने के पश्चात तथा विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त करने के बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 04 मार्च, 2016 के पत्र के माध्यम से आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के लिए उत्पाद कोड नंबर (पीसीएन) निकाला है। प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन, कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों में अंतर स्थापित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों (मॉडल मिलान मानदंड अथवा उत्पाद नियंत्रण संख्या प्रणाली (पीसीएन प्रणाली) का प्रस्ताव किया है:

भाग	पीसीएन	स्तर	पीसीएन	उपभोक्ता	पीसीएन	क्षमता		पीसीएन
हब	ए	कास्ट के रूप में	सी	एनर्कोंन	ए	-	-	एनपीयूसी
मैन फ्रेम	बी	मशीनिंग के रूप में	एम	विंड वर्ल्ड	ए	100	299	ए
फ्रेम	बी	असेंबलिंग	ए	गमासा	बी	300	499	बी
नेसेल	बी			गरूडा	सी	500	699	सी
बेस फ्रेम	बी			ग्लोबल विंड	डी	700	899	डी
मैन कैरियर	बी			हनुसेन	ई	900	999	ई
मैन फ्रेम	बी			जेडएफ विंड पावर	ई	1000	1000	एफ
हाउसिंग	सी			इन्नोवेन	एफ	1001	1199	जी
मैन कवर	सी			इनोक्स	जी	1200	1399	एच
साइड बियरिंग	सी			केनरसिस	एच	1400	1599	आई
हॉलो शॉफ्ट	डी			लीटनर	आई	1600	1799	जे
एक्सल पिन	ई			एलएसएमएल	आई	1800	1999	के
मैन एक्सल	ई			प्रकाश इंडस्ट्रीज	के	2000	2000	एल
रोटर कपलिंग	ई			रेजेन	एल	2001	2099	एम
लेटरल सस्पेंडर	एफ			बेसटास	एम	2100	2100	एन
पिच स्टॉप	एफ			विन विंड	एन	2101	2299	ओ
रोटर	जी			विन एनर्जी	पी	2300	2499	पी
स्टेटर	जी			सुजोन	क्यू	2500	2699	क्यू
रोटर कास्टेड	जी			रिपावर	आर	2700	2899	आर
टोर्की आर्म	एच					2900	3099	एस
डाउन होल्डर	ओ					3100	3299	टी
स्लाइडर क्लॉ	ओ					3300 से अधिक		जेड
यॉ बेस बॉटम	ओ							
यूनिबॉडी एबीएस रिंग	ओ							

भाग	पीसीएन	स्तर	पीसीएन	उपभोक्ता	पीसीएन	क्षमता	पीसीएन
ब्लेड एडॉप्टर	ओ						
804 प्लानेट कैरियर	ओ						
प्लानेट कैरियर	ओ						
रिंग बेस	ओ						
यॉ टॉप	ओ						
वेज	ओ						

- xiii. अनिवार्य तथ्यों के अवलोकन और विभिन्न सहकारी निर्यातकों द्वारा निर्यातित पीसीएन तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीसीएन का विश्लेषण करने पर यह नोट किया गया कि दो भाग अर्थात् हब और मेन फ्रेम (भाग क और भाग ख के लिए पीसीएन) की अधिकतम मात्रा थी और शेष भाग, संख्या में बहुत अधिक थे परंतु उनका प्रत्येक का मात्रा में नगण्य योगदान था। प्रत्येक भाग से जुड़ी क्षमताएं भी पुनः समूह में थीं और चार श्रृंखलाओं के बंडल के रूप में थीं क्योंकि भाग-क और भाग ख के लिए भार के आधार पर ज्यादातर कीमत निर्धारित की गई थी। अतः सही तुलना सुकर बनाने के लिए जांच की शुरूआत के दौरान तैयार किया गया पीसीएन का पुनः समूह बनाया गया और निम्नलिखित रूप में उसे युक्तिसंगत किया गया।

पाटर्स	पीसीएन	स्टेज	पीसीएन	क्षमता	पीसीएन
हब	ए	कास्ट के रूप में	सी	-	एनपीयूसी
मेन फ्रेम	बी	मशीनिंग के रूप में	एम	100	999
फ्रेम	बी	असेंबलिंग	ए	1000	1499
नेसेल	बी			1500	1999
बेस फ्रेम	बी			2000	5000
मेन कैरियर	बी				
हाउसिंग	ओ				
मेन कवर	ओ				
साइड बियरिंग	ओ				
हॉलो शॉफ्ट	ओ				
एक्सल पिन	ओ				
मेन एक्सल	ओ				
रोटर कपलिंग	ओ				
लेटरल सस्पेंडर	ओ				
पिच स्टॉप	ओ				
रोटर	ओ				
स्टेटर	ओ				
रोटर कास्टेड	ओ				
टोर्की आर्म	ओ				
डाउन होल्डर	ओ				
स्लाइडर क्लॉ	ओ				
यॉ बेस बॉटम	ओ				
यूनिवॉडी एबीएस रिंग	ओ				
ब्लेड एडॉप्टर	ओ				
804 प्लानेट कैरियर	ओ				

प्लानेट कैरियर	ओ						
रिंग बेस	ओ						
यॉ टॉप	ओ						
वेज	ओ						

17. नव विकसित पीसीएन के बारे में सूचना हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 25 मई, 2017 के माध्यम से दी गई थी। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पीसीएन पद्धति पर विचार करते हुए सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आरंभ की गई थीं। जहां भी लागू हो, उसकी जांच की गई है और उसका समाधान किया गया है।

ग. घरेलू उद्योग का कार्य क्षेत्र एवं आधार

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

18. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. यह जांच मैसर्स एलएंडटी के कहने पर और न कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाली विनिर्माण इकाई के कहने पर शुरू की गई थी।
 - यह जांच मैसर्स एलएंडटी द्वारा दायर की गई एक याचिका के बाद शुरू की गई थी।
 - सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि मैसर्स एलएंडटी ने मूल याचिका दायर की है और बाद में सूचना में संशोधन किया है।
- ii. यह याचिका मैसर्स एलएंडटी द्वारा दायर की जा रही है और याचिकाकर्ता का पता उनके मुंबई कार्यालय के पते के रूप में दर्शाया गया है। मैसर्स ब्रेडकेन ने याचिका दायर नहीं की है और उसे याचिकाकर्ता के रूप में नहीं माना जा सकता है। मैसर्स एलएंडटी द्वारा ब्रेडकेन को कोयंबटूर बिजनेस प्रभाग की बिक्री मात्र मैसर्स ब्रेडकेन को याचिकाकर्ता के रूप में विचार किए जाने की अनुमति नहीं देता है।
- iii. जांच प्रारंभन संबंधी अधिसूचना में मैसर्स एलएंडटी को याचिकाकर्ता तथा घरेलू उद्योग के रूप में भी निर्दिष्ट किया गया था। मैसर्स ब्रेडकेन द्वारा दायर दिनांक 11 मार्च, 2016 के पत्र के अनुसार, एलएंडटी से कोयंबटूर प्रभाव खरीदा गया था। बीएसई लि. के पास दायर पत्र के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि उक्त व्यापार प्रभाग की बिक्री के लिए एक करार 11 नवंबर, 2015 को मैसर्स एलएंडटी एवं मैसर्स ब्रेडकेन के बीच किया गया था। प्रतिस्पर्धा आयोग से अनुमोदन 20 जनवरी, 2015 को प्राप्त किया गया था। हालांकि, मैसर्स एलएंडटी द्वारा ऐसी कोई सूचना पाटनरोधी शुल्क महानिदेशालय के पास दायर नहीं की गई है।
- iv. कोयंबटूर स्थिति विनिर्माण इकाई का कारपोरेट ढांचा और उत्पादन की लागत नया कानूनी प्रतिष्ठान, जो एक ऑस्ट्रेलियाई पैरेट कंपनी वाली कंपनियों के वृहत समूह का एक हिस्सा है, द्वारा प्रभावित नहीं होता है।
- v. मैसर्स ब्रेडकेन को कोयंबटूर स्थित विनिर्माण इकाई की बिक्री वर्तमान जांच शुरू किए जाने के काफी पहले शुरू हो गई, जो 01 फरवरी, 2016 को हुआ।
- vi. बिक्री के विचार-विमर्श का पहला दौर जांच प्रारंभ किए जाने के बहुत पहले 18 मई, 2015 को की गई थी। बिक्री की सभी शर्तों के मामले में करार अंतिम अधिग्रहण के काफी पहले हो गया था। बिक्री करने के लिए करार जांच की अवधि के दौरान ही पूरा हो गया था। मैसर्स एलएंडटी के लिए यह आवश्यक था कि वह इस प्रकार के घटनाक्रम के बारे में प्राधिकारी को तत्काल सूचित करे जो नहीं किया गया था।
- vii. प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (2) के अंतर्गत, मैसर्स ब्रेडकेन ऑपरेशन प्रा. लि. द्वारा दिया गया नोटिस 10 दिसंबर, 2014 को दायर किया गया था। यह नोटिस मैसर्स ब्रेडकेन और मैसर्स एलएंडटी के बीच व्यापार अंतर करार के कार्यान्वयन के अनुसरण में 11.11.2014 को दायर किया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमोदन 20 जनवरी, 2015 को प्राप्त हुआ था।
- viii. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का आदेश यह दर्शाता है कि मैसर्स ब्रेडकेन को मैसर्स एलएंडटी द्वारा कोयंबटूर व्यापार प्रभाग के अंतरण की प्रक्रिया बहुत पहले 11.11.2014 को हुई थी। यह मैसर्स एलएंडटी की जिम्मेदारी थी कि वह इस प्रकार के अंतरण करार के बारे में प्राधिकारी को सूचित करे।

- ix. बीएसई को दी गई सूचना के अनुसार, व्यापार प्रभाग की बिक्री के लिए मैसर्स एलएंडटी एवं मैसर्स ब्रेडकेन के बीच करार वर्तमान जांच प्रारंभ किए जाने के काफी पहले 11 नवंबर, 2015 को संपन्न किया गया था। मैसर्स एलएंडटी लि. के लिए यह आवश्यक था कि वह स्वामित्व में इस प्रकार के परिवर्तन के बारे में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचित करे जो नहीं किया गया था।
- x. जांच प्रारंभन संबंधी अधिसूचना के अनुसार, मैसर्स एलएंडटी घरेलू उद्योग है और वर्तमान जांच में भी वह घरेलू उद्योग बना हुआ है। घरेलू उद्योग की कानूनी स्थिति में परिवर्तन एमटीआर के लिए एक आधार है।
- xi. मैसर्स ब्रेडकेन द्वारा याचिकाकर्ता के रूप में विचार किए जाने के लिए नए आवेदन की आवश्यकता है/दायर किया जा सकता है।
- xii. टीपीएम परामर्शदाता द्वारा मैसर्स एलएंडटी की ओर से और न कि ब्रेडकेन, भारत की ओर से पत्राचार किए गए थे। टीपीएम के परामर्शदाता अब इस मामले में उनका प्रतिनिधित्व तब तक नहीं कर रहे हैं जब तक इस मुद्दे को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा नहीं उठाया गया है। मैसर्स एलएंडटी के पास अभी भी सुविधाएं हैं जो 850 मी. टन की संस्थापित क्षमता के साथ संबद्ध वस्तुओं का निर्माण कर सकती है।
- xiii. मैसर्स ब्रेडकेन ने और न कि मैसर्स एलएंडटी ने इस बिक्री के बारे में पाटनरोधी महानिदेशालय को सूचित किया है। मैसर्स एलएंडटी का यह दायित्व था कि वह पाटनरोधी महानिदेशालय को अधिसूचित करे क्योंकि यह याचिका स्वयं मैसर्स एलएंडटी द्वारा दायर की गई थी।
- xiv. मैसर्स एलएंडटी ने अपने बोर्ड के संकल्प के साथ-साथ करार की प्रति दायर की होगी। इस प्रकार का कोई दस्तावेज दायर नहीं किया गया है। मैसर्स ब्रेडकेन व्यापार प्रभाग के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट दायर की होगी। हालांकि, इस प्रकार का कोई दस्तावेज मैसर्स ब्रेडकेन द्वारा कभी दायर नहीं किया गया था। मैसर्स ब्रेडकेन द्वारा दो पृष्ठ का एक पत्र बिना किसी सहायक दस्तावेजों के दायर किया गया है।
- xv. स्वामित्व में परिवर्तन के साथ, इसकी पूरी संभावना है कि क्षमता एवं विभिन्न अन्य मानदंडों में भी परिवर्तन हुआ है क्योंकि मैसर्स एलएंडटी बहु उत्पाद कंपनी है और मैसर्स ब्रेडकेन इंडिया एक एकल उत्पाद कंपनी है। वर्तमान लागत एवं क्षति संबंधी अन्य मानदंड इस इकाई के वर्तमान मालिक और न कि पूर्व के मालिक के लिए संगत है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

19. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के कार्य क्षेत्र एवं स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. वर्तमान याचिका मैसर्स लार्सेन एवं टुब्रो लि. द्वारा दायर की गई है जिसका उत्पादन भारतीय उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक है। मैसर्स पटेल अलॉयज स्टील्स प्रा. लि. ने इस याचिका का समर्थन किया है। याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तुओं का पात्र उत्पादक है।
- ii. याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा बनता है। इस कारण से, याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग है और नियमावली के अंतर्गत स्थिति की आवश्यकता को पूरा करता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और न ही वे विचाराधीन उत्पाद का कोई आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित हैं।
- iii. दो कंपनियों, मैसर्स एलएंडटी एवं मैसर्स ब्रेडकेन के बीच व्यापार अंतरण करार जांच प्रारंभ करने के बाद हुआ। जांच मैसर्स एलएंडटी द्वारा दायर की गई याचिका के बाद प्रारंभ की गई थी और सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध दस्तावेज दर्शाता है कि मैसर्स एलएंडटी ने मूल याचिका दायर की है तथा बाद में सूचना में संशोधन किया। व्यापार अंतरण करार जांच के प्रारंभ होने के बाद हुआ और स्वामित्व में परिवर्तन की सूचना उचित रूप में स्वयं मैसर्स ब्रेडकेन द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 के पत्र के माध्यम से प्राधिकारी को दी गई।
- iv. व्यापार अंतरण करार में इस बात का उल्लेख है कि इन कानूनी कार्रवाई से उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार और देयताएं मैसर्स ब्रेडकेन के खाते की हैं। जहां तक इस व्यापार प्रभाग का संबंध है, मैसर्स ब्रेडकेन को वे सारे अधिकार और देयताएं दी गई थीं जो मैसर्स एलएंडटी के पास थीं। मैसर्स एलएंडटी इस करार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली कानूनी प्रक्रियाओं को छोड़कर पूर्व की अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के जिम्मेदार बना हुआ है।
- v. जांच प्रारंभ करते समय, मैसर्स एलएंडटी कोयंबटूर व्यापार प्रभाग का मालिक था और व्यापार अंतरण करार इस जांच के प्रारंभ होने के बाद समाप्त हो गया। मैसर्स ब्रेडकेन द्वारा दायर किए गए पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कंपनी की इस जांच को जारी रखने में रुचि है तथा जिसके लिए वे मैसर्स

टीपीएम परामर्शदाता को अधिकृत करते हैं। प्राधिकारी इस जांच परिणाम में स्वामित्व में बदलाव को अधिसूचित कर सकते हैं और स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख कर सकते हैं कि मैसर्स एलएंडटी एवं मैसर्स ब्रेडकेन, दोनों को याचिकाकर्ता के रूप में माना गया है।

- vi. यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी यह चाहते हैं कि मैसर्स एलएंडटी इस घटनाक्रम अथवा इसमें शामिल किसी अन्य पहलुओं की सूचना दें, तब निर्दिष्ट प्राधिकारी मैसर्स एलएंडटी को पत्र लिख सकते हैं क्योंकि मैसर्स एलएंडटी ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचित नहीं किया है और इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- vii. यह याचिका, जिसे एलएंडटी द्वारा 29 जुलाई, 2015 को दायर किया गया था, इस बात का उल्लेख करती है कि याचिकाकर्ता के लिए संपर्क व्यक्ति डॉ. नित्यानन्दन देवराज हैं जो कोयंबटूर में फाउंड्री बिजनेस यूनिट प्रचालन के प्रमुख थे। बाद में, जब दिनांक 11 मार्च, 2016 को, ब्रेडकेन इंडिया ने पाटनरोधी महानिदेशालय को यह सूचित करते हुए, एक पत्र लिखा है कि इस इकाई का अधिग्रहण इसके द्वारा किया गया है, उस पर डॉ. नित्यानन्दन देवराज द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जो अब ब्रेडकेन इंडिया के अध्यक्ष एवं निदेशक हैं। इस प्रकार से, यह याचिका जिसे 29 जुलाई, 2015 को दायर किया गया था, पर वास्तव में व्यापार इकाई द्वारा हस्ताक्षर किया गया था जिसे बेच दिया गया था और यह पत्र पाटनरोधी महानिदेशालय को इस बिक्री, जिसे व्यापार इकाई द्वारा किया गया था, के बारे में सूचित करते हुए पत्र भेजा गया था।
- viii. मैसर्स एलएंडटी एवं ब्रेडकेन, दोनों को याचिकाकर्ता के रूप में माना जाना चाहिए और मैसर्स ब्रेडकेन ने मैसर्स एलएंडटी को याचिकाकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित नहीं किया है। मैसर्स ब्रेडकेन ने वर्तमान जांच एवं शुल्क लगाए जाने के संबंध में प्राधिकारी के समक्ष अपने आपको तृतीय पक्ष के रूप में जोड़ा है।
- ix. मैसर्स ब्रेडकेन ने वर्तमान याचिका के संबंध में सभी संगत आंकड़े उपलब्ध कराए हैं तथा सभी तथ्यों को स्पष्ट किया है जिसके लिए जांच की अवधि अप्रैल, 2014 से सितंबर, 2015 है।
- x. मैसर्स ब्रेडकेन ने व्यापार का अधिग्रहण करने के संबंध में सभी दस्तावेज एवं प्रमाण उपलब्ध कराए हैं।
- xi. प्रचालन ढांचा, उत्पादन सुविधा एवं व्यापार इकाई में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा, संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री आदि की तुलना में व्यापार प्रभाग के विभिन्न क्रियाकलापों की प्रकृति अधिग्रहण के पूर्व की स्थिति की तुलना में एक जैसी है।
- xii. यदि व्यापार प्रभाग कारपोरेट कानूनी प्रतिष्ठान का हिस्सा था, तब यह स्वाभाविक है कि यह याचिका मैसर्स एलएंडटी के रूप में विनिर्माण प्रचालनों द्वारा हस्ताक्षर की गई थी। हालांकि, समग्र उत्पादन एवं उत्पाद आंकड़े विनिर्माण स्थल से संबंधित हैं। इसके अलावा, मैसर्स एलएंडटी ने इस पत्र को आज की तारीख तक वापस नहीं लिया है।
- xiii. याचिकाकर्ता इस करार की गोपनीयता की धारा से बंधे हुए थे। इसके अलावा, चालू संधि का यह अभिप्राय नहीं है कि यह करार पूर्ण था। वीएसई एवं सीसीआई को सूचित करना प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं एवं जरूरी बातों में से एक है ताकि इस करार को वास्तविक रूप दिया जा सके जो इस कानून के अंतर्गत अपेक्षा है। हितबद्ध पक्षकारों को किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा की जा रही खरीद बिक्री की आवश्यकताओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इन प्रक्रियाओं का पालन मैसर्स ब्रेडकेन एवं मैसर्स एलएंडटी द्वारा सही मायने में पालन किया जाना चाहिए।
- xiv. करार के पूरा होने के तुरंत बाद, मैसर्स ब्रेडकेन ने प्राधिकारी को व्यापार अंतरण करार के बारे में सूचित किया तथा दिनांक 11 मार्च, 2016 के पत्र के माध्यम से टीपीएम परामर्शदाता को अधिकार दिया। इसके अलावा, टीपीएम परामर्शदाताओं द्वारा दी गई सभी सूचना मैसर्स ब्रेडकेन और न कि मैसर्स एलएंडटी की ओर से दी गई थी। टीपीएम को मैसर्स ब्रेडकेन से दिनांक 11 मार्च, 2016 के पत्र के माध्यम से अधिकार प्राप्त हुआ, आगे टीपीएम द्वारा दायर की गई सभी याचिकाएं मैसर्स ब्रेडकेन और न कि एलएंडटी की ओर से थीं।
- xv. मैसर्स एलएंडटी से मैसर्स ब्रेडकेन को कोयंबटूर के व्यापार प्रभाग की बिक्री की प्रक्रिया एवं संधि काफी पहले शुरू हो गई होगी, परंतु यह करार 04 मार्च, 2016 को अर्थात् जांच प्रारंभ किए जाने के पश्चात् पूरा किया गया था। करार के पक्षकार इस करार की गोपनीयता संबंधी धारा से बंधे हुए थे। मैसर्स एलएंडटी तब तक इस घटनाक्रम के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा पक्षकारों को सूचित नहीं कर सकता था जब तक कि यह हस्ताक्षर के रूप में वास्तविक रूप नहीं ले लेता।

- xvi. स्थिति का निर्धारण याचिका के संबंध में और न कि याचिकाकर्ता के रूप में किया जाना अपेक्षित है। स्थिति का निर्धारण उत्पादन के आधार पर किया जाता है और उत्पादक केवल उसी सीमा तक संबंधित है कि उत्पादन किसी कानूनी प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है। वर्तमान याचिका के लिए अद्यतित आंकड़ों को मैसर्स ब्रेडकेन इंडिया प्रा. लि. द्वारा दायर किया गया है।
- xvii. वर्तमान व्यापार अंतरण कीमत में अचानक तीव्र गिरावट के कारण होने वाली बिक्री के रूप में है तथा इस इकाई का अंतरण चालू प्रतिष्ठान के आधार पर किया गया था। वित्तीय कार्य निष्पादन और क्षति के संबंध में सूचना पर व्यापार की किसी बिक्री अथवा खरीद का प्रभाव नहीं पड़ता है। बिक्री के समय, परिसंपत्तियों का बुक मूल्य एवं नियोजित पूंजी पर कोई अन्य राजस्व भार नहीं था। इस प्रकार से, परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में कोई अचानक गिरावट नहीं हुई थी। इसके बदले में, परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हुई है और इस कारण से लाभ के अपेक्षाकृत अधिक स्तर की आवश्यकता है। चूंकि, परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में कोई तीव्र गिरावट नहीं आई है, अतः नियोजित पूंजी को स्वामित्व में परिवर्तन के कारण कम किए जाने की आवश्यकता है। वास्तव में निर्दिष्ट प्राधिकारी को अब उस मूल्यांकन के आधार पर घरेलू उद्योग को निवेश पर लाभ का निर्धारण करना चाहिए जिस पर बिक्री खरीद की लेन-देन के लिए विचार किया गया है।
- xviii. मैसर्स एलएंडटी के पास अभी भी कांसबहल, ओडिशा में संबद्ध वस्तुओं का एक अन्य संयंत्र है जिसने वर्ष 2012-13 में उत्पादन स्थगित कर दिया।
- xix. आज की तारीख तक, एमटीआर इस जांच परिणाम को शुरू किए जाने के बाद ही प्राधिकारी द्वारा की गई। यह तथ्य कि घरेलू उत्पादक की कानूनी स्थिति में परिवर्तन के लिए एमटीआर की आवश्यकता होती है, वास्तव में दर्शाता है कि लगाए गए एवं लागू शुल्क को वापस नहीं लिया जाएगा बल्कि उसकी समीक्षा की जाएगी। वर्तमान मामले में जांच अभी भी जारी है और शुल्क अभी लगाया जाना है। अतः एमटीआर करने का प्रश्न ही नहीं उठता। घरेलू उत्पादक की कानूनी स्थिति में परिवर्तन एमटीआर की आवश्यकता को सिद्ध नहीं करता है क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या घरेलू उद्योग की कानूनी स्थिति में परिवर्तन मात्र पाटनरोधी शुल्क लगाने अथवा उसे जारी रखने के लिए संगत पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन अथवा किसी अन्य मानदंडों में पर्याप्त बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है।
- xx. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता तथा चीन की कंपनियों के परिसरों का मौके पर सत्यापन किया है। यदि याचिका में आधार की कमी है तब हितबद्ध पक्षकार सत्यापन करने नहीं दिया होता और नहीं देना चाहिए था तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी को सत्यापन नहीं करना चाहिए था।
- xxi. मैसर्स एलएंडटी ने अभी भी वर्तमान याचिका जारी रखी, अपने आप में यह दर्शाता है कि व्यापार की बिक्री के बावजूद, कंपनी ने इस याचिका को जारी रखा। कानून के तहत, यह याचिका घरेलू उद्योग की ओर से दायर की जा सकती है। उस मामले में, यह माना जाना चाहिए कि मैसर्स एलएंडटी ने घरेलू उद्योग की ओर से याचिका जारी रखी।
- xxii. किसी कंपनी, जिसने व्यापार प्रभाग को बेच दिया है, के संबंध में इस प्रकार के दस्तावेजों की कोई संगतता नहीं है। नए प्रतिष्ठान की स्थिति की जांच किए जाने की आवश्यकता है और न कि प्रतिष्ठान, जिसने व्यापार बेचा है, उसकी स्थिति की।
- xxiii. यह तर्क संभावनाओं और अनुमानों पर आधारित है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रिकार्ड में वास्तविक सूचना है और उस पर विचार किया जा सकता है।
- xxiv. समग्र कंपनी की बिक्री और विचाराधीन उत्पाद के प्रचालनों की बिक्री में कानून के अंतर्गत अंतर नहीं किया जा सकता है।
- xxv. पक्षकार अनेक महीनों तक इस मुद्दे पर मौन नहीं रह सके। यह दर्शाने के लिए कोई न्यायपरक तर्क नहीं दिया गया है कि वर्तमान याचिका कायम रखने योग्य नहीं है।
- xxvi. वार्षिक रिपोर्ट केवल इसके बारे में उल्लेख करती है कि मैसर्स ब्रेडकेन भारत में फाउंड्री का अधिग्रहण करने की योजना बना रहा है। जब तक बिक्री पूरी नहीं हो जाती है तब तक पक्षकार इस करार की गोपनीयता संबंधी धारा से बंधे हुए हैं।
- xxvii. कंपनी के अपने कोयंबटूर स्थल के लिए लेखा परीक्षित लेखा है जहां विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया जाता है और वह इस याचिका में समग्र आंकड़ों/सूचना का आधार बन गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

20. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:
“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।
21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह याचिका मैसर्स लार्सेन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। बाद में, मैसर्स पटेल अलॉयज द्वारा समर्थन पत्र की एक प्रति क्षमता, उत्पादन और बिक्री के संबंध में सूचना के साथ-साथ प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन का एक बड़ा अनुपात होता है। याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का न तो आयात किया है और न ही यह संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के या तो आयातकों अथवा निर्यातकों से संबंधित है।
22. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति, तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने कथित पाटन, यदि कोई हो, की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो अगर लगाया जाए तो घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की सिफारिश करने के लिए तथा कथित पाटन एवं घरेलू उद्योग को होने वाली परिणामी क्षति की जांच करने के लिए दिनांक 01 फरवरी, 2016 के अधिसूचना संख्या 14/28/2013-डीजीएडी के माध्यम से वर्तमान जांच शुरू की।
23. 04 मार्च, 2016 को, मैसर्स लार्सेन एंड टुब्रो लिमिटेड ने एक व्यापार अंतरण करार के द्वारा विचाराधीन उत्पाद से संबंधित व्यापार मैसर्स ब्रेडकेन इंडिया प्रा. लि. (जिसे एतदपश्चात् “ब्रेडकेन” कहा गया है) को बेच दिया। कोयंबटूर स्थित कंपनी के व्यापार प्रभाग ने 04 मार्च, 2016 से मैसर्स ब्रेडकेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर प्रचालन जारी रखा है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को दिनांक 11 मार्च, 2016 के अपने पत्र के माध्यम से उसके बारे में मैसर्स ब्रेडकेन द्वारा सूचित किया गया था। मैसर्स ब्रेडकेन ने विशिष्ट रूप से उल्लेख किया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह जांच जारी रखनी चाहिए तथा विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए। उक्त पत्र में, टीपीएम परामर्शदाता को पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के समक्ष वर्तमान जांच में उन्हें प्रस्तुत करने का अधिकार देने के अलावा, यह भी सूचित किया गया था कि यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी को मैसर्स ब्रेडकेन द्वारा विचाराधीन उत्पाद के व्यापार एवं व्यापार प्रभाग का अधिग्रहण करने के संबंध में कोई सूचना अपेक्षित हो, तो वे सहयोग करने के लिए इच्छुक हैं।
24. उक्त सूचित घटना की जानकारी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसके तत्काल बाद सार्वजनिक फाइल में इस पत्र का अगोपनीय पाठ रखकर हितबद्ध पक्षकारों को दी गई थी। जब याचिकाकर्ता ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को 11 मार्च, 2016 को उक्त घटनाक्रम के बारे में सूचित भी किया, तब भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया जो इस तथ्य को सिद्ध कर सके कि याचिकाकर्ता के पास अब इस वर्तमान याचिका का समर्थन करने के लिए कोई आधार नहीं है।
25. मैसर्स एलएंडटी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक याचिका दायर की है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच प्रारंभ करके एलएंडटी को कानूनी अधिकार प्रदान किया क्योंकि इस जांच प्रारंभन के फलस्वरूप मैसर्स एलएंडटी के बहुमूल्य अधिकार मिल गया जिसे मैसर्स ब्रेडकेन को व्यापार अंतरण करार के अनुसरण में अंतरित किया गया है। मैसर्स एलएंडटी इस व्यापार प्रभाग से संबंधित प्रक्रिया को छोड़कर देश में तथा विश्व भर में मैसर्स एलएंडटी पर चल रही सभी अन्य कानूनी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार बना हुआ है। मैसर्स एलएंडटी ने वर्तमान याचिका को वापस लेने के बारे में कोई सूचना दायर नहीं की है। यदि उपयुक्त समझा गया तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपयुक्त स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए मैसर्स एलएंडटी को पत्र लिख सकता है।
26. व्यापार अंतरण करार के मामले में, इस व्यापार प्रभाग के संबंध में एलएंडटी के पास सभी अधिकारों को मैसर्स ब्रेडकेन के पास अंतरित कर दिया गया है। जहां तक कोयंबटूर स्थित व्यापार प्रभाग का संबंध है, मैसर्स ब्रेडकेन को विशेष रूप से मैसर्स एलएंडटी के पास उपलब्ध सभी अधिकार दे दिए गए हैं। साथ ही, जहां तक इस व्यापार प्रभाग का संबंध है, मैसर्स ब्रेडकेन ने सभी देयताएं भी प्राप्त कर ली हैं जो पूर्व में मैसर्स एलएंडटी के पास थीं और एलएंडटी के पास कोयंबटूर इकाई रह जाने के अलावा किसी भी प्रभाग के लिए एलएंडटी के सभी अन्य अधिकार और देयताएं भी उसे प्राप्त हो गई हैं।

27. दिनांक 04 अप्रैल, 2016 के पत्र के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चुनी गई जांच की अवधि के लिए अद्यतित आंकड़ों के अगोपनीय पाठ की प्रतियां दायर की थीं क्योंकि वर्तमान याचिका मैसर्स ब्रेडकेन इंडिया प्राइवेट लि. द्वारा दायर की गई है। इस प्रकार से, मैसर्स ब्रेडकेन इंडिया ने न केवल अद्यतित आंकड़े उपलब्ध कराए बल्कि विगत याचिका के संबंध में तथ्यों को भी स्पष्ट किया। इसके अलावा, वर्तमान मामले में जांच की अवधि अप्रैल, 2014 से सितंबर, 2015 है, यह एक अवधि है जिसके दौरान स्वामित्व मैसर्स एलएंडटी के पास था तथा जांच की इस अवधि के लिए आंकड़े मैसर्स ब्रेडकेन इंडिया द्वारा उपलब्ध कराये गये थे।
28. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को दिनांक 09 मई, 2016 के ई-मेल के द्वारा "आगे की जांच के लिए मैसर्स लार्सेन एंड टुब्रो लि. से सभी सहायक दस्तावेजों तथा व्यापार प्रभाग का अधिग्रहण करने संबंधी प्रमाण तत्काल" दायर करने के लिए कहा और याचिकाकर्ता द्वारा उसे दिनांक 17 मई, 2016 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।
29. कोयंबटूर इकाई का अधिग्रहण चल रही प्रतिष्ठान के आधार पर रूप में किया गया था। इस संयोजन को सीसीआई अधिनियम की धारा 5 के संबंध में संयोजन पंजीकरण संख्या सी-2014/12/229 के रूप में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास पंजीकृत किया गया है। परिसंपत्तियों, उत्पादन, क्षमता अथवा किसी अन्य मानदंडों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केवल स्वामित्व बदलकर मैसर्स एलएंडटी से मैसर्स ब्रेडकेन के पास चला गया है।
30. इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे गये दिनांक 09 सितंबर, 2016 के मेल के उत्तर में, अन्य सूचना के साथ-साथ मैसर्स ब्रेडकेन की लागत संबंधी सूचना दिनांक 12 सितंबर, 2016 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
31. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता एवं चीन की कंपनियों के परिसरों में मौके पर सत्यापन किया था। पाटनरोधी महानिदेशालय द्वारा स्थिति के मुद्दे पर चर्चा की गई थी और सत्यापन के समय इन अधिकारियों द्वारा जिस सीमा तक उपयुक्त पाया गया, उस सीमा तक स्पष्टीकरण मांगा गया।
32. पूर्व की पाटनरोधी जांच के समय, क्षति की अवधि 01 अक्तूबर, 2012 से 31 दिसंबर, 2013 थी। प्राधिकारी ने दो संयंत्रों के लिए सूचना अलग करने का निदेश याचिकाकर्ता को दिया (जिसे सूचना के सत्यापन के लिए सामान्य प्रक्रिया है)। उसके बाद, अंतिम जांच परिणाम में, प्राधिकारी ने केवल कोयंबटूर व्यापार प्रभाग से संबंधित सूचना को लिया है और कांसबहल संयंत्र के संबंध में दी गई सूचना को छोड़ दिया है। जब मैसर्स एलएंडटी पूर्व के मामले में भी याचिकाकर्ता था, तब भी प्राधिकारी ने कांसबहल से संबंधित सूचना को छोड़ दिया है। मैसर्स एलएंडटी ने अपने कांसबहल संयंत्र के संबंध में प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए अपनी अनिच्छा का उसमें उल्लेख करते हुए प्राधिकारी को कोई सूचना नहीं भेजी है जो इस याचिका का एक हिस्सा बन गया था। वास्तव में, मैसर्स एलएंडटी ने आज की तारीख तक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अपने अनुरोध को वापस भी नहीं लिया है।
33. अतः प्राधिकारी का यह मानना है कि आवेदक मैसर्स एलएंडटी एवं मैसर्स ब्रेडकेन, दोनों वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता हैं। मैसर्स एलएंडटी ने मैसर्स ब्रेडकेन को एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में कास्टिंग उत्पादक इकाई बेची है जिसके अंतर्गत परिसंपत्तियों की कोई बाधा नहीं हुई है। मैसर्स ब्रेडकेन ने प्राधिकारी से इस जांच को जारी रखने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने तथा मैसर्स एलएंडटी को प्रतिस्थापित न करने के उद्देश्य से अनुरोध किया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि यूनिट की बिक्री और खरीद के संबंध में सूचना आदर्श रूप से यथाशीघ्र शुरू की जानी चाहिए थी। परंतु यह चूक जांच की कार्रवाई को निरस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

विवरण	यूओएम	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई (ए)
याचिकाकर्ता					
एलएंडटी (सीएमयू + केबीएल)	मी. टन	9,923	5,574	7,434	12,157
सूचकांक		100	56	75	123
समर्थक					
पटेल अलॉय स्टील (पी) लि.	मी. टन	4,268	176	201	121
सूचकांक		100	4	5	3
याचिकाकर्ता + समर्थक	मी. टन	14,191	5,750	7,635	12,278
सूचकांक		100	41	54	87

विवरण	यूओएम	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई (ए)
अन्य उत्पादक	मी. टन	3,100	2,900	3,000	3,200
सूचकांक		100	94	97	103
भारतीय उत्पादन	मी. टन	17,291	8,650	10,635	15,478
सूचकांक		100	50	62	90
हिस्सा	यूओएम	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई (ए)
याचिकाकर्ता					
एलएंडटी	%	57%	64%	70%	79%
सूचकांक		100	112	122	137
समर्थक					
पटेल अलॉय स्टील (पी) लि.	%	25%	2%	2%	1%
सूचकांक		100	8	8	3
याचिकाकर्ता + समर्थक	%	82%	66%	72%	79%
सूचकांक		100	81	87	97
अन्य उत्पादक	%	18%	34%	28%	21%
सूचकांक		100	187	157	115
भारतीय उत्पादन	%	100%	100%	100%	100%

34. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के प्रमुख भाग पर नियंत्रण रखता है और इस जांच के प्रयोजनार्थ, आवेदक नियम 5(3) की शर्तों में स्थायी आवश्यकता को पूरा करता है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) की शर्तों में घरेलू उद्योग है।

घ. गोपनीयता

निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

35. निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- याचिका में पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 और 7 के तहत अपेक्षित पर्याप्तता और परिशुद्धता की कमी है। घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया डाटा अपर्याप्त और असंगत है। घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है।
 - जांच की अवधि के दौरान डीजीसीआईएंडएस द्वारा दर्ज किए गए अनुसार, सौदा दर सौदा आधार पर आयात डाटा की सॉफ्ट कॉपी सैंडिस्क इंटरनेशनल लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और ओआरएस के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
 - एनसीवी में प्रदत्त डाटा गोपनीय हैं और एडीडी के नियम 7 के विरुद्ध हैं। सूचना के अगोपनीय रूपांतर द्वारा पूरी जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों को उनके स्वयं की रक्षा के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देनी चाहिए।
 - घरेलू उद्योग खंड VI अर्थात् लागत डाटा पर मौन है।
 - ढलाई के लिए सारी यूटिलिटीयों जैसे विद्युत, भाप या कोई अन्य यूटिलिटीयों की आवश्यकता होती है और याचिकाकर्ता ने ऐसी सूचना जैसे कार्यशील पूंजी, सावधि ऋणों में व्याज, अतिदेय और या चक्रवृद्धि व्याज, मूल्य ह्रास, विभिन्न आय विवरण और डब्ल्यूआईपी के विवरण, वापिसी लाभ, पूंजी इक्विटी पर वांछित वापिसी और साथ ही उसके समर्थन में औचित्य को दर्शाने वाला विवरण उपलब्ध नहीं कराया है।

- vi. सकल निर्धारित परिसंपत्तियां एडीडी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार नहीं हैं और गोपनीय रखी गई हैं।
- vii. क्रय नीति में प्रमुख सामग्रियों के लिए दीर्घावधिक संविदा शामिल है।
- viii. विक्रय नीति थोक प्रयोक्ताओं को विपणन संवितरण सरणियों, कमीशन/छूट नीति, क्रेडिट टर्म आदि विक्रय नीतियों का संकेत देती है।
- ix. लेखाकरण और मालसूची भंडार, डब्ल्यूआईपी मूल्यांकन को एकत्र करता है।
- x. गुणवत्ता नियंत्रण कार्यप्रक्रिया और परीक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।
- xi. आईबीआईएस आयात डाटा से प्राप्त किए गए प्रमुख प्रयोक्ताओं के आयात डाटा का गोपनीय रूप में दावा क्यों किया गया है जबकि यह गलत और छलयोजित डाटा है। प्राधिकारी याचिकाकर्ता को इस सूचना को प्रकट करने का निर्देश देंगे।
- xii. अलकाली मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2006 (194) ईएलटी 161 और रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2006 (202) ईएलटी 23 (एससी) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। बिक्री की मात्रा संबंधी डाटा, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन के सार और कीमत कटौती में दावा की गई गोपनीयता को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- xiii. प्रयोक्ता वार आयात डाटा स्वरूप से गोपनीय नहीं है।

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

36. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किया गया कच्ची सामग्री से संबंधित आयात डाटा गोपनीय सूचना है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने पहले यह विश्वास कराने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को भ्रम में डाला कि प्रविष्टि-वार डाटा का बिल डीजीसीआईएंडएस द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है और कोई भी पक्ष आरटीआई के तहत भी इस सूचना को प्राप्त कर सकता है। हालांकि, डीजीसीआईएंडएस ने प्रविष्टि-वार आयात डाटा का बिल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया है और 8 अंकीय स्तर पर माह-वार देश-वार आयात डाटा उपलब्ध कराया है। तथापि, इसे प्रविष्टि-वार डाटा के बिल के रूप में अनुमानित नहीं किया जा सकता, जिसे डीजीएडी द्वारा मुख्य रूप से सौदा-वार डाटा समझा गया है। माह-वार देश-वार डाटा और प्रविष्टि-वार डाटा का बिल पृथक सूचना है और एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है। यह मुद्दा पहले से ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसने उसके बाद से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन आदेश दिए हैं। स्थगन आदेश के होते हुए भी, याचिकाकर्ता ने पहले ही प्रविष्टि-वार आयात डाटा केबिल उपलब्ध कराए हैं।
- ii. घरेलू उद्योग ने गोपनीय के रूप में केवल ऐसी सूचना का दावा किया है, जिसकी गोपनीयता नियम 7 के तहत उपलब्ध कराई गई है। नियम में व्यवस्था की गई है कि सूचना, जो स्वरूप में गोपनीय है या जिसे गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराया गया है, को प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना गया है। इस प्रकार, इस आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई सूचना उपलब्ध कराई जाती है कि यह गोपनीय है तो प्राधिकारी द्वारा उसे गोपनीय ही रखना होगा।
- iii. घरेलू उद्योग ने किसी ऐसी सूचना का गोपनीय रूप में दावा नहीं किया है जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।
- iv. प्रयोक्ता-वार आयात डाटा स्वरूप में गोपनीय है। प्राधिकारी को कोई गलत डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है और प्राधिकारी को वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों से सूचना मांग सकते हैं और उसका सत्यापन भी कर सकते हैं।
- v. वर्तमान मामले में, उत्तर देने वाले निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का आश्रय लिया है और ऐसी सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।
- vi. हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग से किसी सूचना को बिल्कुल छिपा नहीं सकते। यदि कोई सूचना पूरी तरह से गोपनीय भी है तो भी हितबद्ध पक्षकार इसका पर्याप्त एनसीवी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है और न कि खाली पृष्ठ, ये घरेलू उद्योग को सूचना के सार को उचित रूप से समझने की अनुमति देती है और अपनी रक्षा का पूरा अधिकार देती है।

- vii. निर्दिष्ट प्राधिकारी को किसी पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना को यांत्रिक रूप से केवल इस कारण गोपनीय नहीं मानना चाहिए क्योंकि पक्षकार की इच्छा इसे गोपनीय रखने की है। नियमावली किसी पक्षकार द्वारा गोपनीयता के लिए किए गए अनुरोध पर विचार करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान करती है और यदि वह संतुष्ट है कि इसकी जरूरत नहीं है अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने, अथवा सामान्यीकरण या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटीकरण हेतु प्राधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है तो वह ऐसी
- viii. सूचना की अवहेलना कर सकता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

37. जानकारी की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:

गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक हैं अथवा सूचना प्रदाता या सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसका सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना की अवज्ञा कर सकता है।

38. गोपनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है और तदनुसार, संबोधित किया गया है। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है तथा ऐसी सूचना को गोपनीय समझा गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए हैं। प्राधिकारी ने टिप्पणी की है कि ऐसी किसी सूचना को, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, गोपनीय नहीं माना जा सकता।

ड. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोध और उनकी जांच

निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

39. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- वर्तमान जांच बहुत अधिक प्रकार्यात्मक विसंगतियों द्वारा प्रभावित है। मूल याचिका का अभाव है।
- याचिकाकर्ता ने उल्लेखनीय रूप से जांच को बाधित किया है और उसे परस्पर विरोधी डाटा सम्मिलित करने वाले चार अलग-अलग सेटों को दायर करने के कारण असहयोगी समझा जाना चाहिए। यूएस – हॉट रोलड स्टील और इजिप्ट रिबार्थ पैनल और अपीलीय निकाय ने निर्णय दिया है कि किसी सहयोगी पक्षकार को जांच के दौरान सद्भाव से कार्य करना चाहिए।
- याचिकाकर्ता ने पस्पर विरोधी सूचना को शामिल करने वाले डाटा के चार अलग-अलग सेट प्रस्तुत किए हैं और डाटा में विसंगति के लिए कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया है, उन्होंने दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को दो पत्रों पर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने से पहले तीन महीने तक प्रतीक्षा की और सार्वजनिक सुनवाई की पूर्व संध्या को ही स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया। 12 सितंबर, 2016 को डाटा का नया सेट प्रस्तुत किया।

- iv. आयात डाटा की प्रमाणिकता और शुद्धता के बारे में गंभीर संदेह है क्योंकि सीवीडी और एडीडी जांच में आयात मात्रा और मूल्य के अलग-अलग आंकड़ों का दावा किया गया है।
- v. डाटा में परिवर्तनों के आवर्तन से याचिकाकर्ता के दावों और आरोपों की विश्वसनीयता और शुद्धता पर प्रश्न उठते हैं। गुआटेमाला मामला (डब्ल्यूटी/डीएस 60/एवी/आर) – साक्ष्य की पर्याप्तता इसकी परिशुद्धता और पर्याप्तता पर आश्रित नहीं होगी और पर्याप्तता एवं परिशुद्धता का निर्णय करना प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर है - इसकी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अवहेलना की जा सकती है, किंतु उसके लिए साक्ष्यों का पर्याप्त होना आवश्यक है। जांच शुरूआत को रद्द किया जा सकता है और संशोधित जांच की अवधि के लिए नई जांच शुरूआत और डाटा की जांच की जानी चाहिए, यदि प्राधिकारी डाटा से संतुष्ट हैं, जैसा नियम 5 में अपेक्षा की गई है।
- vi. यदि पाटनरोधी शुल्क एक निर्धारित राशि के रूप में लगाया जाना था तो शुल्क की इस राशि को संबद्ध वस्तुओं के विस्तृत दायरे के संबंध में ध्यान में रखना चाहिए और प्रत्येक प्रकार की कास्टिंग के लिए अपनाया जाना चाहिए।
- vii. क्षति के किसी निर्धारण में सीमित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारकों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कास्टिंग के आयातों पर लागू किया गया अवशिष्ट सीवीडी सब्सिडी मार्जिन के समकक्ष था और क्षति मार्जिन उच्च था। घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति पर प्रभाव को दर्शाने के लिए सीवीडी हेतु उचित समय की प्रतीक्षा करनी है और प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करने के लिए फोरम शॉपिंग, अशुद्ध और भ्रामक डाटा पर क्षति का दावा करने का आश्रय नहीं लेना है।
- viii. सिर्फ मैसर्स पटेल अलॉय स्टील (प्रा.) लि. का समर्थन पत्र पर्याप्त नहीं है – पटेल अलॉय को उनके आर्थिक मानदंडों को दर्शाते हुए उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है; केवल समर्थन पत्र पर्याप्त नहीं है।
- ix. आईबीआईएस आयात डाटा से लिए गए प्रमुख प्रयोक्ताओं के आयात डाटा को क्यों गोपनीय मानकर दावा किया गया है यदि यह गलत और छलयोजित नहीं है।
- x. याचिका इस बारे में मौन है कि कैसे संख्या/पीसों को एमटी में बदल दिया गया है।
- xi. जांच की अवधि आयातों पर सीवीडी के प्रभाव और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की कीमत को ध्यान में नहीं रखा गया है। जांच की अवधि को यह जांच करने के लिए चुनना चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही सामग्री क्षति का लेवी युक्त सीवीडी द्वारा उल्लेख किया गया है। किसी एडीडी पर लेवी लगाते समय सीवीडी को दो बार नहीं गिना जाना चाहिए, जैसा कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत अपेक्षित है, निर्यात की सीमा तक सब्सिडी को यह सुनिश्चित करने के लिए एडीडी लेवी में सम्मिलित किया जाना चाहिए कि कोई अनुचित दोहरी लेवी नहीं है।
- xii. जांच की अवधि कोयंबटूर की बिक्री को ध्यान में रखने में असफल रही है, जो सुझाव देती है कि याचिकाकर्ता को आयातों के कारण क्षति नहीं हो सकती।
- xiii. सीवीडी को लागू करने के बाद स्थिति और लाभप्रदता में सुधार हुआ है जिसके कारण यूनिट के मूल्यांकन में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, मैसर्स ब्रेडकेन की बिक्री को एक लाभप्रद विकल्प बनाया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को लाभप्रदता और कंपनी के वृद्धि पूर्वानुमानों के सही आकलन के लिए परियोजना रिपोर्ट की मांग करनी चाहिए।
- xiv. हांगकांग को शामिल न करना और जांच शुरूआत के बाद जांच की अवधि में परिवर्तन के कारण वर्तमान जांच शुरूआत एडीडी नियमावली के विरुद्ध है।
- xv. याचिकाकर्ता द्वारा दायर अद्यतन डाटा में जांच की अवधि के दौरान हांगकांग से आने वाले आयात शामिल हैं जो 3 प्रतिशत से अधिक हैं, जो न्यूनतम मार्जिन से अधिक हैं। हांगकांग से आयातों की कीमत चीन से आने वाले माल की कीमत 2 प्रतिशत – 3 प्रतिशत है। चीन के लिए कीमत में कटौती 20-30 प्रतिशत है, तब ऐसी स्थिति में हांगकांग के लिए कीमत कटौती कहीं अधिक कम होगी। हांगकांग न केवल न्यूनतम कीमत से अधिक है बल्कि संबद्ध आयातों की तुलना में निम्नतर कीमत पर भी है। हांगकांग के बहिष्करण के कारण आंतरिक संबंधों में एक भी उल्लंघन नहीं हुआ है।
- xvi. घरेलू उद्योग को हांगकांग से स्थानांतरण के प्रमाण उपलब्ध कराने चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी को हांगकांग से निर्यात पर सूचना मांगनी चाहिए।

- xvii. 29 सितंबर, 2015 को दायर याचिका 1 फरवरी, 2016 को जारी की गई जांच आरंभ अधिसूचना के संदर्भ में है। प्रतिवादी इस बात का कारण पता लगाने में असफल हैं कि कैसे एक दस्तावेज, जो जांच आरंभ अधिसूचना को जारी किए जाने से लगभग 5 महीने पहले दायर किया गया था, जांच आरंभ अधिसूचना का अत्यधिक यथार्थता से उल्लेख कर सकता है। तथापि, मैसर्स एलएंडटी के कानूनी प्रतिनिधि ने निवेदन किया है कि यह एक गौण त्रुटि थी और यह कि डीजीएडी में अनुसरण की जा रही पद्धति के अनुसार, जांच आरंभ अधिसूचना को जारी किए जाने के पश्चात याचिका का अगोपनीय रूपांतर दायर किए जाने की आवश्यकता होती है। प्राधिकारी के समक्ष किए गए ऐसे गैर-जिम्मेदार बयान वर्तमान जांच के प्रति याचिकाकर्ता की विचारधारा को दर्शाते हैं और वर्तमान जांच की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।
- xviii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि याचिका में दो रूपांतरण प्रस्तुत किए जाने हैं, एक जांच आरंभ करने के लिए आवेदन करते समय और अन्य अर्थात् जांच आरंभन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात अगोपनीय रूपांतरण। यह पुष्टि करने के लिए यदि कोई विशिष्ट प्रावधान है कि मैसर्स एलएंडटी ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान क्या प्रस्तुत किया है, तब उन्हें इससे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अवगत कराना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा अनुसरण की गई कार्य प्रक्रिया गैर-कानूनी है और माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की यह कार्रवाई वर्तमान जांच के लिए न केवल घातक है बल्कि अनैतिक भी है और एडीडी जांच के आयोजन के मामले में अनुसरण की जा रही वर्तमान कार्यविधि की गहन पुनरीक्षा की मांग करती है।

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

40. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- पाटनरोधी शुल्क लागू करने से संबंधित याचिका बहुत पहले वर्ष 2013 में दायर की गई थी। एनसीवी याचिका में शब्द "अद्यतन याचिका" उल्लेख करने का कारण वर्ष 2013 के बाद से याचिका को बार-बार दायर करना है।
- सूचना और साक्ष्य की गुणवत्ता और मात्रा में, जांच प्रगति के रूप में सुधार हुआ है। जांच आरंभ करने का उद्देश्य संगत सूचना को एकत्र करना है। नियम 5 और 6 की अनिवार्यताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया गया है।
- निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच आरंभ होने पर पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश करते हुए जांच परिणाम दर्ज नहीं किया है। जांच आरंभ करने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त माने जाने वाली सूचना को शुल्क निर्धारण के प्रयोजन हेतु पर्याप्त नहीं माना जा सकता और जांच आरंभ के समय निर्धारण के लिए अपेक्षित सूचना पर जोर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।
- दिनांक 29 सितंबर, 2015 की अद्यतन याचिका के रूप में निर्दिष्ट एनसीवी याचिका, दिनांक 04 अप्रैल, 2016 के दो पत्र और 12 सितंबर, 2016 को प्रस्तुत पत्र के बीच की सांख्यिकी में कुछ अंतर है। दायर डाटा के चार अलग-अलग सेट इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	नाम	तारीख	डाटा में विभिन्नता का कारण
i.	अद्यतन याचिका	29 सितंबर, 2015	आईबीआईएस डाटा पर आधारित, जांच की अवधि - 2014-15
ii.	प्रथम पत्र	04 अप्रैल, 2016	आईबीआईएस डाटा पर आधारित, जांच की अवधि - अप्रैल, 2014 - सितंबर, 2015 तक - आयात के आंकड़ों और नियोजित पूंजी पर वापसी के आंकड़ों में कुछ संगणना त्रुटि है।
iii.	द्वितीय पत्र	04 अप्रैल, 2016	आईबीआईएस डाटा पर आधारित - जांच की अवधि - अप्रैल, 2014 - सितंबर, 2015 तक - दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को त्रुटि के परिशोधन के लिए दायर पत्र डीजीएडी में 18 अप्रैल, 2016 को प्राप्त किया गया।
iv.	तृतीय पत्र	12 सितंबर, 2016	डीजीसीआईएंडएस डाटा पर आधारित, जांच की अवधि अप्रैल, 2014 - सितंबर, 2015 तक। डीजीएडी के निर्देशानुसार दायर संशोधित डाटा पर आधारित पत्र दायर किया गया।

- v. याचिकाकर्ता ने की गई त्रुटि को स्वीकार करते हुए, दिनांक 06 सितंबर, 2016 को दायर पत्र के जरिए, दिनांक 04 अप्रैल, 2016 के पत्रों के अनुसार प्रस्तुत किए गए डाटा में विसंगति के बारे में पहले ही स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया है।
- vi. 04 अप्रैल, 2016 के पत्र में और 12 सितंबर, 2016 को दायर पत्र में प्रस्तुत डाटा में कोई विसंगति नहीं है क्योंकि 04 अप्रैल, 2016 को प्रस्तुत पत्र आईबीआईएस डाटा पर आधारित था जबकि परवर्ती पत्र डीजीसीआईएंडएस डाटा पर आधारित था।
- vii. वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने नवंबर, 2015 में समाप्त सीवीडी जांच में समान सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विचाराधीन उत्पाद की रेंज के भीतर उत्पादों के विस्तृत दायरे को देखते हुए पहले ही पीसीएन तैयार किया है।
- viii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने केवल निर्यातकों और आयातकों को प्रश्नावली जारी की और प्रयोक्ताओं या उनके संघ को कोई प्रश्नावली जारी नहीं की है। चूंकि, प्रयोक्ता संघ के जरिए प्रतिवेदन कर रहे हैं, यह अत्यावश्यक है कि प्राधिकारी प्रयोक्ताओं से और ऐसे प्रयोक्ता संघों से सूचना की मांग करें क्योंकि न तो प्रयोक्ता संघ और न ही प्रयोक्ताओं ने यह विचार करते हुए कोई भी सूचना, जो भी हो, प्रस्तुत नहीं की कि उनके द्वारा आयात किए गए हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए संघ को निर्देश जारी कर सकते हैं, जैसा नियमावली में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- ix. याचिकाकर्ता ने दोहराया है कि पद्धतियों का अनुसरण करके संख्या को भारांश में परिवर्तित किया गया है – हमने पीसीएन – बार समान कास्टिंग को बनाते हैं या उन्हें पहले बनाया है। ऐसे मामलों में जहां हम इसे नहीं बनाते, इन्हें बाजार सूचना के आधार पर अनुमानित किया जाता है।
- x. घरेलू उद्योग 2012 के बाद से लगातार क्षति का सामना कर रहा था क्योंकि प्रथम याचिका वर्ष 2013 में दायर की गयी थी। इसी बीच, सीवीडी लागू किया गया, जो अभी तक क्षति की पूर्ति करने में असमर्थ है। लागू किए गए सीवीडी के प्रभाव को देखने के लिए प्राधिकारी उद्योग के उन्मूलन की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सीवीडी को लागू किए जाने के पश्चात, घरेलू उद्योग के निष्पादन में ह्रास हुआ है।
- xi. एडीडी मामला 01 फरवरी, 2016 को आरंभ किया गया था, जिसके लिए 29 जुलाई, 2016 को सीवी याचिका दायर की गई थी। समान याचिका में जांच के अवधि को सही रूप से मार्च, 2014 से अप्रैल, 2015 लिया गया था। सीवीडी शुल्क 19 जनवरी, 2016 को लगाया गया था। सीवीडी शुल्क के प्रभाव को देखने के लिए, प्रतीक्षा करना व्यवहार्य नहीं था, जबकि सीवीडी को लागू भी नहीं किया गया था और घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही क्षति की पूर्ति करने में शुल्क सक्षम नहीं था। सीवीडी के प्रभाव को ध्यान में रखने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, एकमात्र बाध्यता दोहरे उपाय समस्या को हल करना है।
- xii. निर्यातक ने अद्यतन याचिका में दिए गए आयातों की मात्रा के आंकड़ों की तुलना की है, जो जांच की अवधि के रूप में 2014-15 के डाटा पर आधारित था, पहल पत्र, जिसमें त्रुटि थी, दूसरा पत्र जो आईबीआईएस डाटा पर आधारित था और जांच की अवधि अप्रैल, 2014 – सितंबर, 2015 थी तथा 12 सितंबर का तीसरा पत्र, जो डीजीसीआईएंडएस डाटा पर आधारित था।
- xiii. याचिकाकर्ता ने 12 सितंबर, 2015 के अनुसार, डीजीसीआईएंडएस डाटा और आईबीआईएस डाटा का तुलनात्मक विश्लेषण उपलब्ध कराया है। निर्यातक ने घरेलू उद्योग की औसत बिक्री लागत की चीन से आयातों की औसत कीमत से तुलना की है।
- xiv. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर आने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री कर रहा है, जबकि चीन से आयातों का प्रमुख भाग एसयूवी और मुख्य फ्रेम के रूप में आ रहा है। विचाराधीन उत्पाद की औसत कीमत पूरी तरह से भ्रामक है।
- xv. सभी चार निवेदनों में चीन से आयातों की कीमत में भिन्नता है, विशेष रूप से, जांच की अवधि में, क्योंकि अद्यतन याचिका में डाटा आईबीआईएस पर आधारित था और जांच की अवधि 2014-15 थी, जबकि दूसरे और तृतीय पत्र में लिया गया डाटा आईबीआईएस डाटा पर आधारित था, किंतु जांच की अवधि अप्रैल, 2014 से सितंबर, 2015 थी। तीसरा पत्र डीजीसीआईएंडएस डाटा पर आधारित है।
- xvi. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर आने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन कर रहा है और विचाराधीन उत्पाद की मात्राएं भ्रामक हैं जबकि विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमत महत्वपूर्ण क्षति को दर्शाती है।

- xvii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निर्धारण के लिए केवल क्षति अवधि पर विचार किया है और निर्धारण के लिए जांच की अवधि पश्च अवधि पर विचार नहीं किया है। एसबीआर और एसटीपीपी के मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सिफारिश के समय ज्ञात कराए गए तथ्य के बावजूद कि संबंधित घरेलू उद्योग ने उत्पादन बंद कर दिया था, पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी। प्राधिकारी ने तत्पश्चात एमटीआर आयोजित की और पाटनरोधी शुल्क की वापिसी की सिफारिश की। हालांकि, उत्पादन के समाप्त करने से मूल जांच अप्रभावित बनी रही।
- xviii. यदि हितबद्ध पक्षकार यह महसूस करते हैं कि जांच की अवधि के बाद स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, वे मध्यवर्ती समीक्षा की मांग कर सकते हैं।
- xix. हांगकांग में विचाराधीन उत्पाद का कोई उत्पादन नहीं होता और हांगकांग से निर्यातक ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करना स्वीकार किया है। यदि चीन में उत्पादित वस्तुओं का हांगकांग से निर्यात किया जाता है तो पाटनरोधी शुल्क को लागू करने के लिए हांगकांग के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता। प्राधिकारी द्वारा वस्तुओं का संभव स्थानान्तरण निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग को हांगकांग का साक्ष्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- 41. किए गए विभिन्न अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी ने निम्नानुसार धारित किया है:
- 42. विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने संबंधी याचिका बहुत पहले वर्ष 2013 में वर्तमान प्राधिकारी के समक्ष दायर की गई थी। तथापि, प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर पाटनरोधी जांच 01 फरवरी, 2016 को आरंभ की गई थी। यह दोहराया जाता है कि प्राथमिक संवीक्षा की आवश्यकताओं के तुष्टिकरण तक जांच आरंभ को अपनाया नहीं जाता। अतः याचिका को स्थापित करने के लिए साक्ष्यों को प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित समय एक समय लगने वाला कार्य है जिसकी आवेदक को इन्हें उपलब्ध करने में जरूरत होती है।
- 43. जबकि सब्सिडीरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच अधिसूचना संख्या 17/6/2013-डीजीएडी के अनुसार, दिनांक 29 मई, 2014 को आरंभ की गई थी जिसके अनुसरण में प्राधिकारी द्वारा 27 नवंबर, 2015 को अंतिम जांच परिणाम की सिफारिश की गई थी और अधिसूचना संख्या 1/2016-सीमा शुल्क (सीवीडी) के अनुसार दिनांक 19 जनवरी, 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा सीवीडी लागू की गई थी।
- 44. प्राधिकारी ने अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015 की अवधि के लिए पूर्ण सूचना सन्निहित करने वाली याचिका के आधार पर पाटनरोधी शुल्क जांच आरंभ की। जांच आरंभ के समीप की अवधि के डाटा की जांच करना अनिवार्य समझकर तदनुसार, इस जांच के प्रयोजन हेतु प्राधिकारी ने जांच की अवधि को अप्रैल, 2014 - सितंबर, 2015 तक बढ़ा दिया।
- 45. याचिकाकर्ताओं ने जांच की अवधि अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015 तक होते हुए, आईबीआईएस डाटा के आधार पर दिनांक 29 सितंबर, 2015 के पत्र के अनुसार, याचिका का अगोपनीय रूपांतरण दायर किया। उचित समय पर याचिकाकर्ता ने दिनांक 04 अप्रैल, 2016 के पत्र, जो 04 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हुआ था, के अनुसार विस्तारित जांच की अवधि अप्रैल, 2014 - सितंबर, 2015 होने पर अद्यतन याचिका दायर की। उक्त सूचना अप्रैल, 2014 - सितंबर, 2015 के आईबीआईएस डाटा पर आधारित थी। तथापि, आयात के आंकड़ों और नियोजित पूंजी पर वापिसी के आंकड़ों में संगणना संबंधी कुछ त्रुटि होने के कारण, याचिकाकर्ता ने आईबीआईएस डाटा के आधार पर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 के पत्र के अनुसार, एक संशोधित डाटा दायर किया जो डीजीएडी में 18 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हुआ।
- 46. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई बहुप्रयोजनीय प्रस्तुतियों और उनमें डाटा संबंधी विसंगतियों के संबंध में प्रथम सार्वजनिक सुनवाई के दौरान बहस का संदर्भ देते हुए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से एक अगोपनीय रूपांतरण, जिसे सार्वजनिक फोल्डर में रखा जाएगा और हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया जाएगा, सहित सही डाटा को सम्मिलित करते हुए एक पूर्ण निवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा। उक्त मेल के उत्तर में याचिकाकर्ता ने डीजीसीआईएंडएस डाटा के आधार पर, जांच की अवधि अप्रैल, 2014 - सितंबर, 2015 के लिए दिनांक 12 सितंबर, 2016 के पत्र के जरिए अन्य सूचना के साथ मैसर्स ब्रेडकेन का अद्यतन डाटा प्रस्तुत किया।
- 47. याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डाटा में अंतर के बारे में किए गए तर्क - वितर्क के संबंध में, यह टिप्पणी की गई है कि प्राधिकारी का निर्णय सत्यापित डाटा पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा सत्यापित डाटा पर आधारित निष्कर्ष को सार्वजनिक बयान बदल नहीं सकते। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 12 सितंबर, 2016 के ऊपर उल्लिखित पत्र के अनुसार विसंगति का समाधान किया गया और की गई त्रुटि को स्वीकार करते समय डाटा में विसंगति का स्पष्टीकरण दिया।

48. जहां तक याचिकाकर्ता दोहरे उपाय और फोरम शॉपिंग का संबंध है, प्राधिकारी ने टिप्पणी की है कि सब्सिडीरोधी/प्रतिसंतुलनकारी/पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन, सामान्यतः, सब्सिडी प्राप्त आयातों और पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त और उचित प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति को पुनः स्थापित करना है/किया जा सके। सीवीडी शुल्क 19 जनवरी, 2016 को लागू किया गया था। किसी पाटनरोधी शुल्क पर लेवी लगाते हुए, प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत अनिवार्यताओं पर विचार करेंगे और निर्यात सब्सिडी की सीमा तक कोई दोहरी गणना नहीं की जाएगी। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सकारात्मक निर्धारण किए जाने और पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने के निर्णय की स्थिति में, यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय सरकार से सब्सिडीरोधी/प्रतिसंतुलनकारी देय शुल्क, यदि कोई हो, को समायोजित करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।
49. उठाए गए इस विवाद के संबंध में कि याचिकाकर्ताओं ने क्षति डाटा के नीचे गलत जांच की अवधि को प्रक्षेपित करते हुए 01 फरवरी, 2016 को जारी जांच आरंभन अधिसूचना का संदर्भ देते हुए दिनांक 29 सितंबर, 2015 को एनसीवी याचिका दी है, घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि यह एक टंकण संबंधी त्रुटि है और यह कि डीजीएडी में अनुसरित की जा रही पद्धति के अनुसार जांच आरंभ अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात याचिका के अगोपनीय रूपांतरण प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।
50. उत्पाद के दायरे के विस्तृत दायरे को देखते हुए, और एक उचित प्रतिस्पर्द्धा के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन को फिर से एकत्र करने के बारे में विचार किया, जिसे दिनांक 25 मई, 2017 के पत्र के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को संप्रेषित किया गया।
51. जहां तक इस विवाद का संबंध है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात हांगकांग से आ रहे हैं, वर्तमान जांच के लिए हांगकांग संबद्ध देश नहीं है।

बाजार अर्थव्यवस्था उपचार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

क. सामान्य मूल्य

52. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
- व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*
 - जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-*
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा*
 - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;*

परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

निर्यातकों,आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

53. निर्यातकों/आयातकों/अन्य संबंधित पक्षों द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के अनुसार भारत में उत्पादन लागत के आधार पर यथोचित रूप से समायोजित सामान्य मूल्य का दावा किया गया है। यह एडीडी नियमों के अनुलग्नक 1(7) के तहत कानून की अपेक्षाओं के विरुद्ध है, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को आधार बनाया है जो कि नियमों के तहत अंतिम विकल्प है। प्राधिकारी तभी अंतिम विकल्प का प्रयोग कर सकता है जब अनुलग्नक 1 के पैरा 7 में दिए गए दोनों विकल्पों का प्रयोग किया जा चुका हो।
 - सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपयोग की गई पद्धति अस्पष्ट है और एडीडी नियमों के अनुलग्नक 1 के पैरा 7 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती।

- iii. “फासनर्स केस” के संबंध में एबी रिपोर्ट में प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 के समाप्त होने पर चीन के स्वतः बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त कर लेने के लिए मजबूत औचित्य दिया गया है। चीन अपने प्रवेश के बाद से ही अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है और भारत को समझौतों के तहत चीन के पूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को स्वीकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहिए और पाटनरोधी जांच में “स्थानापन्न देश” का दृष्टिकोण अपनाना बंद करना चाहिए।
- iv. 11 दिसंबर, 2016 के बाद भारत के पास गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति का प्रयोग करके चीनी उत्पादों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच में सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है और ऐसी कोई भी कार्रवाई जीएटीटी, 1994 और अन्य समझौतों के विरुद्ध होगी।
- v. ऐसी कोई गणना उपलब्ध नहीं कराई गई है कि कारखाना निर्यात मूल्य कैसे निर्धारित किया गया। यह गणना निराधार और अत्यधिक काल्पनिक है। यह अस्पष्ट है कि कैसे ग्रेड-दर-ग्रेड तुलना की गई है। पूर्ण तथा पुख्ता तरीके से डंपिंग अंतर गणना उपलब्ध कराएं।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

54. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:
 - i. चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है और किसी भी देश ने चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए योग्यता को पूरा करने हेतु विधि के अनुसार प्रत्येक शर्त पूरी नहीं की है। इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए चीनी उत्पादकों की लागत तथा मूल्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
 - ii. सामान्य मूल्य “किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उपभोग के प्रयोजन से ऐसी ही वस्तु हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनात्मक मूल्य” होना चाहिए। इस आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निर्धारित प्राधिकारी को ऐसे तीसरे देश में एक कोऑपरेटिंग उत्पादक द्वारा की गई सम्पूर्ण घरेलू बिक्री और उत्पादन की लागत के संबंध में पूर्ण तथा व्यापक सत्यापित की जा सकने वाली सूचना और इससे संबंधित अन्य सम्पूर्ण सूचना तथा प्रमाणों की आवश्यकता होगी।
 - iii. याचिकाकर्ता किसी भी अन्य देश के संबंध में यह सूचना प्राप्त नहीं कर पाया है और उसने अंतिम विकल्प का प्रयोग किया है चूंकि उनके पास एक उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के लिए आवश्यक सूचना नहीं थी।
 - iv. हितवर्द्ध पक्षों के पास जांच शुरू होने के बाद से किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश का सुझाव देने और इसके लिए प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय तथा अवसर था। हितार्थी पक्षों पर किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का सुझाव देने पर कोई रोक नहीं है।
 - v. भारत चीन के लिए एक उपयुक्त स्थानापन्न देश है चूंकि इससे सटीक तथा पर्याप्त सूचना प्राप्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त अन्य जांच प्राधिकरणों द्वारा भी भारत को उपयुक्त स्थानापन्न देश माना गया है।
 - vi. एससीएम के तहत कार्यवाही में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में उल्लिखित सब्सिडी के संबंध में एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे; तथापि यदि इन्हें लागू करने में कोई विशिष्ट कठिनाई आ रही है तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य सब्सिडी लाभ को चिन्हित करने तथा इसका मापन करने के लिए पद्धतियों का प्रयोग कर सकता है जिनमें इस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में लागू निबंधन एवं शर्तें सदैव उपयुक्त मानदंड के रूप में उपलब्ध न हों। ऐसी पद्धति का प्रयोग करते समय जहां व्यवहार्य हो वहां आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य को चीन से बाहर लागू निबंधन एवं शर्तों का प्रयोग करने पर विचार करने से पहले चीन में लागू ऐसी निबंधन एवं शर्तों को समायोजित करना चाहिए।
 - vii. अनुच्छेद 15(ख) में उल्लेख किया गया है कि खंड 15(क)(ii) के प्रावधान चीन के प्रवेश करने के 15 वर्ष में समाप्त हो जाएंगे। इस प्रावधान का यह प्रभाव है कि डीए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए चीन में लागत तथा मूल्य पर विचार नहीं कर रहे।
 - viii. चीनी उत्पादों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वातावरण के तहत प्रचालित कम्पनियां माना जाना चाहिए और तब तक सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के आधार पर किया जाना चाहिए जब तक जांच अवधि में दिसंबर, 2016 तक की अवधि शामिल है।
 - ix. वर्तमान मामले में पीओआई अप्रैल 2014 – सितंबर 2015 है, धारा 15 के प्रावधान वर्तमान जांच अवधि पर पूर्णतया लागू होंगे। चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के आधार पर किया जाना चाहिए।
 - x. अनुच्छेद 15(क)(i) के प्रावधान अभी भी लागू हैं और चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इन पर विचार किया जाना होगा। उपर्युक्त प्रावधानों की कोई और व्याख्या नहीं हो सकती। इसलिए निर्दिष्टप्राधिकारी कृपया

चीनी उत्पादकों को यह निर्देश दे कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन तथा बिक्री के संबंध में ऐसे समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग पर बाजार अर्थव्यवस्था की शर्तें लागू हैं, ताकि निर्धारित प्राधिकारी जांच के अधीन उद्योग के लिए चीनी मूल्य अथवा लागत का प्रयोग कर सके।

- xi. प्रतिवादी निर्यातकों को यह स्थापित करना चाहिए कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में उल्लिखित लागत घटक जांच के अधीन निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा रखे गए रिकॉर्ड में उचित रूप से तथा पूर्णतया दर्शाए गए हैं। यदि लागत के कुछ घटक जांच के अधीन निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा रखे गए रिकॉर्ड में उचित रूप से तथा पूर्णतया नहीं दर्शाए गए हैं तो निर्दिष्टप्राधिकारी व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के दावे को खारिज कर देगा।
- xii. निर्दिष्टप्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पैरा 1-6 का अनुसरण तभी करेंगे यदि प्रतिवादी चीनी कम्पनियां यह स्थापित करें कि उनकी लागत तथा मूल्य की सूचना ऐसी है कि व्यक्तिगत सामान्य मूल्य तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जा सकता है। यदि प्रतिवादी चीनी कम्पनियां यह प्रदर्शित नहीं कर पाती कि उनके द्वारा दी गई लागत तथा मूल्य की सूचना अपनाई जा सकती है तो निर्दिष्टप्राधिकारी व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के दावे को खारिज कर देंगे।
- xiii. प्राधिकारी को चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय को यथोचित रूप से समायोजित करते हुए और याचिकाकर्ताओं के उपभोग मानकों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।
- xiv. पीयूसी का उत्पादन तथा बिक्री विभिन्न प्रकार से/रूपों में की जाती है जो संबंधित लागत और/अथवा मूल्य के संबंध में उल्लेखनीय रूप से अलग-अलग है। इसलिए याचिकाकर्ता ने एक पीसीएन पद्धति बनाई है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत लेन-देन में शामिल उत्पाद को चिह्नित करने के लिए किया जाता है।
- xv. पीसीएन का प्रयोग पाटन तथा नुकसान के अंतर का निर्धारण करने के लिए किया गया है।
- xvi. निर्यात मूल्य का निर्धारण प्रत्येक पीसीएन के लिए अलग-अलग भारत औसत आयात मूल्य के रूप में किया गया है। निर्यात मूल्य की गणना सीआईएफ स्तर पर की गई है। पाटनरोधी के संबंध में डब्ल्यूटीओ समझौते और भारतीय नियमों के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना व्यापार के समान स्तर पर की जानी चाहिए। इसलिए निर्यात मूल्य को समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, बंदरगाह व्यय, बैंक शुल्क तथा अंतर्देशीय भाड़े के व्यय के लिए समायोजित किया गया है जिनका वहन निर्यातक द्वारा भारत में सामान के निर्यात के लिए किया गया हो।

प्राधिकारी द्वारा जांच – गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में चीन

55. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

- (क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
 - (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
 - (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्यसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए उस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाता है कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में

सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों लागू करने में, जहाँ व्यवहार्य हो, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों के संबंध में पाटनरोधी कार्य समिति को सूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों के संबंध में कमिटी ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मैजर्स को सूचित करेगा।

(घ) चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया कि आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्रवेश की तारीख को बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्रवेश की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में यदि चीन के द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

56. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने प्रतिक्रिया दी है और प्रश्नावली का जवाब दिया है।

क. दालियान हौरारी हैवी इंडस्ट्री कास्टिंग क. लि.

ख. जिंसु फॉ फाउंड्री क. लि.

ग. जेजियांग जियाली विंड पावर टैक्नोलोजी क. लि.

घ. जियांगसु सिनोजित विंड एनर्जी टैक्नोलोजी क. लि.

- चांगझु सिनोजित विंडएनर्जी टैक्नोलोजी क. लि.
- जियांग्यिन हेंगुआ मशीनरी क. लि., जियांग्यिन सिटी
- जियांग्यिन क्विक्सिंग टैक्नोलोजी क. लि., जियांग्यिन सिटी
- जियांग्यिन चैजिंग न्यू एनर्जीक. लि., वुक्सी सिटी, जियांगसु
- टैकटोन एचके लि.

ड. नानटोंग होग्डे मैकेनिकल क. लि. एंड कोजुमी मशीनरी क.लि.

च. येओंग गुआन एनर्जी टैक्नोलोजी ग्रुप कम्पनी लिमिटेड

- डोंगुआन येओंग गुआन मोल्ड फैक्टरी क. लि.
- जियांगसु ब्राइट स्टील फाइन मशीनरी क. लि.
- निंगबो लू लिन मशीन टूल फाउंड्री क. लि.
- निंगबो येओंग शांग कास्टिंग आइरन क. लि.
- येओंग चैन एशिया पैसिफिक क. लि.

57. येओंग गुआन एनर्जी टैक्नोलोजी ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, चीन पीआर और इसकी सहायक कम्पनियों के अतिरिक्त जन.गण. के किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) संबंधी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इसलिए वर्तमान जांच में अन्य सहयोगी निर्यातकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है। येओंग गुआन एनर्जी टैक्नोलोजी ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, चीन जन.गण. और इसकी सहायक कम्पनियों ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा किया है और बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

58. येओंग गुआन एनर्जी टैक्नोलोजी ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.र और इसकी सहायक कम्पनियों ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का अनुरोध किया है। निम्नलिखित इसकी संबंधित कम्पनियाँ हैं-

- i. येओंग गुआन एनर्जी टैक्नोलोजी ग्रुप – डोंगुआन येओंग गुआन मोल्ड फैक्टरी क. लि.
- ii. येओंग गुआन एनर्जी टैक्नोलोजी ग्रुप – जियांगसु ब्राइट स्टील फाइन मशीनरी क. लि.
- iii. येओंग गुआन एनर्जी टैक्नोलोजी ग्रुप – निंगबो लू लिन मशीन टूल फाउंड्री क. लि.

- iv. येओंग गुआन एनर्जी टैक्नोलोजी ग्रुप – निंग्बो येओंग शांग कास्टिंग आइरन क. लि.
- v. येओंग गुआन एनर्जी टैक्नोलोजी ग्रुप – येओंग घेन एशिया पैसिफिक क. लि.
59. निर्यातक समूह कम्पनी ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं-
- प्रत्येक सहायक कम्पनी पर अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी का येओंग गुआन इंटरनैशनल क. लिमिटेड ("येओंग गुआन एचके") के माध्यम से स्वामित्व है जो कि होंग कोंग के कानूनों के तहत निगमित एक कम्पनी है और इस पर पूर्णतः कम्पनी का स्वामित्व है। इन सभी कम्पनियों पर कम्पनी का पूर्ण स्वामित्व है, जो कि ताइवान में एक सार्वजनिक-व्यापार वाली कम्पनी है और इस प्रकार ये 100% विदेशी निवेश वाली सहायक कम्पनियां हैं।
 - कम्पनी ताइवान में एक सूचीबद्ध कम्पनी है जो कि कैमैन आइलैंड्स में पंजीकृत एक नियंत्रक कम्पनी है। इसके व्यापार का प्रचालन चीन जन.गण. और ताइवान में कम्पनी के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों द्वारा किया जाता है। पीओआई के दौरान येओंग गुआन ग्रुप द्वारा भारत को पीयूसी की निर्यात की जाने वाली सम्पूर्ण सामग्री चीन पीआर में निर्मित की जाती थी जबकि निर्यातक हैं (i) येओंग शांग निंग्बो और (ii) येओंग चेन ताइवान। अन्य तीन सहायक कम्पनियां ब्राइट स्टील जियांग्सु, येओंग गुआन डोंगोन और लू लिन निंग्बो चीन पीआर में पीयूसी का निर्माण करती थी और इसे चीन जन.गण. में बेचती थीं और साथ ही वे इसे संबंधित कम्पनियों को पीओआई के दौरान किसी तीसरे देश (भारत सहित) को पुनः बेचने के लिए भी बेचती थीं।
 - चूंकि कम्पनी एक सार्वजनिक कम्पनी है इसमें केवल दो अंशधारक हैं जिनके पास कम्पनी के कम से कम 5% शेयर हैं। कम्पनी के दो अंशधारक व्यक्ति हैं और ताइवान के नागरिक हैं। येओंग गुआन एचके ब्राइट स्टील जियांग्सु, जिस पर येओंग गुआन एचके और येओंग गुआन डोंगोन का आंशिक स्वामित्व है, को छोड़ कर चारों सहायक कम्पनियों का एकमात्र अंशधारक है। कम्पनी येओंग गुआन एचके की एकमात्र अंशधारक है। कम्पनी एक कैमैन कम्पनी है और ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।
 - सभी आपूर्तिकर्ता चीन जन.गण. में निगमित प्राइवेट कम्पनियां हैं। येओंग गुआन ग्रुप ने किसी ऐसे व्यक्ति से कच्चा माल नहीं खरीदा जो एक सरकारी अधिकारी हो अथवा सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली किसी कम्पनी में कार्यरत हो। कच्चे माल का खरीद मूल्य बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों के बीच बात-चीत से निर्धारित किया जाता था और बाजार मूल्य के अनुरूप होता था। सभी सुविधाओं के लिए सामान्य दर से शुल्क लिया जाता है। कम्पनी अथवा इसकी पांच सहायक कम्पनियों द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल के आयात पर कोई रोक अथवा शर्त नहीं है।
 - येओंग गुआन ग्रुप बाजार की स्थितियों, उत्पादन की लागत, ऑर्डर की मात्रा और आपूर्ति के समय सहित प्रमुख व्यापार घटकों और बिक्री की अन्य शर्तों को ध्यान में रखते हुए पीयूसी के बिक्री मूल्य का प्रस्ताव करता है। सभी बिक्री मूल्य येओंग गुआन ग्रुप और इसके उपभोक्ताओं के बीच सीधी बात-चीत से तय होते हैं और येओंग गुआन ग्रुप और उपभोक्ताओं के बीच सहमति होने पर इनका निर्धारण किया जाता है। बिक्री मूल्य किसी समीक्षा अथवा किसी सरकार के निर्देशों के शर्ताधीन नहीं होता।
 - कम्पनी का प्रबंधन इसके निदेशकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रबंधन टीम को सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती अथवा सरकार को सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती सिवाय इसके कि कर जमा कराने के प्रयोजन से मुख्य वित्तीय अधिकारी चीन जन.गण. के वित्त मंत्रालय में पंजीकृत होना चाहिए। कम्पनी और इसकी पांच सहायक कम्पनियों का प्रबंधन उनके निदेशकों के नियंत्रण में है। वे सभी कम्पनी और पांचों सहायक कम्पनियों के निदेशक बनने से पहले निजी कम्पनियों के लिए कार्य करते थे। कम्पनी अथवा इसकी पांच सहायक कम्पनियों के निर्यात राजस्व पर कोई सीमा नहीं है। बैंक खाता कम्पनी अथवा पांचों सहायक कम्पनियों के नाम पर रखा जाता है जैसा भी मामला हो।
 - कम्पनी के कर्मचारियों को पारिश्रमिक के रूप में महीने में एक बार वेतन, समयोपरि वेतन और सांविधिक भत्ते दिए जाते हैं। कर्मचारियों को समयोपरि वेतन और भत्तों का भुगतान लागू कानूनों के अनुसार किया जाता है। कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति का भुगतान महीने में एक बार किया जाता है। पांचों सहायक कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी अपने कर्मचारियों को सीधे भुगतान करती है। चीन के श्रम कानून के अनुसार एक कम्पनी को पांच प्रकार के बीमा तथा आवासन के लिए निधि का अंशदान करना चाहिए जिनमें कर्मचारियों के लिए अक्षय निधि, चिकित्सा, बेरोजगारी, रोजगार के दौरान चोटिल होने, मातृत्व और आवास भविष्य निधि शामिल हैं। कम्पनी अथवा इसकी पांच सहायक कम्पनियां मलेशियाई राष्ट्रीयता के 2 कर्मचारियों की सेवाएं लेती हैं और इसके प्रबंधन में कई प्रमुख व्यक्ति ताइवान के नागरिक हैं।
60. अनुच्छेद 15 का अर्थ है कि एक उप-पैरा के प्रावधान चीन के प्रवेश करने के बाद से 15 वर्ष में समाप्त हो जाएंगे। इस पैरा के प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए। चूंकि पाटन द्वारा घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचने का तथ्य जांच

अवधि के आधार पर ही स्थापित किया गया है इसलिए वर्तमान जांच के उद्देश्य से केवल जांच अवधि के दौरान की स्थितियां संगत, उपयुक्त तथा आवश्यक हैं। वर्तमान समीक्षा के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2014 से सितंबर, 2015 तक है। चूंकि अनुच्छेद 15 का उप-पैरा जांच की अवधि के दौरान लागू था इसलिए प्राधिकारी एक ऐसी पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं जो कि चीन में घरेलू मूल्य अथवा लागत के साथ पूर्ण तुलना न करे यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से नहीं दर्शा सकता कि उत्पाद के निर्माण, उत्पादन तथा बिक्री के संबंध में ऐसे ही उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां हैं।

61. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में भारत और अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांच में चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश माना गया है। चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश माना गया है बशर्ते कि नियमों के संदर्भ में निर्यातक देश अथवा व्यक्तिगत निर्यातकों द्वारा इस परिकल्पना का खंडन न किया जाए।

62. यथासंशोधित पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक I पैरा 8 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की परिकल्पना का खंडन किया जा सकता है यदि चीन के निर्यातक पैरा 8 के उप-पैरा (3) में विनिर्धारित मानदंडों के आधार पर सूचना तथा पर्याप्त प्रमाण दे और इस धारणा के विपरीत सिद्ध करे। चीन जन.गण. वस्तुओं के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप-पैरा (3) में उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराने होंगे ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सके कि क्या:-

- क. चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों के कच्चे माल, प्रौद्योगिकी तथा श्रम की लागत, परिणाम, बिक्री तथा निवेश सहित मूल्य, लागत और इनपुट के संबंध में निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों की प्रतिक्रिया में और इस संबंध में राज्य के अधिक हस्तक्षेप के बिना लिए जाएं और क्या प्रमुख इनपुट की लागत उल्लेखनीय रूप से बाजार मूल्य को दर्शाती है;
- ख. ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति में पूर्व की गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली में उल्लेखनीय विरूपण की संभावना है, विशेष रूप से सम्पत्ति के अवमूल्यन, अन्य बट्टे खाते, वस्तु विनिमय व्यापार और ऋण की प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान के संबंध में;
- ग. ऐसी फर्मों के दिवालिया होने और सम्पत्ति कानून, जो फर्मों के प्रचालन के लिए कानूनी सुनिश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देते हैं, के तहत आने की संभावना है और
- घ. विनिमय दर रूपांतरण बाजार दर पर किया जाता है।

63. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए और किसी चीनी निर्यात कम्पनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की परिकल्पना का खंडन न किए जाने की स्थिति में प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानना उचित समझते हैं और चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमों के अनुलग्नक-I पैरा 7 के अनुसार आगे बढ़ने का प्रस्ताव करते हैं।

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

64. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से अनुलग्नक-I पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। चीन पीआर से भारत में आयात किए जाने वाले उत्पादों का सामान्य मूल्य प्रमुख कच्चे माल के लिए घरेलू उद्योग के इष्टतम उपभोग मानकों, घरेलू औद्योगिक मूल्यों के अनुसार कच्चे माल की लागत, घरेलू उद्योग के लिए अनुमत्य स्तरों पर रूपांतरण लागत, ब्याज, एसजीए आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। उचित लाभ के लिए ब्याज को छोड़ कर बिक्री की लागत की *** की अनुमति दी गई है।

निर्यात मूल्य

65. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातक समूहों ने वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली (ईक्यू) का जवाब प्रस्तुत किया है-

- क. दालियान हौरुई हैवी इंडस्ट्री कास्टिंग क. लि.
- ख. जियांग्सु फॉ फाउंड्री क. लि.
- ग. झेजियांग जियाली विंड पावर टैक्नोलोजी क. लि.
- घ. जियांग्सु सिनोजित विंड एनर्जी टैक्नोलोजी क. लि.
 - चांगझू सिनोजित विंड एनर्जी टैक्नोलोजी क. लि.
 - जियांग्यिन हेंगुआ मशीनरी क. लि., जियांग्यिन सिटी
 - जियांग्यिन क्विक्सिंग टैक्नोलोजी क. लि., जियांग्यिन सिटी
 - जियांग्यिन चेंजलिंग न्यू एनर्जी क. लि., वुक्सी सिटी, जियांग्सु

➤ टैकटोन एचके लि.

ड. नांटोंग होंगडे मैकेनिकल क. लि. और कोइजुमी मशीनरी क. लि.

च. येओंग गुआन एनर्जी टेक्नोलोजी ग्रुप कम्पनी लिमिटेड

➤ डोंगौन येओंग गुआन मोल्ड फैक्टरी क. लि.

➤ जियांग्सु ब्राइट स्टील फाइन मशीनरी क. लि.

➤ निंग्बो लू लिन मशीन टूल फाउंड्री क. लि.

➤ निंग्बो येओंग शांग कास्टिंग आयरन क. लि.

➤ येओंग घेन एशिया पैसिफिक क. लि.

66. उत्तरों की जांच के बाद प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों के आंकड़ों का सत्यापन किया गया। डीजीसीआई एवं एस आंकड़ों की जांच की गई है। निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का सत्यापन किया गया और निर्यातकों की प्रश्नावली के परिशिष्ट-वार उत्तरों की जांच की गई।

67. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को स्वीकार कर लिया है और बाद में निर्यात मूल्य तथा डंपिंग अंतर के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा इनका सत्यापन किया गया। उत्तर देने वाले उन निर्यातकों के लिए जिनकी निर्यात कीमत तथा मूल्य समायोजन का सत्यापन कर लिया गया है, उनकी परिशिष्टवार सूचना तथा इनके द्वारा दावा किए गए सभी समायोजनों में दी गई भारत में उनकी कीमतों तथा प्राधिकारी द्वारा सत्यापित कीमतों को ध्यान में रखते हुए निर्यात कीमत निर्धारित की गई है।

68. प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार उत्तर न देने वाले निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। अन्य निर्यातकों के लिए एक सहकारी निर्यातक की निवल निर्यात कीमत तथा सामान्य मूल्य स्वीकार किया गया है।

69. इस प्रकार निर्धारित डंपिंग अंतर नीचे तालिकाबद्ध रूप से समूह-वार दिया गया है।

पाटनमार्जिन

70. डंपिंग अंतर का पता लगाने के लिए भारत के लिए निर्यात मूल्य (निर्यातक द्वारा दावा किए गए और प्राधिकारी द्वारा उचित सत्यापन के बाद स्वीकृत सभी समायोजनों का निवल) की तुलना सामान्य मूल्य से की गई है। संदर्भित देश में सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पीओआई के दौरान डंपिंग अंतर नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार निर्धारित किया गया है:

डंपिंग अंतर तालिका						
क्र. सं.	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य अम.डा./मी.ट.	निर्यात मूल्यअम.डा./मी.ट.	डंपिंग अंतरअम.डा./मी.ट.	डंपिंग अंतर %
1	दालियान हौरुई हेवी इंडस्ट्री कास्टिंग क. लि.	दालियान हौरुई हेवी इंडस्ट्री कास्टिंग क. लि.	***	***	***	15-25
2	झेजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलोजी क. लि.	झेजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलोजी क. लि.	***	***	***	15-25
3	जियांग्सु सिनोजित विंड एनर्जी टेक्नोलोजी क. लि. ➤ चांगझू सिनोजित विंड एनर्जी टेक्नोलोजी क. लि. ➤ जियांग्यिन हेंगुआ मशीनरी क. लि., जियांग्यिन सिटी ➤ जियांग्यिन क्विक्सिंग टेक्नोलोजी क. लि., जियांग्यिन सिटी ➤ जियांग्यिन चैजलिंग न्यू एनर्जी क. लि.,	जियांग्सु सिनोजित विंड एनर्जी टेक्नोलोजी क. लि. टैकटोन एचके लि.	***	***	***	15-25

	बुक्सी सिटी, जियांग्सु					
4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नांटोंग होंगडे मैकेनिकल क. लि. ➤ कोइजुमी मशीनरी क. लि. 	नांटोंग होंगडे मैकेनिकल क. लि.	***	***	***	15-25
5	जियांग्सु फॉ फाउंड्री क. लि.	जियांग्सु फॉ फाउंड्री क. लि.	***	***	***	30-40
6	येओंग गुआन एनर्जी टेक्नोलोजी ग्रुप कम्पनी लिमिटेड <ul style="list-style-type: none"> ➤ डोंगौन येओंग गुआन मोल्ड फैक्टरी क. लि. ➤ जियांग्सु ब्राइट स्टील फाइन मशीनरी क. लि. ➤ निंग्बो लू लिन मशीन टूल फाउंड्री क. लि. ➤ निंग्बो येओंग शांग कास्टिंग आयरन क. लि. ➤ येओंग घेन एशिया पैसिफिक क. लि. 	निंग्बो येओंग शांग कास्टिंग आयरन क. लि. येओंग घेन एशिया पैसिफिक क. लि.	***	***	***	15-25
	शेष अन्य		***	***	***	45-55

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

71. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितार्थी पक्षों द्वारा घरेलू उद्योग को नुकसान के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई:

- निर्दिष्ट प्राधिकारी को वर्तमान जांच शुरू नहीं करनी चाहिए थी और इसे अब तदनुसार समाप्त कर दिया जाना चाहिए चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना तथा दस्तावेज विभिन्न मानकों के संदर्भ में अस्पष्ट और भ्रामक हैं।
- इन आरोपों को दृढ़ता के साथ खारिज किया जाता है कि कोई नुकसान और पाटन है और/अथवा यदि उपाय नहीं किए गए तो गंभीर नुकसान होने का खतरा है।
- घरेलू उद्योग को हुआ नुकसान चीन से आने वाले आयात के कारण नहीं है। घरेलू उद्योग को हुए नुकसान चीन से आयात के कारण नहीं हुए हैं।
- जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में पीओआई अप्रैल, 2014 से सितंबर, 2015 के बीच है जबकि याचिका में दी गई सम्पूर्ण सूचना अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 के बीच की है। पीओआई के सटीक तथा ठीक-ठीक आंकड़ों के बिना प्राधिकारी ने किस आधार पर जांच शुरू की है और अन्य हितार्थी पक्षों से टिप्पणियां मांगी हैं। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को प्रारंभिक अधिसूचना के अनुसार पीओआई के लिए सभी नुकसान मानदंड उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देना चाहिए।
- आयात की मात्रा में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। प्रस्तुत किया गया प्रमाण यह प्रदर्शित करने में असफल है कि आयात से डीआई को कोई नुकसान हुआ है। आयात से घरेलू उद्योग के मूल्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा और कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि यह कृत्रिम रूप से बनाया गया है।
- इसलिए वस्तुओं पर सीमा शुल्क 7.5% से कम हो कर 5% होने के बावजूद दो पीओआई के बीच लैंडेड मूल्य में वृद्धि हुई है।
- आयात में वृद्धि का अर्थ यह नहीं है कि भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पादका पाटन किया जा रहा है और न ही इसका अर्थ ये है कि मूल देश से विचाराधीन उत्पाद के बाजार हिस्से में तेजी से वृद्धि हो रही है।

- viii. सीवीडी जांच के लिए याचिका, पाटनरोधी जांच के लिए याचिका में जिस मांग का दावा किया गया है और सीवीडी की जांच में जारी किए गए अंतिम जांच परिणाम से मेल नहीं खाते।
- ix. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया मूल्य घटाने का दावा गलत है।
- x. घरेलू उद्योग अच्छा उत्पादन कर रहा है और वृद्धि सकारात्मक है। प्रारूप IV(A) का उचित विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है और इसमें कोई सूचना छिपाई नहीं जानी चाहिए।
- xi. घरेलू उद्योग ने अपना उत्पादन, बाजार हिस्सा, क्षमता का प्रयोग, घरेलू बिक्री और श्रम शक्ति को बढ़ाया है जो कि यह दर्शाता है कि यह एक बढ़ता हुआ उद्योग है जिसे कोई क्षति अथवा नुकसान नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत घट गई है।
- xii. एनआईपी के निर्धारण के लिए लगाई गई पूंजी पर 22% के प्रतिफल को उत्पादन की लागत में जोड़ा जाता है।
- xiii. घरेलू उद्योग में मांग में वृद्धि बिक्री की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है और पीओआई में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में लगभग 8% की वृद्धि दर्शाती है।
- xiv. पीयूसी के आयात के कारण घरेलू उद्योग को कोई स्पष्ट क्षति/उल्लेखनीय नुकसान नहीं हुआ है।
- xv. आयात की मात्रा और डीआई के लाभ के बीच सह-संबंध स्थापित नहीं किया गया है। जब आयात की मात्रा में तेजी से गिरावट आई तो घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई जबकि जब आयात बढ़ रहे थे तो डीआई में एक सकारात्मक रुझान देखा गया।
- xvi. नुकसान के निर्धारण के लिए विचारित अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई जबकि वेतन में कमी आई।
- xvii. नुकसान के अंतर के निर्धारण के लिए कोई स्पष्ट पद्धति नहीं अपनाई गई और यह पूर्णतः गलत तथा भ्रामक दिखाई देती है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया नुकसान का अंतर प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर अवास्तविक है और सब्सिडी-विरोधी जांच में स्थापित नुकसान के अंतर की तुलना में इसमें नाटकीय वृद्धि हुई है।
- xviii. कांसबहल इकाई में उत्पादन पर रोक को अनुलग्नक III, पैरा 4(iv) के अर्थ में एक असाधारण व्यय के रूप में देखा जाना चाहिए और उत्पादन की लागत में इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- xix. याचिकाकर्ता के आर्थिक घटकों में परेशानी वाला घटक है उत्पादन क्षमता में कमी जो कि तय सम्पत्ति में प्रदर्शित नहीं हो रहा।
- xx. याचिका और घरेलू उद्योग द्वारा इसकी लेखापरीक्षा रिपोर्टों में दर्शाए गए तथ्यों में कई असंगतियां और विरोधाभासी दावे किए गए हैं।
- xxi. सीएएसटीएटी ने ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाइलैंड) बनाम डीए के मामले में कहा था कि नुकसान का निर्धारण और करणीय संबंध का निर्धारण एक विश्वसनीय तरीके से किया जाना चाहिए और ऐसा न होने पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को हटाया जा सकता है।
- xxii. आयात मूल्य और घरेलू उद्योग के मूल्य में परिवर्तन के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग के लिए बिक्री मूल्य को कम करने का कोई कारण नहीं है विशेष रूप से पीओआई के दौरान जब आयात मूल्य बढ़ गया।
- xxiii. आयात मूल्य और घरेलू उद्योग की लाभकारिता के बीच कोई करणीय संबंध नहीं है। नुकसान व्यापार नीतियों के कारण हुआ है। नुकसान जांच की अवधि के दौरान संयंत्र बंद करने के कारण हुआ है।
- xxiv. नुकसान अन्य कारणों से हुआ है जैसे होंग कोंग से आयात। होंग कोंग से आयात का मूल्य चीन से कम है। चीन पर सीवीडी लगाए जाने के बाद, इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं है कि चीन से आयात के कारण डीआई को कोई नुकसान हुआ हो।
- xxv. घरेलू उद्योग द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद अथवा उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली तकनीकें निम्न गुणवत्ता की हैं। घरेलू उद्योग उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा नहीं करता। यही प्रमुख कारण है कि सीवीडी लगाए जाने के बावजूद संबंधित देश से आयात जारी है। एलएंडटी की कच्ची कास्टिंग अन्य स्थानों पर ले जाई जाती है जिसमें अधिक समय तथा लागत लगती है।
- xxvi. पवन ऊर्जा क्षेत्र में नुकसान के कारण होने वाला नुकसान। घरेलू उद्योग को उस वर्ष काफी नुकसान हुआ जब पवन ऊर्जा क्षेत्र में नुकसान हो रहा था। यह एक संयोग नहीं हो सकता। 2013 में पवन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि से तेजी से बढ़ते मूल्य-ह्रास और सृजन आधारित प्रोत्साहन में कमी आई। यह डीआई को होने वाले नुकसान का एक कारण हो सकता है। इसलिए 2013 में डीआई को बड़ा नुकसान हुआ।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

72. याचिकादाता ने प्रारंभ में जांच अवधि, अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015 के लिए सूचना प्रदान की थी, जिसके आधार पर प्राधिकारी ने जांच शुरू की थी। प्राधिकारी ने यह आवश्यक समझा था कि जांच शुरू करने की अवधि से निकटस्थ अवधि के आंकड़ों की जांच की जाए और तदनुसार उपरोक्त बढ़ाई गई अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा जांच अवधि, अप्रैल, 2014 - सितंबर, 2015 के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे।

73. याचिकादाता ने जांच के लिए अप्रैल, 2014 - सितंबर, 2015 तक की अवधि के लिए जांच शुरू करने के बाद की सभी संशोधित सूचना प्रदान की है। तथापि, क्षति अवधि में वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और अप्रैल, 2014 - सितंबर, 2015 (जांच अवधि) भी शामिल होगी। घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) कुल आयातों के साथ-साथ संबद्ध देश से आयात में मूल वर्ष से ले कर वर्ष 2012-13 तक गिरावट आई है, जिसमें जांच अवधि तक और अधिक गिरावट आई है। संबद्ध देश की मांग में बाजार का हिस्सा स्थिर बना हुआ है।
- (2) वर्ष 2010-11 से ले कर जांच पश्चात अवधि, 2015-16 तक सीवीडी लागू होने के बाद भी चीन से आयातों की मात्रा में विकट वृद्धि हुई है। बाजार के हिस्से के संबंध में उल्लेखनीय है कि क्षति अवधि में संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि हुई है।
- (3) वैश्विक मंदी होने के कारण वर्ष 2012-13 और 2013-14 में मांग में गिरावट आने के कारण संबद्ध देश के आयातों में गिरावट आई है। तथापि, इसे उसी वर्ष में संबद्ध देश से आयातों के बाजार के हिस्से में हुई वृद्धि के आलोक में देखा जा सकता है।
- (4) मूल वर्ष से ले कर वर्ष 2012-13 तक मांग में गिरावट आई है, जिसमें जांच अवधि में और वृद्धि हुई है। अकेले याचिकादाता के पास इतनी क्षमता विद्यमान है कि वह देश में वर्तमान और भावी मांग को पूरा कर सकता है, लेकिन वह पाटित आयातों के निरंतर विद्यमान होने से ऐसा नहीं कर पाया है।
- (5) समस्त क्षति अवधि में खपत के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है और उत्पादन के संबंध में आयातों में मूल वर्ष से ले कर वर्ष 2012-13 तक गिरावट आई है और इसमें जांच अवधि तक और अधिक गिरावट आई है।
- (6) आयातों की पहुंच कीमतें, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से अत्यधिक कम रही हैं जिसके परिणामस्वरूप कीमत में अत्यधिक कटौती हो रही है।
- (7) संबद्ध वस्तुओं की बिक्रियों की लागत में मूल वर्ष से ले कर वर्ष 2012-13 तक गिरावट आई है और इसमें जांच अवधि तक और अधिक गिरावट आई है। समस्त क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को अपनी बिक्रीकीमतों को लागत से भी कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है, जिसके फलस्वरूप कीमतहास हुआ है और उसको अत्यधिक वित्तीय घाटे हुए हैं। संबद्ध वस्तुओं के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का अत्यधिक हास और न्यूनीकरण कर रहे हैं। इस प्रकार घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- (8) निर्दिष्ट प्राधिकारी को समग्र कार्य-निष्पादन पर विचार करना चाहिए तथा छांटों और चुनों की प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए।
- (9) देश में पर्याप्त मांग होने के बावजूद भी मूल वर्ष 2012-13 से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में गिरावट आई तथा वर्ष 2013-14 और जांच अवधि में उसके उत्पादन में और अधिक गिरावट आई है।
- (10) घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और मूल वर्ष से ले कर वर्ष 2012-13 तक इसमें अत्यधिक गिरावट आई है तथा जांच अवधि तक इसमें और अधिक गिरावट आई है।
- (11) घरेलू उद्योग की बिक्रियों की प्रवृत्ति भी वही रही है जैसे कि क्षमता उपयोग की रही है।
- (12) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में अत्यधिक गिरावट आई है क्योंकि घरेलू उद्योग को क्षति अवधि में अत्यधिक वित्तीय घाटे हुए हैं। नकदी लाभ ने भी वही प्रवृत्ति दर्शाई है, जैसे कि घरेलू उद्योग के लाभ की प्रवृत्ति रही है और घरेलू उद्योग को विगत कुछ समय से निवेश पर अत्यधिक नकारात्मक प्रतिलाभ हो रहा है।
- (13) उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग की कीमत के प्राचलों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है और उनमें अत्यधिक गिरावट आई है।
- (14) प्राधिकारी की सामान्य पद्धति के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा 22% के प्रतिलाभ को अपनाया गया है।
- (15) क्षति अवधि में एनएफए में 34% तक की गिरावट आई है।

- (16) घरेलू उद्योग ने अपनी कीमत को पाटित आयातित वस्तुओं की कीमत के समान बनाने के लिए अपनी बिक्री कीमत को घटा कर कम कर दिया है। साथ ही विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न रूप भिन्न कीमतों के हैं तथा औसत कीमत अथवा भारित औसत कीमत, भ्रामक छवि प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (17) मात्रा के रूप में घरेलू उद्योग की संवृद्धि सकारात्मक रही है, जबकि कीमत प्राचल के रूप में यह नकारात्मक है।
- (18) घरेलू उद्योग के कार्यों की स्थिति को देखते हुए, जहां विगत कुछ वर्षों से निरंतर पाटन होने के कारण उत्पाद संगत रूप से कार्य-निष्पादन नहीं कर रहा है, उसमें पर्याप्त नए निवेशों की कल्पना नहीं की जा सकती है। घरेलू उद्योग के पास पहले से ही अत्यधिक क्षमताएं विद्यमान हैं।
- (19) सिब्सडी-रोधी जांच में प्राधिकारी द्वारा विधि से परे क्षति रहित कीमत परिकलित की गई थी और उसके लिए वास्तविक क्षमता उपयोग के बजाय सामान्य कार्य के लिए अनुमानित क्षमता उपयोग को ध्यान में रखा गया था।
- (20) विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न प्रकार के उत्पाद निहित हैं जिनके कारण प्राधिकारी ने पीसीएन प्राप्त किया है। उत्पादन की लागत में उत्पादित उत्पाद की किस्म के साथ-साथ किए गए मशीन कार्य के अनुसार अंतर व्याप्त है। इस प्रकार घरेलू उद्योग के उत्पादन की औसत लागत भ्रामक है।
- (21) विचाराधीन उत्पाद गहन-श्रमिक प्रधान उत्पाद है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता के एक बहु-उत्पाद कंपनी होने और देश में स्थापित श्रम कानून को ध्यान में रखते हुए ये प्राचल पाटन के प्रतिकूल प्रभाव को नहीं दर्शा सकते हैं।
- (22) क्षति अवधि में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि में अदा की गई मजदूरी में विकट गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त क्षति अवधि में उत्पादन के प्रति यूनिट की मजदूरी लागत में अत्यधिक गिरावट आई है। यदि जांच अवधि के लिए आधार वर्ष में उत्पादन के प्रति यूनिट पर खर्च हुई मजदूरी लागत को ध्यान में रखा जाए, तो यह देखा जा सकता है कि जांच अवधि में घाटे बहुत अधिक हुए हैं।
- (23) याचिकादाता यह समझने में असमर्थ है कि निर्यातक द्वारा किस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। विगत घरेलू उद्योग, मेसर्स एलएंडटी एक बहु-उत्पाद कंपनी थी और उसके प्रस्तुत किए गए आंकड़े, कंपनी के कास्टिंग्स घटक को हुई क्षति की सही छवि नहीं दर्शाते हैं।
- (24) याचिकादाता ने कुछ भी नहीं छिपाया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी पहले इसकी जांच कर सकते हैं और उसके बाद इन आंकड़ों को अपना सकते हैं। घरेलू उद्योग ने अपनी सूचना का अंधाधुंध विश्वास करने की मांग नहीं की है।
- (25) निर्यातक द्वारा किया गया निवेदन गलत है क्योंकि जांच अवधि के दौरान संयंत्र बंद नहीं था। वर्ष 2013 में कानसबहाई यूनिट में केवल संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन बंद कर दिया गया था।
- (26) चीन पर लागू किए गए सीवीडी से घरेलू उद्योग को हो रही क्षति का पूर्णतया निदान नहीं हुआ है।
- (27) संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हो रही है। इस तर्क का कोई कानूनी आधार नहीं है कि चूंकि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों से भी क्षति हुई है, इसलिए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है। कारणात्मक संबंध से पहले शब्द "ए" (और न कि "दि") लगाए जाने का यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि जब तक कि पाटन, घरेलू उद्योग की क्षति का एक कारण बना रहता है, तब तक प्राधिकारी पाटन के कारण होने वाली क्षति का सकारात्मक जांच परिणाम दर्ज करेंगे।
- (28) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिज्ञात किए गए कारकों से यह स्थापित नहीं होता है कि ऐसे अन्य भी कारक हैं जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। साथ ही ऐसा प्रत्यक्ष साक्ष्य विद्यमान है कि पाटित आयातों के कारण बाजार में कीमत में गिरावट आई है।
- (29) वर्ष 2012-13 में विंड एनर्जी क्षेत्र में मंदी आई थी और न कि समस्त क्षति अवधि में तथा तीव्र अवमूल्यन और जनरेशन आधारित प्रोत्साहनों को समाप्त कर दिए जाने के कारण क्षति हुई थी, जिन्हें वर्ष 2012-13 में पहले से ही ध्यान में रखा गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

74. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को नोट कर लिया है। प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है।

75. अनुबंध-11 के साथ पठित पाटन-रोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो।

76. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि इसकी जांच की जाए कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत के साथ तुलना करने पर पाटित आयातों द्वारा कीमतों में अत्यधिक कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव अन्यथा कीमतों में अत्यधिक ह्रास कर रहे होते अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकते जो कि अन्यथा अत्यधिक सीमा तक हो गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निबल बिक्रियों की वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग को प्रभावित करने वाले सूचकों पर पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

77. इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाते समय जिस स्थिति पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, वह आदर्श दशाओं के परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि घरेलू उद्योग की विशिष्ट परिस्थितियां हैं।

78. क्षति नहीं होने के निवेदनों के संबंध में नीचे किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः स्पष्ट है, जिससे यह स्थापित होता है कि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

79. इसके अतिरिक्त कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टें जैसे सार्वजनिक विवरण, इस निष्कर्ष को परिवर्तित नहीं करते हैं कि उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

80. इस निवेदन के संबंध में कि पृथक विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार समग्र घरेलू उद्योग के लिए क्षति का निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है।

81. जांच की कार्रवाई के दौरान क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदनों की जांच की गई है और उनका समाधान किया गया है, जो कि निम्नानुसार है।

82. पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी को मात्रा और कीमत दोनों के प्रभाव की जांच करके क्षति की जांच करना अपेक्षित होता है। क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।

83. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख है:

"(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

84. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी प्राचल गिरावट दर्शाएं। कुछ प्राचल गिरावट दर्शा सकते हैं, जबकि अन्य कुछ प्राचल सुधार दर्शा सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी सभी क्षति प्राचलों पर विचार करते हैं और उसके बाद यह निष्कर्ष देते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा नहीं। प्राधिकारी ने निवेदनों में प्रस्तुत किए गए तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए सार्थक रूप से क्षति के प्राचलों की जांच की है।

मांग का मूल्यांकन

85. भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग का निर्धारण, भारतीय उत्पादकों और सभी स्रोतों से आयातों की बिक्रियों के योगफल के रूप में किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है।

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि (ए)
घरेलू उद्योग की बिक्रियां (सीएमयू+ केबीएल)	मी.टन	8,079	5,133	5,908	11,242
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	मी.टन	7,368	3,076	3,201	3,321

संबद्ध देश - आयात	मी.टन	15,117	10,430	13,751	17,941
अन्य देश - आयात	मी.टन	1,661	502	282	2,190
कुल मांग	मी.टन	32,225	19,141	23,142	34,693

86. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष से ले कर वर्ष 2012-13 तक विशेष क्षेत्र में मंदी होने के कारण संबद्ध वस्तुओं की मांग में गिरावट आई है, हालांकि कि समग्र क्षति अवधि में उसमें और अधिक गिरावट आई है।

पाटित आयातों की मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

87. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नानुसार निर्धारित है :-

"नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।"

(1) समग्र रूप से और सापेक्षिक रूप से आयात की मात्रा

88. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में पाटित आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों के अनुसार क्षति की जांच के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयात निम्नानुसार हैं:-

आयात - मात्रा	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि (ए)
चीन	मी.टन	15,117	10,430	13,751	17,941
अन्य देश	मी.टन	1,661	502	282	2,190
कुल आयात	मी.टन	16,778	10,932	14,033	20,131
संबद्ध देश से आयात					
खपत के संबंध में	%	47%	54%	59%	52%
उत्पादन के संबंध में	%	87%	121%	129%	116%
कुल आयातों के संबंध में	%	90%	95%	98%	89%

89. यह नोट किया जाता है कि :-

- (1) कुल आयातों के साथ-साथ संबद्ध देश से आयातों में मूल वर्ष से ले कर वर्ष 2012-13 में गिरावट आई है और उसके बाद जांच अवधि तक उसमें और अधिक गिरावट आई है।
- (2) खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयातों में मूल वर्ष से ले कर वर्ष 2013-14 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच अवधि में उसमें मामूली गिरावट आई है।
- (3) उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से आयातों में मूल वर्ष से ले कर वर्ष 2013-14 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच अवधि में उसमें मामूली गिरावट आई है।
- (4) आयातों के संबंध में संबद्ध देश से आयातों में मूल वर्ष से ले कर वर्ष 2013-14 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच अवधि में उसमें मामूली गिरावट आई है।

(2) बाजार का हिस्सा

90. यह देखा जा सकता है कि भारत में संबद्ध देशों से आयातों में मूल वर्ष से ले कर वर्ष 2012-13 तक गिरावट आई है और उसके बाद जांच अवधि में गिरावट में और अधिक वृद्धि हुई है।

91. संबद्ध देश की मांग में बाजार के हिस्से में मूल वर्ष से ले कर वर्ष 2013-14 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच अवधि में उसमें गिरावट आई है।

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि (ए)
घरेलू उद्योग की बिक्रियां (सीएमयू+ केबीएल)	मी.टन	8,079	5,133	5,908	11,242
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	मी.टन	7,368	3,076	3,201	3,321
संबद्ध देश - आयात	मी.टन	15,117	10,430	13,751	17,941
अन्य देश - आयात	मी.टन	1,661	502	282	2,190
कुल मांग	मी.टन	32,225	19,141	23,142	34,693
मांग में बाजार का हिस्सा					
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	%	25%	27%	26%	32%
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	%	23%	16%	14%	10%
संबद्ध देश	%	47%	54%	59%	52%
अन्य देश	%	5%	3%	1%	6%
कुल मांग	%	100%	100%	100%	100%

92. इसके अतिरिक्त जब तक आयातों की प्रतिस्पर्द्धा में और आयातों की तुलना में घरेलू उद्योग कीमतों को प्रभारित करता रहा है, घरेलू उद्योग को उत्पाद को बेचने में कोई समस्या अनुभव नहीं हुई है।

पाटित आयातों का कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर उसका प्रभाव

93. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-11 (ii) में निर्धारित प्रावधान निम्नानुसार है :-

“जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।”

94. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत के साथ तुलना करने पर पाटित आयातों द्वारा कीमतों में अत्यधिक कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव अन्यथा कीमतों में अत्यधिक ह्रास कर रहे होते अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकते जो कि अन्यथा अत्यधिक सीमा तक हो गई होती।

95. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत की तुलना, घरेलू उद्योग की निबल बिक्रियों की वसूली के साथ की है। इस संबंध में उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत, जो कि व्यापार के समस्त स्तर पर सभी छूटों और करों का निबल है, के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण, कारखाना-गत स्तर पर किया गया है।

96. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच, कीमत में कटौती होने, कम कीमत पर बिक्री होने, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण होने के संदर्भ में की गई है।

(1) पाटित आयातों के कीमत कटौती के प्रभाव

97. प्राधिकारी ने पीसीएन प्रणाली बनाई है (जैसा कि ऊपर भाग-1 में उल्लेख किया गया है), जिसका कि अलग-अलग लेन-देनों में शामिल उत्पाद किस्म की पहचान के लिए प्रयोग किया गया है। चूंकि आयात के पीसीएन मिश्र तथा घरेलू बिक्री के पीसीएन मिश्र भिन्न हैं, अतः कीमत कटौती के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए सभी आयातों और घरेलू बिक्री के औसत पर विचार किया गया है।

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि-क
आयातों की पहुंच कीमत	रूपए/मी.टन	94,417	115,838	123,971	121,024
निबल बिक्री कीमत (सीएमयू+ केबीएल)	रूपए/मी.टन	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रूपए/मी.टन	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	सीमा	50-60%	10-20%	0-10%	(20)-(10)%

(2) कीमत में कटौती

98. प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कम कीमत पर बिक्री करने से हुई क्षति की भी जांच की है। इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत की तुलना, प्रत्येक किस्म के उत्पाद के लिए आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है। आयातों की भारित औसत पहुंच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की भारित औसत क्षति रहित कीमत तुलना निम्नानुसार है:-

विवरण	रूपए/मी.टन	अमरीकी डालर/मी.टन
क्षति रहित कीमत (एनआईपी)	***	***
पहुंच कीमत	121,024	1,931
क्षति मार्जिन	***	***
क्षति मार्जिन-%	***	***
क्षति मार्जिन (सीमा)	15-25%	15-25%

(3) कीमतह्रास/कीमत न्यूनीकरण

99. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात, घरेलू कीमतों में ह्रास अथवा न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अत्यधिक ह्रास हो रहा है अथवा कीमतों में वृद्धि होने में रूकावट आ रही है, जो कि अन्यथा अत्यधिक सीमा तक हो जाती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों पर विचार किया है। इनकी स्थिति नीचे तालिका(सीएमयू+ केबीएल) में दर्शाई गई है:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि (ए)
बिक्रियों की लागत	रूपए/मी.टन	***	***	***	***
सूचकांक		100	114	94	70
बिक्री कीमत	रूपए/मी.टन	***	***	***	***
सूचकांक		100	88	88	71

100. यह देखा जाएगा कि -

- (1) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत दूसरे वर्ष में बढ़ी परंतु उसके बाद काफी घट गई।
- (2) संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत पूरी क्षति अवधि में कम हुई है।
- (3) बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत आधार वर्ष की तुलना में घटी है।

101. याचिकाकर्ता को अपनी कीमतों को लागत से बहुत कम करने पर विवश होना पड़ा है, जिसके फलस्वरूप उसकी कीमतों में ह्रास हुआ है और उसे अत्यधिक वित्तीय घाटे हुए हैं। संबद्ध वस्तुओं के आयात, घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक ह्रास और न्यूनीकरण कर रहे हैं। इस प्रकार पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक प्राचल

102. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-11 में ऐसी अपेक्षा है कि क्षति का निर्धारण करने में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की सार्थक जांच करना निहित होगा। इस संबंध में नियमावली में आगे की गई व्यवस्था निम्नानुसार है:-

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूचियां, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

103. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति प्राचलों का उल्लेख नीचे किया गया है।

(1) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

104. उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग (सीएनयू) का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार था:-

प्राचल	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि (क)
क्षमता	मी.टन	30,000	30,000	30,000	30,000
सूचीबद्ध		100	100	100	100
उत्पादन – विचाराधीन उत्पाद	मी.टन	9,923	5,574	7,434	12,157
सूचीबद्ध		100	56	75	123
उत्पादन – एनपीयूसी	मी.टन	3,382	2,982	343	757
सूचीबद्ध		100	88	10	22
कुल उत्पादन	मी.टन	7,907	8,556	7,778	12,914
सूचीबद्ध		100	108	98	163
क्षमता उपयोग	%	26%	29%	26%	43%
संयंत्र उपयोग	%	35%	22%	26%	43%
सूचीबद्ध		100	108	98	163
घरेलू बिक्रियां	मी.टन	8,079	5,133	5,908	11,242
मूल्यांकित मांग	मी.टन	32,225	19,141	23,142	34,693

105. उपरोक्त तालिका से निम्नानुसार नोट किया जाता है:-

- (1) घरेलू उद्योग के पास देश में वर्तमान और संभावित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता विद्यमान है।
- (2) विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में मूल वर्ष से वर्ष 2012-13 में गिरावट आई है और उसके बाद वर्ष 2013-14 और जांच अवधि में उसकी गिरावट में और वृद्धि हुई है।
- (3) देश में पर्याप्त मांग होने के बावजूद भी उत्पादन में गिरावट आई है।
- (4) घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्षमता उपयोग में मूल वर्ष से वर्ष 2012-13 में बहुत अधिक गिरावट आई है और जांच अवधि तक उसमें और अधिक गिरावट आई है।
- (5) घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वही प्रवृत्ति रही है, जो कि क्षमता उपयोग की रही है।

(2) मांग में बाजार का हिस्सा

106. घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से पर पाटित आयातोंके प्रभाव की जांच की गई है, जो कि निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)	जांच अवधि-क
मांग में बाजार का हिस्सा						
घरेलू उद्योग की विक्रियां (सीएमयू+ केवीएल)	%	25%	27%	26%	32%	32%
अन्य भारतीय उत्पादकों की विक्रियां	%	23%	16%	14%	10%	10%
संबद्ध देश	%	47%	54%	59%	52%	52%
अन्य देश	%	5%	3%	1%	6%	6%
कुल मांग	%	100%	100%	100%	100%	100%

107. यह नोट किया जाता है कि -

- (1) घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में मूल वर्ष से वर्ष 2012-13 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद वर्ष 2013-14 में गिरावट आई है और जांच अवधि में उसमें पुनः वृद्धि हुई है।
- (2) जब कि संबद्ध देश के बाजार के हिस्से में मूल वर्ष से वर्ष 2013-14 तक वृद्धि हुई है और जांच अवधि में उसमें गिरावट आई है।
- (3) इस अवधि को दौरान भारतीय उत्पादकों के बाजार के हिस्से में अत्यधिक गिरावट आई है।
- (4) इसके अतिरिक्त अन्य देशों के बाजार के हिस्से में मूल वर्ष से वर्ष 2013-14 तक गिरावट आई है और जांच अवधि में उसमें वृद्धि हुई है।

(3) लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी लाभ

108. घरेलू उद्योग (सीएमयू) के लाभ/घाटे, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ का विश्लेषण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

लाभ/(घाटा)	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि- क
लाभ/(घाटा)	लाख रूपए	***	***	***	***
सूचकांक		-100	-745	-265	-76
नकदी लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***
सूचकांक		100	-170	24	93
पीवीआईटी	लाख रूपए	***	***	***	***
सूचकांक		-100	-757	-264	-75
आरओसीई एनएफए	%	***	***	***	***
सूचकांक		-100	-1,119	-501	-151

109. घरेलू उद्योग को पूरी क्षति अवधि में हानियां हुई हैं, यद्यपि, 2013-14 और जांच की अवधि के दौरान उसे नकद लाभ हुए हैं। सभी मानदंड 2012-13 के दौरान सबसे बदतर निष्पादन दर्शाते हैं जिनमें बाद में सुधार हुआ है, यद्यपि, समग्र निष्पादन नकारात्मक है।

(4) रोजगार और वेतन

110. रोजगार, वेतन और उत्पादकता से संबंधित (सीएमयूकी) स्थिति निम्नानुसार है:-

प्राचल	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि(क)
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***

सूचकांक		100	100	105	108
वेतन	लाख रुपए	***	***	***	***
सूचकांक		100	70	43	45

111. यह नोट किया जाता है कि समस्त क्षति अवधि में घरेलू उद्योग (केवल सीएमयू यूनिट पर विचार करते हुए) के रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई है, जबकि समस्त क्षति अवधि में वेतन में गिरावट आई है।

(5) मालसूची

112. क्षति अवधि के दौरान मालसूची शून्य रही है। संबद्ध सामान "ऑर्डर पर निर्माण" उत्पाद हैं। इस प्रकार मालसूची का मानदंड इस मामले में क्षति का मूल्यांकन करने के लिए समुचित मानदंड नहीं है।

(6) संवृद्धि

वर्ष दर वर्ष संवृद्धि	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)	जांच अवधि*
उत्पादन - विचाराधीन उत्पाद	%	-	-29%	33%	42%	42%
घरेलू बिक्रियों की मात्रा	%	-	-36%	15%	60%	60%
बिक्रियों/यूनिट की लागत	%	-	14%	-18%	-17%	-17%
बिक्री कीमत/यूनिट	%	-	-12%	0%	-13%	-13%
लाभ/घाटा/यूनिट	%	-	1073%	-69%	-56%	-56%
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	-	-16%	10%	5%	5%

113. देश में इस उत्पाद की बढ़ती हुई मांग से मात्रा की दृष्टि से घरेलू उद्योग की वृद्धि 2012-13 के बाद सकारात्मक रही है जबकि कीमत मानदंड की दृष्टि से वृद्धि नकारात्मक थी। आर ओ सी ई में वृद्धि के मानदंड यद्यपि, 2013-14 से सुधार दर्शाते हैं, तथापि यह नोट किया जाता है कि आरओसीई पूरी क्षति अवधि में नकारात्मक थी।

(7) पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता

114. घरेलू उद्योग के पास पहले से ही अत्यधिक क्षमताएं विद्यमान हैं। निरंतर निष्पादन नहीं होने की स्थिति में पर्याप्त नए निवेश की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।

(8) पाटन का स्तर और पाटन मार्जिन

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है, बल्कि यह बहुत अधिक भी है। घरेलू उद्योग पर पाटन का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है।

(9) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

116. संबद्ध देश से आयात कीमतों की जांच करने, लागत ढांचे में परिवर्तन होने, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा होने, पाटित आयातों से भिन्न कारक जो कि घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, आदि से यह पता चलता है कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से कम है, जिसके कारण भारतीय बाजार में अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री की जा रही है। इस प्रकार घरेलू कीमतों को प्रभावित करने का कारक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य है।

(10) कारणात्मक संबंध

117. प्राधिकारी ने पाटन और घरेलू उद्योग की आर्थिक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करने के लिए पाटन-रोधी नियमावली में सूचीबद्ध ऐसे अन्य कारकों की भी जांच की है, जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

1. तृतीय देशों से आयात

118. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त संबद्ध वस्तुओं के आयातों के आंकड़ों की जांच की है। वर्तमान परिदृश्य में आयात हांगकांग से हो रहे हैं।

II. मांग में संकुचन

119. वर्ष 2012-13 के बाद से क्षति अवधि में संबद्ध उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। मांग में संभावित गिरावट आने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

III. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

120. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए खपत के पैटर्न में परिवर्तन, घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

IV. व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धतियां तथा विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

121. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धति नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

V. प्रोद्योगिकी में विकास

122. उत्पाद के उत्पादन की प्रोद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए प्रोद्योगिकी में विकास क्षति का एक कारक नहीं है।

VI. निर्यात निष्पादन

123. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकादाता ने विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया है। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा क्षति होने के दावे का कारण निर्यात नहीं है।

VII. उत्पाद का सहायिकीकरण

124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन सरकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले से ही संबद्ध वस्तुओं पर सब्सिडी-रोधी/प्रतिकारी शुल्क लगाया हुआ है।

VIII. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन ने प्राधिकारी द्वारा किए गए घरेलू उद्योग के निष्पादन के मूल्यांकन को प्रभावित नहीं किया है। प्राधिकारी द्वारा केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना पर ही विचार किया गया है। घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद पर क्षति होने का दावा किया है।

(11) कारणात्मक संबंध को सिद्ध करने वाले कारक

126. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन के विश्लेषण से यह पता चलता है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में वास्तविक रूप से गिरावट आई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग के बीच कारणात्मक संबंध होने की संपुष्टि निम्नोक्त आधार पर होती है:-

- (1) घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों द्वारा पेश की गई कीमतों के बीच अत्यधिक अंतर है। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को मात्रात्मक क्षति हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग अपने उत्पादन और बिक्रियों को अनुकूलतम स्तर तक नहीं ले जा सका है।
- (2) इसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग पर्याप्त बिक्रियों की मात्राओं को प्राप्त नहीं कर सका है। इस प्रकार भारत में मांग होने के बावजूद इसके परिणाम स्वरूप अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सका है, जो कि संबद्ध देश से पाटित आयातों का प्रत्यक्ष परिणाम है।
- (3) आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद की कीमतों को कम करने और ऐसी कीमत पर बेचने के लिए विवश होना पड़ा है, जिस पर उसे अत्यधिक वित्तीय घाटे हो रहे हैं।
- (4) नियोजित पूंजी पर नकारात्मक लाभ और प्रतिलाभ, पाटित आयातों का प्रत्यक्ष परिणाम है।
- (5) घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्रियां और क्षमता उपयोग, पहले प्राप्त किए गए स्तरों से अत्यधिक कम हैं।
- (6) आयातों में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग का स्टॉक अत्यधिक जमा हो रहा है। घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करने के बावजूद भी जमा स्टॉक को परिसमाप्त करने में असमर्थ है।
- (7) प्राचलों की संख्या के संबंध में घरेलू उद्योग की संवृद्धि नकारात्मक हो गई है।

क्षति मार्जिन की मात्रा

127. जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत की तुलना, संबद्ध देश से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:-

क्षति मार्जिन तालिका						
क्रमांक	उत्पादक	निर्यातक	क्षति रहित कीमत अम.डा./मी.ट.	पहुंच कीमत अम.डा./मी.ट.	क्षति मार्जिन अम.डा./मी.ट.	क्षति मार्जिन %
1.	डालियान हुआरुई हैवी इंडस्ट्री कास्टिंग कंपनी लिमिटेड	डालियान हुआरुई हैवी इंडस्ट्री कास्टिंग कंपनी लिमिटेड	***	***	***	15-25
2.	झेन्नियांग जिआली विंड पावर टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड	झेन्नियांग जिआली विंड पावर टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	5-15
3.	जिआंगसू सिनाजीत विंड एनर्जी टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड <ul style="list-style-type: none"> चांगझाऊ सिनाजीत विंड एनर्जी टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड जिआंगिन हेंगुआ मशीनरी कंपनी लिमिटेड, जिआंगिन सिटी जिआंगिन क्युक्सिंग टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड, जिआंगिन सिटी जिआंगिन चांगलिंग न्यू एनर्जी कंपनी लिमिटेड, बूक्सी सिटी, जिआंगसू 	<ul style="list-style-type: none"> जिआंगसू सिनाजीत विंड एनर्जी टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड टेक्टोन एचके, लिमिटेड 	***	***	***	10-20
4.	<ul style="list-style-type: none"> नानटोंग होंगडे मेकेनिकल कंपनी लिमिटेड कोईजुमी मशीनरी कंपनी लिमिटेड 	नानटोंग होंगडे मेकेनिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	15-25
5.	जिआंगसू फाब फाउंडरी कंपनी लिमिटेड	जिआंगसू फाब फाउंडरी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	25-35
6.	जिआंग गुआन एनर्जी टेक्निकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड <ul style="list-style-type: none"> डोंगगुआन जिआंग गुआन मोल्ड फैक्टरी कंपनी लिमिटेड जिआंगसू ब्राइट स्टील फाईन मशीनरी कंपनी 	जिआंग गुआन एनर्जी टेक्निकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड	***	***	***	15-25

	लिमिटेड ➤ निंगबो लू लिन मशीन टूल फाउंडरी कंपनी लिमिटेड ➤ निंगबो जिऑंग शांग कास्टिंग ऑयरन कंपनी लिमिटेड ➤ जिऑंग घेन एशिया पेसिफिक कंपनी लिमिटेड					
	शेष अन्य		***	***	***	35-45

प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

128. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) प्राधिकारीऐसी कार्य-प्रणाली के विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, जिसके आधार पर प्रकटन विवरण में निर्यात कीमत स्थापित की गई है। प्राधिकारी ने प्रदत्त सूचना के अनुसार कुछ समायोजन किए हैं। प्राधिकारी को प्रत्येक आपूर्ति श्रृंखला के पृथक ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए और प्रत्येक आपूर्ति श्रृंखला के लिए निर्यात की गई कीमत के तरीके को दर्ज किया जाना चाहिए।
- (2) प्रतिवादी द्वारा संबद्ध वस्तुओं के निर्यात से संबंधित आपूर्ति श्रृंखला को गलत ढंग से पाटन मार्जिन तालिका में दर्ज किया गया है और प्रकटन विवरण में क्षति मार्जिन दर्शाया गया है। नानडोंग एक उत्पादक और निर्यातक है। नानडोंग होंगडे ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और भारत को उनका निर्यात किया है। कोईजुमी भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में लिप्त नहीं है और वह केवल तैयार उत्पाद में नानडोंग होंगडे के लिए अर्ध-तैयार उत्पाद की प्रक्रिया में शामिल था। विशेषकर कोईजुमी ने नानडोंग होंगडे के साथ उत्पादन में सहयोग देने का करार किया है।
- (3) परिकलित किया गया पाटन-रोधी मार्जिन, लागू प्रतिकारी शुल्क के लिए समायोजन पर आधारित होना चाहिए।
- (4) जिआंग गुआन ग्रुप ने एमईटी के दावे के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है/सूचना प्रदान की है। प्राधिकारी ने प्रदत्त की गई सूचना और दस्तावेज/साक्ष्यों का खंडन नहीं किया है/पर आपत्ति नहीं की है। अनुबंध-1 के पैरा 8 (3) के उप-पैरा (क) से (घ) में विनिश्चित मानदंड के संबंध में किए गए निवेदनों के खिलाफ चीन जनवादी गणराज्य के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के संबंध में प्रकटन विवरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कोई आपत्ति/खंडन नहीं किए जाने की स्थिति में यह बहुत गलत है और मानी गई एनएमई की अवधारणा विधि में और मामले के तथ्यों के अनुसार वैधता के लिए मान्य नहीं है।
- (5) विचाराधीन उत्पाद के दायरे को घरेलू उद्योग के अनुरोध से भी आगे बढ़ा दिया गया है। एलएंडटी ने चीन जनवादी गणराज्य से "विंड आपरेटिड इलेक्ट्रीसिटी जेनेरेटर की कास्टिंग्स" के आयात के खिलाफ जांच शुरू करने की मांग की थी। तथापि, "विंड आपरेटिड इलेक्ट्रीसिटी जेनेरेटर्स की कास्टिंग्स, चाहे वह मशीनकृत है अथवा नहीं, अपरिष्कृत है अथवा तैयार है या सब-असेम्बल्ड रूप में है अथवा सब-असेम्बली के एक भाग के रूप में है या विंड आपरेटिड इलेक्ट्रीसिटी जेनेरेटर्स के निमित्त एक उपस्कर/संघटक के रूप में है" के खिलाफ वर्तमान जांच शुरू कर दी गई है। प्राधिकारी के लिए यह उपयुक्त नहीं है कि वे स्वप्रेरणा से बिना कोई सही कारण बताए विचाराधीन उत्पाद में उपांगों को शामिल करने के लिए उसके दायरे को संशोधित कर दें। इस प्रकार कोई विनिश्चित औचित्य बताए बिना विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बढ़ा दिया गया है।
- (6) जबकि अब एलएंडटी घरेलू उद्योग नहीं रहा है और इसलिए यह जांच सही नहीं है। वर्तमान जांच शुरू होने के समय कोयम्बटूर यूनिट को ब्राडकेन इंडिया को बेचे जाने के निर्णय के अनुसरण में वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ एलएंडटी घरेलू उद्योग नहीं रहा है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्तमान याचिका को बनाए रखे जाने के लिए किए गए निवेदनों की अनदेखी करके तथा यह मानते हुए कि एलएंडटी और ब्राडकेन इंडिया दोनों ही वर्तमान मामले में याचिकादाता बनते हैं, बहुत विकट गलती की है।

- (7) याचिकादाता भारत में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करने के लिए फोरम शॉपिंग करने का एक ऐसा रास्ता अपना रहा है, जो कि व्यापार-रोधी, उपभोक्ता-रोधी और प्रतिस्पर्द्धा-रोधी है। सीवीडी जांच के परिणामों की प्रतीक्षा किए बिना याचिका दायर की गई है, जिससे याचिकादाता की बैचेनी और विचाराधीन उत्पाद के उच्च कोटि के आयातों से तुरत छुटकारा प्राप्त करने और प्रतिस्पर्द्धा समाप्त करने का स्पष्ट पता चलता है। सीवीडी के लिए उपयुक्त समय देने के बजाय क्षति के प्रभाव को दर्शाया जा रहा है।
- (8) याचिकादाता ने 40% क्षति मार्जिन का दावा किया है, जो कि 10% के मार्जिन की तुलना में बहुत अवास्तविक प्रतीत होता है, जिस पर सीवीडी लागू किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान जांच में जांच अवधि, सीवीडी लागू करने से पहले की है, फिर भी इतने कम समय में क्षति मार्जिन में 30% की वृद्धि होने का दावा किया गया है। इस प्रकार याचिकादाता ने फोरम शॉपिंग करने का रास्ता अपनाया है और वह प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करने के लिए गलत और भ्रामक आंकड़ों पर क्षति होने का दावा कर रहा है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में किए गए ऐसे निवेदनों की पूर्णतया अनदेखी की है।
- (9) एलएंडटी द्वारा कोयम्बटूर यूनिट को ब्राडकेन इंडिया को बेचे जाने संबंधी सूचना को छिपाया गया है।
- (10) घरेलू उद्योग को जांच अवधि में कोई क्षति नहीं हुई है और विभिन्न आर्थिक प्राचलों पर प्राधिकारी के प्रेक्षण, प्रकटन विवरण में मांग, पूर्णरूपेण आयातों, कीमत हास/कीमत न्यूनीकरण के रूप में निर्दिष्ट किए गए रिकार्ड के सामने पूर्णतया विपरीत हैं।
- (11) आर्थिक क्षति होने, आरोपित पटित आयातों के कारण एलएंडटी को आर्थिक क्षति होने अथवा सामग्री में मंदी होने का खतरा सिद्ध नहीं हुआ है। जांच अवधि में याचिकादाता उत्पादन, बाजार के हिस्से, बिक्री में प्रोन्नति होने की प्रवृत्ति दर्शा रहा है और जबकि क्षमता उपयोग 41% दर्शाया गया है, जो कि उद्योग में मंदी आने का एक सूचक नहीं है।
- (12) जिआंगसू सिनोजीत विंड एनर्जी टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड और नानटोंग होंगडे मेकेनिकल कंपनी लिमिटेड की आपूर्ति श्रृंखला के संबंध में हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे जांच अवधि के दौरान उनके निर्यातों के मूल्य, पाटन मार्जिन के लिए दर्ज की गई निर्यात कीमत और क्षति मार्जिन के लिए यथा दर्ज पहुंच कीमत, पाटन मार्जिन और पाटन मार्जिन परिकलन का आधार के ब्यौरे प्रदान करें और यह बताएं कि क्या उत्पाद के आरेखन भार, तैयार भार अथवा गैर-तैयार भार पर विचार किया गया है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

129. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद का निर्धारण, "विंड आपरेटर इलेक्ट्रीसिटी जेनेरेटर्स की कास्टिंग्स, जिसे विंडमिल्स अथवा विंड टर्बाईन्स के लिए चाहे वह मशीनकृत है अथवा नहीं, अपरिष्कृत है अथवा तैयार है या सब-असेम्बलड रूप में है अथवा एक सब-असेम्बली के एक भाग के रूप में है या विंड आपरेटर इलेक्ट्रीसिटी जेनेरेटर्स के निमित्त एक उपस्कर/संघटक के रूप में है, के लिए कास्टिंग्स के रूप में भी जाना जाता है" के रूप में किया गया है।
- (2) उचित तुलना को सुकर बनाने के लिए प्राधिकारी द्वारा पीसीएन बनाया गया है और उसे पुनःवर्गीकृत और सुव्यवस्थित किया गया है। याचिकादाता को ऐसे पुनःवर्गीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है। यह स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है कि याचिकादाता ने गैर-तैयार किए गए रूप में उत्पाद को बेचा है, जबकि उत्पाद को तैयार रूप में आयात किया गया है।
- (3) उत्पादों के भार की एक समान आधार पर विचार किए जाने की आवश्यकता है ताकि क्षति मार्जिन के प्रयोजनार्थ अलग-अलग वस्तु की ठीक ढंग से तुलना की जा सके। घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत में तैयार उत्पाद की लागत को जोड़ना मात्र इस प्रयोजनार्थ अपर्याप्त होगा। सहयोजित भार को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है।
- (4) चूंकि सीमा-शुल्क का वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया शुल्क तालिका में यह विनिश्चित कर सकते हैं कि विचाराधीन उत्पाद पर सीमा-शुल्क के ऐसे वर्गीकरण की ओर ध्यान दिए बिना शुल्क लागू होना चाहिए, जिसके अंतर्गत आयातकों द्वारा वस्तुओं की क्लीयर करवाया जा रहा है और सीमा-शुल्क का वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है।
- (5) प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित किए गए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से अत्यधिक कम है।

- (6) कृपया शुल्क सम-मूल्य के आधार पर लगाया जाए क्योंकि ऐसे अनेक विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं, जिनकी सहयोजित कीमतों में अत्यधिक अंतर व्याप्त है।
- (7) विचाराधीन उत्पाद पर सब्सिडी-रोधी/प्रतिकारी शुल्क पहले से ही लागू है। तदनुसार वर्तमान जांच के अनुसार संबद्ध वस्तुओं देय पाटन-रोधी शुल्क पहले से ही लागू सीवीडी के अध्यक्षीन हो सकता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

130. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात निवेदनों को नोट कर लिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिकतर निवेदन पुनरावर्ती प्रकृति के हैं और इनकी पहले से ही जांच कर ली गई है तथा उपयुक्त निदान इन अंतिम जांच परिणाम में कर लिया गया है।

131. चूंकि कुछ सूचना के व्यवसाय संवेदी होने के कारण हितबद्ध पक्षकारों की गोपनीय सूचना है, इसलिए निर्यात कीमत में समायोजन करने से संबंधित निवेदनों के बारे में उल्लेखनीय है कि प्राधिकारी ऐसी सूचना को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकटन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। तथापि, जहां कहीं भी अनुरोध किया गया है, निर्यात कीमत और पहुंच मूल्यों के गोपनीय कार्यचालन के बारे में निर्याताकों को बताया गया है।

132. नानटोंग होंगडे और कोईजूमी से संबंधी आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित निवेदनों के बारे में उल्लेखनीय है कि प्राधिकारी ने उनको नोट कर लिया है।

133. पाटन-रोधी शुल्क में सीवीडी का समायोजन करने से संबंधित निवेदनों के बारे में उल्लेखनीय है कि प्राधिकारी द्वारा इस पर पहले से ही विचार कर लिया गया है।

134. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित किए गए मार्जिन से अत्यधिक कम होने से संबंधित निवेदनों के बारे में उल्लेखनीय है कि प्राधिकारी ने दिनांक 17 जुलाई, 2017 के पत्र द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को यह स्पष्ट करने का आग्रह किया है कि वे यह स्पष्ट बताएं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सूचित भार, तैयार कास्टिंग्स अथवा तैयार कास्टिंग्स का अपरिष्कृत भार है। इसके अतिरिक्त यदि हितबद्ध पक्षकार ने तैयार कास्टिंग्स का भार सूचित किया है, तो वे तैयार कास्टिंग्स के अपरिष्कृत भार अर्थात् तैयार नहीं किए गए कास्टिंग्स के भार को सूचित करें।

135. प्राधिकारी द्वारा किए गए कार्यचालन और परिकलन की दुबारा जांच करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सत्यापित आंकड़ों के समनुरूप कार्य कर रहे हैं, इस उपाय का उपयोग किया गया है।

136. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक द्वारा पैकिंग सूची में भार दर्शाने के आधार और घरेलू उद्योग के बीजक कुल मिलाकर समान हैं। निर्यातकों द्वारा दावा किए गए भार में परिवर्तन करना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि उसे पैकिंग सूची से विधिवत रूप से सत्यापित किया गया है तथा सीमाशुल्क प्राधिकारी के समक्ष घोषित किया गया है।

भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

137. प्राधिकारी इस बात को मानते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद की कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटन-रोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटन-रोधी उपाय करने से पाटन की पद्धतियों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुचित प्रक्रिया समाप्त होगी, घरेलू उद्योग में होने वाली गिरावट रूकेगी तथा उपभोक्ताओं की व्यापक पसंद की संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। पाटन-रोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्यतया पाटन की अनुचित व्यावहारिक पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में ऐसा खुला और उचित प्रतिस्पर्द्धा वातावरण बहाल किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में हो। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने से किसी भी तरह से उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी उपाय लागू करने से किसी भी तरह से ईरान से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए ये उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेंगे। उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो अथवा उससे अधिक स्रोतों को बनाए रख सकते हैं।

सिफारिशें

138. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:-

- (क) भारत को संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात, सामान्य मूल्यों से कम पर किया जा रहा है।
- (ख) संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।
- (ग) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई थी और इसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई थी तथा निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सार्थक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू की गई थी और उसका संचालन किया गया था तथा सार्थक पाटन मार्जिन के साथ-साथ ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि हो जाने पर, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और क्षति के प्रतिकरण के लिए पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं कि नीचे वर्णित रूप में और तरीके से चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाए।

140. चूंकि विचाराधीन उत्पाद पर केन्द्रीय सरकार की अन्य अधिसूचनाओं के अंतर्गत सब्सिडी-रोधी/प्रतिकारी शुल्क पहले से ही लागू है, इसलिए प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम मार्जिन के बराबर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार चीन के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नीचे तालिका के कालम 8 में निर्दिष्ट राशि के अनुसार परिकलित पाटन-रोधी शुल्क की मात्रा और पहले से ही देय सब्सिडी-रोधी/प्रतिकारी शुल्क के बीच के अंतर की राशि का शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. मां. क.	उप-शीर्ष अथवा टैरिफ की मद	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि पहुंच मूल्य के प्रतिशत के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	प्रशुल्क शीर्षक अर्थात् अध्याय 84 और 85 में 8483400, 8503009, 85030010 के अंतर्गत	"पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स, चाहे वह उप व्यवस्था के भाग के रूप में अथवा पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स के उद्देश्य से एक उपकरण/संघटक का एक भाग के रूप में कच्चे, तैयार अथवा उप व्यवस्थित रूप में मशीन किया गया हो अथवा न किया गया हो, के लिए कास्टिंग"	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	डालियान हुआरूई हैवी इंस्ट्री कास्टिंग कंपनी लिमिटेड	डालियान हुआरूई हैवी इंस्ट्री कास्टिंग कंपनी लिमिटेड	18.48
2.			चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	झेन्नियांग जिआली विंड पावर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	झेन्नियांग जिआली विंड पावर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	6.27
3.			चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	जिआंगसू सिनाजीत विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ➤ चांगझाऊ सिनाजीत विंड	जिआंगसू सिनाजीत विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड टेकटोन एचके, लिमिटेड	14.44

					<p>एनर्जी टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड</p> <p>➤ जिआंगिन हेंगुआ मशीनरी कंपनी लिमिटेड, जिआंगिन सिटी</p> <p>➤ जिआंगिन क्युक्सिंग टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड, जिआंगिन सिटी</p> <p>➤ जिआंगिन चांगलिंग न्यू एनर्जी कंपनी लिमिटेड, वूक्सी सिटी, जिआंगसू</p>		
4.			चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	<p>➤ नानटोंग होंगडे मेकेनिकल कंपनी लिमिटेड</p> <p>➤ कोईजुमी मशीनरी कंपनी लिमिटेड</p>	नानटोंग होंगडे मेकेनिकल कंपनी लिमिटेड	18.64
5.			चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	जिआंगसू फाब फाउंडरी कंपनी लिमिटेड	जिआंगसू फाब फाउंडरी कंपनी लिमिटेड	28.83
6.			चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	<p>जिआंग गुआन एनर्जी टेक्निकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड</p> <p>➤ डोंगगुआन जिआंग गुआन मोल्ड फैक्टरी कंपनी लिमिटेड</p> <p>➤ जिआंगसू ब्राइट स्टील फाईन मशीनरी कंपनी लिमिटेड</p> <p>➤ निंगबो लू लिन मशीन टूल फाउंडरी कंपनी लिमिटेड</p> <p>➤ निंगबो येओंग शांग कास्टिंग ऑयरन कंपनी लिमिटेड</p> <p>➤ येओंग चैन एशिया</p>	<p>निंगबो येओंग शांग कास्टिंग ऑयरन कंपनी लिमिटेड</p> <p>येओंग चैन एशिया पैसिफिक कंपनी लिमिटेड</p>	15.46

					पेसिफिक कंपनी लिमिटेड		
7.			चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	क्रमांक 1 से 6 तक का कोई भी संयोजन		35.92
8.			चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	कोई	35.92
9.			कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	35.92

टिप्पणियां:-

- (1) वर्तमान अधिसूचना के प्रयोजनार्थ हवा से प्रचालित विद्युतीय जेनेरेटर्स का अभिप्राय "विंड आपरेटिड इलेक्ट्रीसिटी जेनेरेटर्स की कास्टिंग्स, जिसे विंडमिल्स अथवा विंड टर्बाईन्स के लिए चाहे वह मशीनकृत है अथवा नहीं, अपरिष्कृत है अथवा तैयार है या सब-असेम्बल्ड रूप में है अथवा सब-असेम्बली के एक भाग के रूप में है या विंड आपरेटिड इलेक्ट्रीसिटी जेनेरेटर्स के निमित्त एक उपस्कर/संघटक के रूप में है, के लिए कास्टिंग्स के रूप में भी जाना जाता है"से है।
- (2) सीमा-शुल्क विभाग की दिनांक 19 जनवरी, 2016 की सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या 1/2016-सीमा-शुल्क (सीवीडी) द्वारा "विंड आपरेटिड इलेक्ट्रीसिटी जेनेरेटर्स की कास्टिंग्स, चाहे वह मशीनकृत है अथवा नहीं, अपरिष्कृत है अथवा तैयार है या सब-असेम्बल्ड रूप में है अथवा एक सब-असेम्बली के एक भाग के रूप में है या विंड आपरेटिड इलेक्ट्रीसिटी जेनेरेटर्स के निमित्त एक उपस्कर/संघटक के रूप में है" परसब्सिडी-रोधी/प्रतिकारी शुल्क पहले से ही लागू है।

141. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) द्वारा यथा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और उसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3 क, 3 ख, 9 और 9 क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़ कर सभी सीमा शुल्क शामिल होंगे।

142. इसअंतिम निर्णय के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकारकेआदेशकेविरुद्धकोईभी अपील सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) केसमक्ष दायर कीजाएगी।

डा. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2017

(FINAL FINDINGS)

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Castings for Wind Operated Electricity Generators, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators", originating in or exported from China PR.

F. No. 14/28/2013-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. Background of the case

2. WHEREAS, M/s Larsen & Toubro Limited (hereinafter also referred to as the petitioner) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and the Rules, for initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of "Castings for

Wind Operated Electricity Generators, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators” (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country), alleging dumping and consequent injury and requested for levy of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the above subject country. M/s. Patel Alloys Steels P Limited (hereinafter referred to as “Patel Alloys”) has supported the petition.

3. And whereas, the Authority on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 14/28/2013-DGAD dated 1st, Feb 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating this Anti-Dumping investigations concerning import of the subject goods, originating in or exported from the above country, in accordance with the Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry, if any.

4. M/s Bradken India Pvt. Ltd. has purchased the manufacturing facilities of the subject goods at Coimbatore from M/s Larsen Toubro Ltd. on 3rd March 2016 as an ongoing concern and impleaded to be the petitioner in the present investigation. The relevant documents have been placed in the public file for inspection of the interested parties.

B. GENERAL PROCEDURE

5. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to this subject investigation:

- i. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application from the domestic industry requesting for initiation of an antidumping investigation before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule 5 of Rule 5 supra.
- ii. The Embassies/representatives of the subject country in New Delhi were also informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2).
- iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicants available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
- iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
- v. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from China to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from China PR.
- vi. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. Beijing Belying Foundry Co., Ltd.
 - b. Beijing Global Technotrade Group (BGTG)
 - c. Changzhou Shuangye Machinery & Electric Co., Ltd.
 - d. Changzhou Sinojit Wind Energy Tech Co Ltd., China PR,
 - e. CSR Sifang Co., Ltd.
 - f. Dalian Bingshan Group Refrigerating Equipment Co., Ltd.
 - g. Dalian Huarui Heavy Industry Steel casting Co. Ltd.

-
- h. Dalian Huarai Heavy Industry Casting Co. Ltd.
 - i. Dalian Huarui Heavy Industry International Co., Ltd.
 - j. Dalian Huarui Heavy Industry Steel Casting Joint-stock Co., Ltd.
 - k. Dingzhou Dongfang Foundry Co., Ltd.
 - l. Gexpro Industry Supply Shanghai Co., Ltd.
 - m. Guangzhou Hyenergy Co., Ltd.
 - n. Hydra Grene Hydraulics Equipment Accessory (Tianjin) Co. Ltd.
 - o. Jiangyin Fengdian Flange Manufacture Co., Ltd.
 - p. Jiangsu Jixin Wind Energy Technology Co., Ltd.
 - q. Jiangsu Wenhui Seel Engineering Co., Ltd.
 - r. Jiangsu Faw Foundry Co., Ltd.
 - s. Jinan Double Win Unity Manufacturing Technology Co., Ltd.
 - t. Liyan Flying Industry Co., Ltd.
 - u. Jiangyin Hengrun Ring Forging Co., Ltd.
 - v. Nanjing Yisuman Industrial & Trading Co., Ltd.
 - w. Nantong Hongde Mechanical Co., Ltd.
 - x. Ningbo Ginlong Technologies Co., Ltd.
 - y. Ningbo Saivs Machinery Co., Ltd.
 - z. Qingdao Aeolos Wing Energy Co., Ltd.
 - aa. Qingdao Anhua New Energy Equipment Co., Ltd.
 - bb. Qingdao R.H.S International Trading Co., Ltd.
 - cc. Qingdao Richuari Precision Machinery Co., Ltd.
 - dd. Shaanxi Qinchuan Machinery Import & Export Co., Ltd.
 - ee. Satarem China Co. Ltd.
 - ff. Shenzhen Shengxin Trading Co., Ltd.
 - gg. Shandong LaiwuJinlei Wind-Power Technology Co., Ltd.
 - hh. Shanghai Silic E&A International Trade Co., Ltd.
 - ii. Shanghai Zhong Zhu Import & Export Co., Ltd.
 - jj. Shenyang Huali Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd.
 - kk. Shenzhen Hejia Trading Co., Ltd.
 - ll. Qingdao Sinotrans Bounded Warehousing Logistics Co., Ltd.
 - mm. Shi Jia Zhuang Danzhuo Trade Co., Ltd.

- nn. Sinovel Wind Group Co., Ltd.
- oo. Tianjin Kailong Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd.
- pp. Tianjin Municipal Highway Facilities Engineering Co., Ltd.
- qq. Techtone (HK) Energy Technology Co. Ltd., China PR,
- rr. Wafangdian Mos-Wrc Bearing Manufacturing Co., Ltd.
- ss. Wenzhou Kaicheng Foundry Co., Ltd.
- tt. Wuzi Techance Steel Structure Construction Co., Ltd.
- uu. Yeong Guan Energy Tech. Group- Jiangsu Bright Steel Fine Machinery Co., Ltd., China PR,
- vv. Yeong Guan Energy Tech. Group- Dongguan Yeong Guan Mould Factory, China PR,
- ww. Yeong Guan Energy Tech. Group- Yeong Ghen Asia Pacific Co., Ltd. Ltd., China PR,
- xx. Yeong Guan Energy Tech. Group- Ningbo Lu Lin Machine Tool Foundry Co. ,Ltd, China PR,
- yy. Yeong Guan Energy Tech. Group- Ningbo Yeong Shang Casting Iron Go., Ltd., China PR
- zz. Zhuzhou Times New Material Technology Co., Ltd.
- aaa. Zhuzhou Jiabang Photoelectric Material Co., Ltd.
- bbb. Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co., Ltd.

vii. The following producers/exporters from the subject country filed exporter's questionnaire response in the prescribed format:

- a. Dalian Huarui Heavy Industry Casting Co. Ltd.
- b. Jiangsu Faw Foundry Co., Ltd.
- c. Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd.
- d. Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co., Ltd
- Changzhou Sinojit Wind Energy Tech. Co. Ltd
- Jiangyin Henghua Machinery Co., Ltd. Jiangyin City
- Jiangyin Qixing Technology Co., Ltd. Jiangyin City
- Jiangyin Changling New Energy Co., Ltd. Wuxi City, Jiangsu
- Techtone HK, Ltd
- e. Nantong Hongde Mechanical Co. Ltd. & KOIZUMI Machinery Co. Ltd.
- f. Yeong Guan Energy Tech. Group Company Limited
- Dongguan Yeong Guan Mould Factory Co., Ltd.
- Jiangsu Bright Steel Fine Machinery Co., Ltd
- Ningbo Lu Lin Machine Tool Foundry Co. ,Ltd
- Ningbo Yeong Shang Casting Iron Co. Ltd.
- Yeong Chen Asia Pacific Co., Ltd.

viii. Except for Yeong Guan Energy Tech. Group Company Limited., and its subsidiaries, none of the producers/exporters from China PR have responded to the Market Economy Treatment (MET) Questionnaire. Hence, the other, cooperating exporters have been given non-market economy treatment in

the present investigation. Yeong Guan Energy Tech. Group Company Limited., and its subsidiaries claimed market economy treatment and has submitted Market Economy Treatment (MET) questionnaire response.

ix. The China Chamber of Commerce of Machinery and Electronic Products (CCCME) an association of producers/exporters of the subject merchandise of the above investigation has requested to be the interested party in this investigation.

x. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

- a. M/s. Chiranjeevi Wind Energy Limited, Coimbatore.
- b. M/s Gamesa Wind Turbines Private Limited, Chennai.
- c. M/s GE India Industrial Private Limited, Bangalore.
- d. M/s Global Wind Power Limited, Chennai.
- e. M/s Inox Wind Limited, Noida.
- f. M/s Leitwind Shriram Manufacturing Limited, Thiruvallur.
- g. M/s Pioneer Wincon Private Limited, Chennai.
- h. M/s Regen Powertech Private Limited, Chennai.
- i. M/s RRB Energy Limited, Chennai.
- j. M/s Shriram EPC Limited, Chennai.
- k. M/s Siva Wind turbine India Private Limited, Erode.
- l. M/s Southern Wind Farms Limited, Chennai.
- m. M/s Wind World (India) Limited, Mumbai.
- n. M/s Suzlon Energy Limited, Pune.

ix. Except M/s Inox Wind Limited, none of the importers listed above have filed the Importer's questionnaire response.

x. Indian Wind Turbine Manufacturers Association (IWTMA), an association of importers of the subject merchandise of the above investigation has requested to be the interested party in this investigation.

xi. Initiation notification was sent to the following other domestic producers in India of the subject goods. However, none of the other producers have responded the same.

- a. Lakshmi Machine Works
- b. Vaksh Steel Pvt. Ltd.
- c. Walchandnagar Industries Ltd.

xii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

xiii. The applicant had furnished transaction-wise imports data from the IBIS source and the Authority had relied upon the same prima facie for initiating the investigation.

xiv. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions, and relied upon the same in this finding. DG Systems data has been used to complement the analysis, wherever applicable.

- xv. The Non-injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xvi. Accordingly, the NIP for the domestic industry has been determined as per the PCN.
- xvii. The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is from 1st April, 2014 to 30th September, 2015 (18 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from 2011-12, 2012-13, 2013-14 and the POI.
- xviii. The Authority held first oral hearing on 7th September, 2016 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6(6), which was attended by the representatives of domestic industry, exporters from China PR, exporter association, importers and importer association. The interested parties who presented their views orally at the time of oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were provided opportunity to offer rejoinder submissions to the views expressed by opposing interested parties.
- xix. Due to change in the incumbency of the Designated Authority and in line with the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the ATMA case, second oral hearing was conducted by the new Designated Authority on 16th December 2016 which was attended by the representatives of domestic industry, exporters from China PR, exporter association, importers and importer association. The hearing was restricted to the issue of change of ownership of the castings business division from M/S L&T to Bradken and the standing of the new petitioner. The interested parties who presented their views orally at the time of oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally in pursuant to the said issue and were provided opportunity to offer rejoinder submissions to the views expressed by opposing interested parties.
- xx. The Authority held the third oral hearing on 3rd May, 2017 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6(6), with regard to the merits of the case, which was attended by the representatives of domestic industry, exporters from China PR, exporter association, importers and importer association. The interested parties who presented their views orally at the time of oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were provided opportunity to offer rejoinder submissions to the views expressed by opposing interested parties.
- xxi. The Department of Revenue has extended the time period for completion of this investigation up to 30th July 2017 in terms of Rule 17 (1) of the Rules.
- xxii. On the spot verification of the data of the domestic industry, as well as that of the cooperating exporters, was carried out to the extent considered necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of this finding.
- xxiii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this finding.
- xxiv. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xxv. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded this finding on the basis of the facts available.

- xxvi. In accordance with the Rules the Authority issued a disclosure statement containing all essential facts of the case on 11th July 2017 for the comments of the interested parties. The comments of the interested parties, to the extent they are relevant, have been addressed in this finding in appropriate places.
- xxvii. *** In this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxviii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs 62.66

C. Product Under Consideration And Like Article

6. The Product under Consideration (PUC) in the present investigation is “Castings for wind-operated electricity generators, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators”. Castings for wind-operated electricity generators are also known as “windmill” or “wind turbine”.

7. A Windmill requires a number of casting parts, including the

- i. Hub, Rotohub, Rotor Nabe,
- ii. Main Frame, Base Frame, Main Foundation, Nacelle, Nacelle Frame, Nacelle Foundation,
- iii. Bearing Housing, Bearing Support,
- iv. Hollow Shaft,
- v. Main Axle, Rotor Shaft, Main Shaft, Rotor Coupling, Axle Pin,
- vi. Lateral Suspender,
- vii. Pitch Stop, Stator,
- viii. Generator castings, Part of Generators, Rotor,
- ix. Torque Arm support, Gear Box.

8. The product scope includes only wind turbine casting within the scope of the PUC. Casting if imported in raw/unfinished/semi finished or if imported as a part of sub-assembly equipments are within the scope of PUC. The basic function of a casting is in a wind turbine, to be used in a wind mill along with some other non-casting parts and components like blades, etc. which leads to the generation of electricity.

9. The subject goods is subsumed within Customs sub-heading No. 8503 under the Customs Tariff Act, they are also being imported under other tariff heads viz; 84834000, 85030090, 85030010 in Chapter 84 and 85. However, customs classification is indicative only and in no way it is binding on the scope of the present investigation.

10. Petitioner has claimed that there is no difference in subject goods produced by the petitioner and exported from the subject country. Subject goods produced by the petitioner and imported from the subject country are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Subject goods produced by the domestic industry and imported from subject country are like article in accordance to the Rules.

Submissions made by exporter, importer and other interested parties

11. The following are the submissions made by exporters/importers/other interested parties with regard to scope of the product under consideration and like article:

- i. The product involved is castings for wind-operated electricity generators also known as castings for windmills or wind turbines. The products is including varies shapes based on the customers' request, i.e. machined products, finished or sub-assembled products, parts of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component, meant for wind-operated electricity generators.
- ii. There is no difference between the goods sold in home market and exported to other countries including India in physical/ Technical/ Chemical characteristics.
- iii. M/S L&T has sought initiation of investigation against import “Castings of wind operated Electricity Generator” from China PR. However, the current investigation has been initiated

vide the Initiation Notification against "Castings for Wind Operated Electricity Generators whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a subassembly, or part of an Equipment/ Component meant for Wind operated electricity generators". Designated Authority has nowhere clarified as to how scope of the PUC has been widened. It is not right on part of the Authority to suo moto revise the PUC to include parts thereof without giving any cogent reasons for the same and without justifying the scope has been enhanced. Initiation Notification has travelled beyond the mandate of M/S L&T – Designated Authority has not mentioned how the scope of PUC as per letter dated 24th July, 2015 has been broadened and the intention of widening the scope with cogent reasons.

Submissions made by the Domestic industry

12. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article:

- i. The product under consideration in the present investigation is "Castings for wind-operated electricity generators, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators".
- ii. A Windmill requires a number of casting parts, including the Hub, Rotohub, Rotor Nabe, Main Frame, Base Frame, Main Foundation, Nacelle, Nacelle Frame, Nacelle Foundation, Bearing Housing, Bearing Support, Hollow Shaft, Main Axle, Rotor Shaft, Rotor Coupling, Axle Pin, Main Shaft, Lateral Suspender, Pitch Stop, Stator, Generator castings, Part of Generators, Rotor, Torque Arm support, etc.
- iii. The product is primarily sold in pieces/nos. The price depends upon the design, size, weight, and processing involved in a particular casting. Two castings of the same nature like HUB of two different windmills may not be the same in terms of associated weight, design, machining and process involved. Hence, the two may differ significantly in terms of cost and price.
- iv. The basic function of a casting is in a wind turbine, to be used in a wind mill along with some other non-casting parts and components like blades, etc. which leads to the generation of electricity.
- v. The product under consideration is classified under Chapter 85 of Customs Tariff Act, 1975 which covers "Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles". The product does not have dedicated classification.
- vi. Petitioner had suggested a PCN system which is used for identifying the product type for determination of dumping margin, price undercutting and injury margin. Even when the same has been adopted by the Designated Authority and no party has made any submissions in this regard.
- vii. This PCN system was also used for determination of injury margin in the CVD case, wherein the final findings have already been notified.
- viii. The average price of PUC is misleading. In fact, dumping margin, price undercutting and injury margin have been determined on PCN basis only for the reason that the average price analysis is misleading.
- ix. There are no known differences in subject goods produced by the petitioner and exported from China PR. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. The goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from China PR in terms of essential product properties. In fact, the subject goods are largely produced to meet specific customer requirements. The goods offered by the domestic industry are like article to the goods imported from China PR. All parts are made only as per customer specifications.
- x. The scope of the investigation is the same as the scope of the product under consideration in the petition. There is no enhancement.

Examination by the Authority

13. The meaning and scope of the product under consideration was defined by the Authority in the initiation notification as follows:

“The product under consideration in this investigation is “Castings for wind operated electricity generators also known as castings for windmills or wind turbines, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component, meant for wind-operated electricity generators”.

4. A Windmill requires a number of casting parts, including the Hub, Rotohub, Rotor Nabe, Main Frame, Base Frame, Main Foundation, Nacelle, Nacelle Frame, Nacelle Foundation, Bearing Housing, Bearing Support, Hollow Shaft, Main Axle, Rotor Shaft, Rotor Coupling, Axle Pin, Main Shaft, Lateral Suspender, Pitch Stop, Stator, Generator castings, Part of Generators, Rotor, Torque Arm support, etc. These castings are used in the wind turbines along with some other non-casting parts and components like blades, etc. which leads to the generation of electricity. All such castings, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component, meant for wind-operated electricity generators are covered in the present investigation.”

14. The arguments of interested parties have been examined by undertaking on the spot verification at the premises of the petitioning companies and calling relevant information from the parties.

15. Following are the observations made by the Authority in regard to the product under consideration:

- i. The product under consideration in this investigation is “Castings for wind operated electricity generators also known as castings for windmills or wind turbines, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component, meant for wind-operated electricity generators”.
- ii. A Windmill requires a number of casting parts, including the Hub, Rotohub, Rotor Nabe, Main Frame, Base Frame, Main Foundation, Nacelle, Nacelle Frame, Nacelle Foundation, Bearing Housing, Bearing Support, Hollow Shaft, Main Axle, Rotor Shaft, Rotor Coupling, Axle Pin, Main Shaft, Lateral Suspender, Pitch Stop, Stator, Generator castings, Part of Generators, Rotor, Torque Arm support, etc. These castings are used in the wind turbines along with some other non-casting parts and components like blades, etc. which leads to the generation of electricity. All such castings, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component, meant for wind-operated electricity generators are covered in the present investigation.
- iii. Although the product under consideration is classified under Customs sub-heading No. 8503 under Chapter 85 of Customs Tariff Act, 1975, as reported by the domestic industry and reflected in the relied upon imports data obtained from DGCI&S, the PUC is being imported under various other heads as well. However, customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.
- iv. The product under consideration has also been collectively referred to as castings for wind operated electricity generators (WOEG). The basic function of a casting is to be used in a wind mill along with some other non-casting parts and components like tower, blades, etc. which leads to the generation of electricity. A windmill requires a number of casting parts including Hub, Rotohub, Rotor Nabe, Main Frame, Base Frame, Main Foundation, Nacelle, Nacelle Frame, Nacelle Foundation, Bearing Housing, Bearing Support, Hollow Shaft, Main Axle, Rotor Shaft, Rotor Coupling, Axle Pin, Main Shaft, Lateral Suspender, Pitch Stop, Stator, Generator castings, Part of Generators, Rotor, Torque Arm support, etc.
- v. In view of the above, the Authority holds that the scope of the product under consideration defined in the notice of initiation is appropriate and defines the scope of the product under consideration as follows:

"Castings for wind-operated electricity generators also known as castings for windmill or wind turbine, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators"

16. With regard to like articles, Rule 2(d) of the AD Rules provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

- vii. The petitioner claimed that the goods are produced as per requirements and specifications given by the consumer/buyer and therefore the goods supplied by the domestic industry and Chinese suppliers have to conform to the specifications laid down by the consumers.
- viii. The product is primarily sold in pieces/nos. The price depends upon the design, size, weight, and processing involved in a particular casting. Two castings of the same nature like HUB of two different windmills may not be the same in terms of associated weight, design, machining and process involved. Hence, the two may differ significantly in terms of cost and price.
- ix. In view of the above, the authority holds that subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from China in terms of the Rules.
- x. The product is model specific depending upon the design and capacity of the wind mill required by the wind mill producers. Both the domestic producers and exporters supply to the same wind mill producers in India.

PCN derived by the Authority-

- xi. The petitioner had determined dumping margin, price undercutting and injury margin at the time of application by following criteria to differentiate different types of the product under consideration.
- xii. Post initiation, and after receipt of questionnaire responses from various interested parties, Authority has derived the Product Code Number (PCN) for the collection and analysis of data vide communication dated 4th March, 2016. The authority proposed following criteria [modal match criteria or product control number system (PCN system)] to differentiate different types of the product under consideration in order to determine dumping margin, price undercutting and injury margin.

Parts	PCN	Stage	PCN	Customer	PCN	Capacity		PCN
HUB	A	As Cast	C	Enercon	A	-	-	NPUC
Main frame	B	As Machining	M	Windworld	A	100	299	A
Frame	B	Assembling	A	Gamasa	B	300	499	B
Nacelle	B			Garuda	C	500	699	C
Base frame	B			Global Wind	D	700	899	D
Main Carrier	B			Hansen	E	900	999	E
Main frame	B			ZF Wind Power	E	1000	1000	F
Housing	C			Innovent	F	1001	1199	G
Main Cover	C			Inox	G	1200	1399	H
Side Bearing	C			Kenersys	H	1400	1599	I
Hollow shaft	D			Leitner	I	1600	1799	J
Axle Pin	E			LSML	I	1800	1999	K
Main Axle	E			Prakash industries	K	2000	2000	L
Rotor Coupling	E			Regen	L	2001	2099	M
Lateral Suspender	F			Vestas	M	2100	2100	N
Pitch stop	F			Win wind	N	2101	2299	O
Rotor	G			Winergy	P	2300	2499	P

Parts	PCN	Stage	PCN	Customer	PCN	Capacity		PCN
Stator	G			Suzon	Q	2500	2699	Q
Rotor Casted	G			Repower	R	2700	2899	R
Torque Arm	H					2900	3099	S
Down Holder	O					3100	3299	T
Slider Claw	O					Above 3300		Z
Yaw Base Bottom	O							
Unibody ABS Ring	O							
Blade Adaptor	O							
804 Planet Carrier	O							
Planet Carrier	O							
Ring Base	O							
Yaw Top	O							
Wedge	O							

- xiii. On perusal of essentials facts and on analysis of PCNs exported by various co-operative exporters and PCN produced by the domestic industry, it was noted that two parts namely Hub and Main Frame (PCN for part A & part B) constituted majority of the volume and the rest of the parts which were large in number but each having negligible contribution in volume. Capacities associated with each part were also regrouped and bundled into four ranges as the pricing was largely determined on weight basis for Part A and B. Therefore, in order to facilitate a fair comparison, the PCN devised during initiation of investigation were regrouped and rationalized as follows.

Parts	PCN	Stage	PCN	Capacity		PCN
HUB	A	As Cast	C	-	-	NPUC
Main frame	B	As Machining	M	100	999	A
Frame	B	Assembling	A	1000	1499	B
Nacelle	B			1500	1999	C
Base frame	B			2000	5000	D
Main Carrier	B					
Housing	O					
Main Cover	O					
Side Bearing	O					
Hollow shaft	O					
Axle Pin	O					
Main Axle	O					
Rotor Coupling	O					
Lateral Suspender	O					
Pitch stop	O					
Rotor	O					

Stator	O							
Rotor Casted	O							
Torque Arm	O							
Down Holder	O							
Slider Claw	O							
YAW BASE BOTTOM	O							
Unibody ABS Ring	O							
Blade Adaptor	O							
804 Planet Carrier	O							
Planet Carrier	O							
Ring Base	O							
Yaw Top	O							
Wedge	O							

17. The newly devised PCN was communicated to the interested parties vide communication dated 25th May, 2017. Comments were invited from all interested parties considering the PCN system determined by the authority. The same has been examined and addressed wherever applicable.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

18. The following are the submissions made by exporters/importers/other interested parties have made any submissions in this regard:

- i. The investigation was initiated at the behest of M/S L&T and not at the behest of the manufacturing unit producing the subject goods.
 - The investigation was initiated following a petition filed by L&T.
 - The document available in the public file shows that M/S L&T has filed the original petition and the revised information thereafter.
- ii. Petition is being filed by M/S L&T and the address of the petitioner has been shown as their Mumbai office's address. Bradken has not filed the petition and can't be considered as the petitioner. Mere sale of the Coimbatore business division by M/S L&T to Bradken doesn't allow Bradken to be considered as the petitioner.
- iii. In initiation Notification, M/S L&T was designated as the petitioner and also the Domestic Industry. As per letter dated 11th March, 2016, filed by Bradken, purchased the Coimbatore division from L&T. As per letter filed with BSE Ltd., it has been stated that an agreement for sale of the said business division was entered into between M/S L&T and Bradken on 11th Nov 2015. Approval from Competition Commission was obtained on 20th Jan., 2015. However, no such information has been filed with DGAD by L&T.
- iv. The corporate structure and cost of production of the manufacturing unit located in Coimbatore are affected by the new legal entity which is part of a large group of companies having an Australian parent company.
- v. The sale of the manufacturing unit located in Coimbatore to Bradken was engaged well before the initiation of the present investigations which took place on 1st Feb, 2016.
- vi. The first installment of the consideration for sale was made on 18th May 2015, much before the initiation. The agreement in respect of all terms of sale had been reached much before the final acquisition. The agreement to make sale had concluded during the period of investigation itself. It was obligatory for L&T, to inform the Authority immediately about such development which was not done.

- vii. Notice was filed on 10th Dec., 2014, under sub-section (2) of Section-6 of the Competition Act, 2002 given by Bradken Operations Pty. Limited. The notice was tiled pursuant to the execution of a Business Transfer Agreement between Bradken and M/S L&T on 11.11.2014. Approval of CCI was obtained on 20th Jan., 2015.
- viii. Order of CCI shows that process of transfer of Coimbatore Business division to Bradken by L&T, had taken place as early as 11.11.2014. It was an onus duty of L&T, to inform the Authority about such transfer agreement.
- ix. As per information provided to BSE, Agreement between L&T, and Bradken for sale of business division was concluded on 11th Nov., 2015 much before the present investigation satisfied. It was obligatory on the part of M/S L&T Ltd., to intimate the Hon'ble Designated Authority about such change in ownership which was not done.
- x. As per the initiation notification, M/S L&T is the domestic industry and continues to be in the present investigation. Change in the legal status of domestic producer is a ground for MTR.
- xi. New application needs/can be filed by Bradken to be considered as the Petitioner.
- xii. Communications have been made by TPM Consultants on behalf of L&T, and not on behalf of Bradken, India. TPM Consultants continued to represent M/S L&T as M/S L&T never notified that TPM Consultants are no more representing them in this matter, till this issue has been raised by interested parties. M/S L&T is still having facilities which can manufacture the subject goods with an installed capacity of 850 Mt.
- xiii. Bradken has informed the DGAD about the sale and not L&T. It was an obligation of M/S L&T to notify DGAD as the petition was filed by M/S L&T itself.
- xiv. M/S L&T shall have filed copy of agreement along with its Board resolution. No such documents have been filed. Bradken shall have filed valuation report for the business division. However, no such document was ever filed by Bradken. Two-page letter by Bradken has been filed without any supporting documents.
- xv. With the change in ownership, there is a strong possibility that there is a change in capacity and various other parameters also as M/S L&T is multi-product company and Bradken India is a single product company. The present cost and all injury parameters are relevant for the current owner of the unit and not of the earlier owner.

Submissions made by the Domestic industry

19. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing:

- i. The present petition has been filed by Larsen & Toubro Limited whose production constitutes more than 50% of Indian production. M/s Patel Alloys Steels Pvt. Limited has supported the petition. Petitioner is eligible producer of the subject goods in India.
- ii. Production of the petitioner constitutes a major proportion in Indian production. The petitioner, therefore, constitutes domestic industry and satisfies the requirement of standing under the Rules. Further, the petitioner has not imported the product under consideration, nor are they related to any importer or exporter of the product under consideration.
- iii. Business Transfer Agreement between the two companies, M/S L&T & Bradken, materialized after the initiation of the investigation. Investigation was initiated following a petition filed by M/S L&T and the documents available in the public file shows that M/S L&T has filed the original petition and the revised information thereafter. The Business Transfer Agreement materialized post initiation of the investigation and the change of ownership was well intimated to the Authority vide letter dated 11th March, 2016, by the Bradken itself.
- iv. The BTA mentions that any rights and obligations arising in these legal proceedings are to Bradken's account. Bradken had been conferred upon with all the rights and all the liabilities that were with M/S L&T in so far as this business division is concerned. M/S L&T continues to remain responsible for other previous legal proceedings barring the ones arising under this agreement.

- v. At the time of initiation of investigation, M/S L&T was the owner of the Coimbatore Business division, and the business transfer agreement got concluded post initiation of the investigation. The letter filed by Bradken clearly states that the company is interested in order to continue the investigation and for which they authorize M/s TPM Consultants. The Authority may notify the change of ownership in the finding and clearly mention that both M/S L&T and Bradken are considered as the petitioners.
- vi. If Designated Authority wants M/S L&T to inform the development or any other aspects involved therein, the Designated Authority can write to L&T. Because M/S L&T has not informed Designated Authority does not mean the investigation should be terminated.
- vii. The petition, as filed on 29th July, 2015 by L&T, states that the contact person for the petitioner is Dr. Nithyanandan Devaraaj who was the head of Foundry Business Unit Operations at Coimbatore. Later, when on 11th March, 2016, Bradken India wrote a letter to DGAD informing that the unit has been acquired by it; the same was signed by Dr. Nithyanandan Devaraaj, who is now the President & Director of Bradken India. Thus, the petition which was filed on 29th July, 2015, was in fact signed by the business unit which has been sold and the letter sent to DGAD informing about the sale, was also done by the business unit.
- viii. Both M/S L&T and Bradken should be considered as the petitioners and Bradken has not substituted M/S L&T as the petitioners. Bradken has impleaded itself before the Authority with regard to present investigation and imposition of duty.
- ix. Bradken has provided all relevant data and clarified all facts regarding present petition for which POI is April 2014- September 2015.
- x. Bradken has provided all documents and proof of taking over of business.
- xi. There is no change in the operating structure, production facility and business unit. Also, the nature of various activities of the business division vis-à-vis production, sale etc of subject goods remains the same as compared to the position before acquisition.
- xii. If the business division was part of corporate legal entity, it is natural that the petition would be signed by the manufacturing operations as L&T. However, entire production and product data pertains to the manufacturing location. Further, M/S L&T has not till date withdrawn the letter.
- xiii. The petitioner was bound by the confidentiality clause of the Agreement. Further, ongoing negotiations do not mean that the agreement was complete. Informing to BSE & CCI is one of the procedural requirements and essentials to materialize the Agreement which is the requirement under the law. The interested parties should be well aware of the requirements of the sale purchase being done by any public ltd. company. These procedures have been followed by Bradken and M/S L&T in letter & spirit.
- xiv. Immediately after the agreement was complete, Bradken has informed the Authority about the Business transfer agreement and gave the authorization to TPM consultants vide letter dated 11th March 2016. Further all the communications made by TPM consultants were made on the behalf of Bradken and not L&T. TPM got authorization from Bradken, vide letter dated 11th March, 2016, all further fillings done by TPM were on the behalf of Bradken and not L&T.
- xv. The process and negotiations of sale of the business division of Coimbatore from M/S L&T to Bradken may have started way back but the agreement was completed on 4th March, 2016 i.e. post initiation of the investigation. The parties to the agreement were bound by the confidentiality clause of the agreement. M/S L&T could not have informed the Designated Authority or parties about the development, unless it materialized in the form of signature.
- xvi. Standing is required to be determined in respect of petition and not petitioner. The standing is determined on the basis of production and producer is relevant only to the extent that the production has been done by a legal entity. The updated data for the present petition has been filed by Bradken India Pvt. Ltd.
- xvii. The present business transfer is by way of slump sale and the transfer of the unit was done on the basis of ongoing concern. Financial performance and injury information is not impacted by any sale or purchase of business. At the time of sale, the book value of assets and the capital

employed had no other revenue implication. Thus, there was no impairment of assets. Instead, there is upward valuation of assets, requiring higher level of profits. Since, there is not impairment of assets, the capital employed is required to be reduced because of change of ownership. In fact, the Designated Authority should now determine return on investment to the domestic industry on the basis of the valuation that has been considered for sale-purchase transaction.

- xviii. M/S L&T is still having another plant of the subject goods at Kansbahal, Odissa, which suspended production in the year 2012-13.
- xix. Till date the MTR conducted by the Authority only after the imposition of the finding. The fact that change in legal status of domestic producer calls for MTR in fact shows that duties imposed and in force shall not be withdrawn, and rather be reviewed. In the present case the investigation is still going on and duty is yet to be imposed so no question of doing MTR. Change in legal status of domestic producer does not establish a need for MTR, as the Designated Authority will have to be consider whether mere change in legal status of domestic producer is sufficient enough to bring significant change in dumping margin or injury margin or any other parameters relevant to imposition or continuation of ADD.
- xx. Authority has conducted on the spot verification at the premises of the petitioner and Chinese companies. If the Petition lacked standing, the interested parties would not and should not have offered verification and the Designated Authority should not have conducted verification.
- xxi. M/S L&T still continued the present petition itself shows that despite sale of the business, the company continued with the petition. Under the law, the petition can be filed by or on behalf of domestic industry. In that case, it should be construed that M/S L&T continued the petition on behalf of domestic industry.
- xxii. There is no relevance of such documents pertaining to a company who has sold the business division. The status of new entity is required to be examined. Not the status of entity who has sold the business.
- xxiii. The argument is based on possibilities and conjectures. The Designated Authority has actual information on record and the same may be considered.
- xxiv. Sale of entire company and sale of PUC operations cannot be distinguished under the law.
- xxv. Parties cannot be sitting silent on the issue for several months. No jurisprudence has been provided to show that the present petition is not maintainable.
- xxvi. The annual report just talks about that the Bradken is planning to acquire a foundry in India. Till the stage the sale is complete the parties are bound by the confidentiality clause of the agreement.
- xxvii. The company has audited accounts for its Coimbatore location where PUC is produced and the same has formed the basis of entire data/ information in the petition.

Examination by the Authority

20. Rule 2(b) defines domestic industry as under:-

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

21. The Authority notes that the petition has been filed by Larsen & Toubro Limited. Subsequently, a copy of support letter by M/s Patel Alloys has been submitted along with information concerning capacity, production and sales. The production by the petitioner constitutes a major proportion in the Indian production of the subject goods. Petitioner has neither imported the product under consideration from the subject country during the POI nor is related to either importers or exporters of subject goods from the subject country.

22. On the basis of sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject country; injury to the domestic industry; and causal link between the dumping and injury exist, the Authority

initiated the present investigation vide notification no. 14/28/2013-DGAD dated 1st February, 2016 to examine the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping, if any, and to recommend the amount of antidumping duties, which if levied would be adequate to remove injury to the domestic industry.

23. On 4th March, 2016, M/s Larsen & Toubro Limited sold the business relating to the product under consideration to M/s Bradken India Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as “Bradken”) through a Business Transfer Agreement. The business division of the company situated at Coimbatore has continued the operations in the name of Bradken India Private Limited w.e.f 4th March, 2016. The Designated Authority was informed about the same by Bradken vide its letter dated 11th March, 2016. Bradken specifically mentioned that the Designated Authority should continue the investigation and recommend anti dumping duty on imports of the product under consideration. In the said letter, apart from giving authorization to TPM Consultants to represent them in the present investigation before the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties, it was also mentioned that, in case, the Designated Authority requires any information regarding the acquisition of the business as well as business division of the product under consideration by Bradken, they are willing to assist.

24. The said reported event was made known to the interested parties by the Designated Authority by placing the non confidential version of the letter in the public file immediately thereafter. Even when petitioner had informed the Designated Authority about the said development on 11th March, 2016, none of the interested parties made any submissions whatsoever which could establish that the petitioner no longer had standing to maintain the present petition.

25. M/S L&T filed a petition for imposition of anti-dumping duties. Initiation of the investigation by the Designated Authority conferred a legal right on L&T, as this initiation resulted in conferment of valuable right onto M/S L&T which has been transferred to Bradken in pursuance of the Business Transfer Agreement. M/S L&T continues to remain responsible for all other legal proceedings going on in M/S L&T in the country or globally, barring the proceedings relating to this business division. M/S L&T has not filed any communication withdrawing the present petition. If deemed appropriate, the Designated Authority may write to M/S L&T to seek appropriate clarification.

26. In terms of Business Transfer Agreement, all rights with M/S L&T with regard to this business division have been transmitted to Bradken. Bradken has been in particular conferred all rights available to M/S L&T in so far as business division at Coimbatore are concerned. At the same time, Bradken has also acquired all liabilities that were earlier with M/S L&T in so far as this business division is concerned. And, all other rights and liabilities with M/S L&T for any of the division other than Coimbatore unit continue with L&T.

27. Vide letter dated 4th April, 2016, petitioner had filed copies of the non-confidential version of updated data for the POI chosen by the Designated Authority for the present petition has been filed by M/s Bradken India Pvt. Ltd. Thus, not only M/s Bradken India provided updated data, but also clarified facts with regard to past petition. Further, the POI in the present case is April, 2014- September, 2015, a period during which the ownership was with M/S L&T and data for this POI was provided by M/s Bradken India.

28. The Designated Authority asked the petitioner to file “all supporting documents and proof of taking over of the business division from M/s Larsen Toubro Ltd. immediately for further examination” vide email dated 9th May 2016 and the same was submitted by the petitioner via letter dated 17th May, 2016.

29. The acquisition of the Coimbatore unit was done as going concern basis. This combination has been registered with Competition Commission of India as *Combination Registration No. C-2014/12/229* with respect to Section 5 of the CCI Act. There are no changes in assets, production, capacity or any other parameters. Only the ownership has been changed from M/S L&T to M/s Bradken.

30. Further, in reply to the mail dated 9th September, 2016, sent by the Designated Authority, the costing information of M/s Bradken along with other information was submitted by the Petitioner via letter dated 12th September, 2016.

31. The authority has conducted on the spot verification at the premises of the petitioner and Chinese companies. The issue of standing was discussed by the DGAD and clarifications sought to the extent deemed appropriate by the officers at the time of verification.

32. At the time of previous anti subsidy investigations, the injury period was 1st October, 2012 to 31st December, 2013, the authority directed the petitioner to segregate the information for two plants (which is the normal procedure for verification of information). Thereafter, in the final findings, the authority has adopted information relating to only Coimbatore business division and has discarded the information relating to Kansbahal Plant. Even when M/S L&T was a petitioner in the previous case, the authority had discarded information relating to Kansbahal plant. M/S L&T has not sent any communication to the authority stating therein their unwillingness to provide any information required by the authority with regard to their Kansbahal plant which had formed a part of petition. In fact, M/S L&T has not till date even withdrawn its request for imposition of ADD.

33. Therefore, the Authority holds that the applicants M/S L&T & M/s Bradken both constitute petitioner in the present case. M/S L&T has sold the castings producing unit to the M/s Bradken as an ongoing concern under which there is no impairment of assets have taken place. M/s Bradken has impleaded with the Authority in order to continue the investigation and impose the anti dumping duty and not substituted L&T. The Authority holds that ideally the information regarding the sale and purchase of the unit should have been intimated at the earliest. However, the omission is not substantive enough to vitiate the proceeding of the investigation.

Particulars	UOM	2011-12	2012-13	2013-14	POI (A)
Petitioner					
L&T	MT	9,923	5,574	7,434	12,157
Index		100	56	75	123
Supporter					
Patel Alloy Steel (P) Ltd.	MT	4,268	176	201	121
Index		100	4	5	3
Petitioner + Supporters	MT	14,191	5,750	7,635	12,278
Index		100	41	54	87
Other Producers	MT	3,100	2,900	3,000	3,200
Index		100	94	97	103
Indian Production	MT	17,291	8,650	10,635	15,478
Index		100	50	62	90
Share	UOM	2011-12	2012-13	2013-14	POI (A)
Petitioner					
L&T	%	57%	64%	70%	79%
Index		100	112	122	137
Supporter					
Patel Alloy Steel (P) Ltd.	%	25%	2%	2%	1%
Index		100	8	8	3
Petitioner + Supporters	%	82%	66%	72%	79%
Index		100	81	87	97
Other Producers	%	18%	34%	28%	21%
Index		100	187	157	115
Indian Production	%	100%	100%	100%	100%

34. Further, petitioner command a major proportion of the production of the subject goods in India and for the purpose of this investigation the applicants satisfies the standing requirement in terms of Rule 5(3) and constitutes the domestic industry in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

D. CONFIDENTIALITY**Submissions by exporter, importer and other interested parties**

35. The exporter, importer and other interested parties made the following submissions:

- i. The petition lacks adequacy and accuracy, required under rule 5 and 7 of Anti-dumping Rules. Data given by the DI is insufficient and inconsistent. Excessive confidentiality claimed by the DI.
- ii. Soft copy of the import data on a transaction-by transaction basis as recorded by the DGCI&S during the POI has not been furnished even after the decision by Delhi High Court in Sandisk international Ltd. vs The Designated Authority & Ors.
- iii. Data provided in NCV are confidential and against Rule 7 of ADD. Non confidential version of the information should allow interested parties to exercise their rights of defense throughout the investigation.
- iv. DI is silent on Section VI i.e. costing data.
- v. Castings require all utilities such as power, steam or any other utilities and Petitioner has not provided such information as working capital, interest in terms loans, overdue and or compounding interest, depreciation, details of miscellaneous income and details of WIP, Return profit: Statement showing desirable return on capital equity along with justification in support thereof.
- vi. Gross fixed assets are not as per Annexure III of ADD Rules and kept confidential
- vii. Purchase policy including long terms contracts for major materials.
- viii. Sales Policy indicating marketing distribution channels, commission/discount policy, credit terms etc., sale policies to bulk consumers.
- ix. Stores accounting and inventory stock, WIP Valuation.
- x. Quality control procedure and tests being conducted.
- xi. Why Import data of major consumers sourced from IBIS Import data has been claimed confidential unless it is wrong and manipulated data. The Authority shall direct the Petitioner to disclose this information.
- xii. Excessive Confidentiality claimed against the judgement given by Hon'ble Supreme Court in the matter of *Alkali Manufacturers Associations of India vs. Designated Authority 2006 (194) E.L.T 161* and *Reliance Industries vs. Designated Authority 2006 (202) EL T 23 (SC)*. Confidentiality claimed in Sales Volume data, Summary of DM, IM & Price Undercutting cannot be accepted.
- xiii. The consumer wise import data is not confidential in nature.

Submissions by Domestic industry

36. The Domestic Industry made the following submissions:

- i. The raw import data sourced from DGCI&S is confidential information. Some interested parties had earlier misled the Hon'ble High Court of Delhi in believing that bill of entry wise data is publically made available by DGCI&S and a party can obtain this information even under RTI. However DGCI&S does not publically make available bill of entry wise import data and provides month wise, country wise import data at 8 digit level. This, however, cannot be construed as bill of entry wise data, which is largely understood by DGAD as transaction wise data. Month wise country wise data and bill of entry wise data are different information and are poles apart. The issue is already under consideration before Hon'ble Supreme Court, who has since stayed the order of Hon'ble High Court of Delhi. Notwithstanding the stay order, the petitioner has already made available bill of entry wise import data.
- ii. Domestic industry has claimed only such information as confidential, confidentiality of which is provided under Rule 7. The Rules provide that information which is confidential in nature or which has been provided on confidential basis can be treated confidential by the Authority. Thus, any information provided to the Designated Authority on the grounds that it is confidentiality shall have to be kept confidential by the Authority.

- iii. The domestic industry has not claimed any information as confidential which is available in public domain.
- iv. The consumer wise import data is confidential in nature. There is no wrong data provided to the Authority and the actual figures are submitted with the Authority. The Authority may call the information from the interested parties and may verify the same.
- v. In the present case, the responding exporters have resorted to excessive confidentiality and have not provided even such information which is publicly available.
- vi. The interested parties cannot simply withhold some information from the domestic industry. Even if some information is fully confidential, the interested parties are obliged to provide sufficient NCV of the same and not blank pages, permit the domestic industry to reasonably understand the substance of the information and have full right of defense.
- vii. Designated Authority is not required to mechanically treat the information provided by a party as confidential merely because that party has desired it to be kept confidential. Rules confer discretion upon the Designated Authority to consider the request for confidentiality made by a party and if it is satisfied that the same is not warranted or that the supplier of the information is unwilling to make information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

EXAMINATION BY AUTHORITY

37. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule(2),(3)(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

38. Submissions made by the interested parties with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are examined and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.

E. Misc. submissions made by interested parties and the Examination thereof

Submissions by exporter, importer and other interested parties

39. The exporter, importer and other interested parties made the following submissions:

- i. The present investigation is affected by severe procedural deficiencies. Absence of original petition.
- ii. The Petitioner has significantly impeded the investigation and should be considered as non-cooperative by filing four different sets of containing contradicting data. US - Hot-Rolled Steel

- and in Egypt Rebar the Panel and Appellate Body ruled that any cooperating party should act in good faith during the investigation.
- iii. The Petitioner has submitted four different sets of data containing contradicting information and no explanation provided to explain the discrepancies in data; waited for three months before providing clarification on two letters dated 4 April 2016 and only provided clarification on the eve of the public hearing. A new set of data filed on 12th September 2016.
 - iv. Serious doubts about authenticity and accuracy of import data as different figures of imports volumes and value have been claimed in the CVD and ADD investigations.
 - v. The frequency of changes in data has only raised questions on credibility and accuracy of the Petitioner's claims and allegations. Guatemala case (WT/DS60/AB/R) - 'sufficiency' of the evidence shall not rely on its accuracy and adequacy' and it shall be the discretion of the authority to decide- adequacy and accuracy' may be ignored by DA, but for that the evidence needs to be sufficient. The initiation should be quashed and a fresh initiation and examination of the data for the revised POI should be carried out if Authority is satisfied with the data as required in Rule 5.
 - vi. If anti-dumping duty were to be imposed in the form of a fixed amount this amount of duty should take into account the wide scope of the subject goods and should be adapted to each types of castings.
 - vii. Any determination of the injury should exclude factors other than limited imports. The residual CVD imposed on imports of castings were equal to the subsidy margin and injury margin was higher. DI has to wait for reasonable amount of time for CVD to show impact on injury caused and not resort to forum shopping, claiming injury on inaccurate and misleading data to eliminate competition.
 - viii. Letter of support by M/s Patel Alloys Steels (P) Limited alone is not sufficient- Direct Patel alloy to file response giving their economic parameters; simple support letter is not sufficient.
 - ix. Why Import data of major consumers sourced from IBIS Import data has been claimed confidential unless it is wrong and manipulated data.
 - x. The Petition is silent about as to how the number/pieces have been converted into MT.
 - xi. POI fails to take into account the impact the CVD on the imports and the price of PUC imported from the subject country. POI should have been selected to investigate whether the levied CVD duties have addressed the material injury faced by the DI. The CVD should not be double counted when levying any ADD as required under Customs Tariff Act, 1975 to the extent of export subsidies should be subsumed in the ADD levy to ensure that there is no unfair double levy.
 - xii. POI fails to take into consideration the sale of Coimbatore which suggests that the Petitioner could not have been injured due to the imports.
 - xiii. The situation and profitability have improved post the imposition of the CVD which would have lead to an increased valuation of the unit thus making the sale by M/s Bradken a viable option. DA should call upon the Project Report to accurately assess the profitability and growth predictions of the company.
 - xiv. The Present Initiation is in Contravention of ADD Rules due to exclusion of Hong Kong and changing the POI after the initiation.
 - xv. Updated data filed by the petitioner has the imports coming from Hong Kong during the POI which is above 3%, which is above the de-minimis margin. Price of imports from Hong Kong are 2%-3% that the price of goods coming from China. The price undercutting for China is 20-30%, then in such situation the price undercutting for Hong Kong will be much more less. Hong Kong is not only above de minimis but also at a price lower than the subject imports. There is not only a breach in causality due to the exclusion of Hong Kong.
 - xvi. The DI should provide proof of transshipment from Hong Kong. The DA must seek information on export from Hong Kong.
 - xvii. Petition filed on September 29, 2015 is referring to Initiation Notification issued on February 1, 2016. The Respondent is not able to find out reason how a document that was filed almost 5

months prior to issuance of the Initiation Notification can very accurately specify the Initiation Notification. However, legal representative of M/S L&T submitted that this was a minor error and that as per practice being followed in the DGAD, non-confidential version of the Petition is required to be filed after issuance of the Initiation Notification. Such irresponsible statements made before the Authority shows approach of the Petitioner towards the current investigation and puts question mark on the sanctity of present investigations.

- xviii. Rule 5 of the AD Rules, nowhere mentions that two versions of petition have to be filed, one while applying for initiating of investigation and other i.e. non-confidential version after issuance of initiation notification. If there is any specific provision confirming what M/S L&T submitted during the Public Hearing, then they must make other interested parties aware of the same. The procedure followed by the Petitioner is unlawful and the Hon'ble Designated Authority must dismiss the Petition. This action of the Petitioner is not only fatal to the present investigation but unethical also and calls for serious review of the current procedure being followed in the matter of conducting ADD investigations.

Submissions by Domestic industry

40. The Domestic Industry made the following submissions:

- i. Petition with regard to the imposition of anti dumping duty was filed way back in the year 2013. The reason for mentioning the word “*updated petition*” on the NCV petition is due to the repeated filing of petition since the year 2013.
- ii. Quality and quantity of information and evidence improves, as an investigation progresses. Purpose of initiation is to gather relevant information. The requirements of Rule 5 and 6 have adequately been met.
- iii. The Designated Authority has not recorded a finding recommending anti-dumping duties upon initiation of investigations. Information sufficient for the purpose of initiation may not be sufficient for the purpose of determination and information required for determination need not be insisted upon at the time of initiation.
- iv. There is some difference in some of the statistics between NCV petition denoted as updated petition dated 29th September, 2015, two letters dated 4th April, 2016 and the letter filed on 12th September, 2016. The four different sets of data filed are—

SN	Name	Date	Reason for variation in data
i.	Updated petition	29 th September, 2015	Based on IBIS data, having POI- 2014-15
i.	First letter	4 th April, 2016	Based on IBIS data, having POI- April, 2014-September, 2015- Having some calculation error in the figures of imports and return on capital employed
i.	Second letter	4 th April, 2016	Based on IBIS data, having POI- April, 2014-September, 2015, filed to rectify the error, dated 4 th April, 2016 received in DGAD on 18 th April, 2016
v.	Third letter	12 th September, 2016	Based on DGCI&S data, having POI- April, 2014-September, 2015. Letter filed based on revised data filed as per directions of the DGAD

- v. Petitioner has already provided the explanation with regard to the discrepancy in the data filed vide letters dated 4th April, 2016 through letter filed dated 6th September, 2016, acknowledging the error made.
- vi. There is no discrepancy in the data filed in the letter dated 4th April, 2016 and in the letter filed on 12th September, 2016 as the letter filed on 4th April, 2016 was based on IBIS data where as the later was based on DGCI&S data.

- vii. The Authority in the present investigation has already formed the PCN looking at the wide range of products within the range of PUC followed the same principle in the CVD investigation concluded in November, 2015.
- viii. The Designated Authority has issued questionnaires only to exporters and importers and not issued any questionnaire to consumers or their association. Consumers are being represented through association, it is imperative that the authority calls information from consumers and from such consumer association as neither the user association nor the consumers have filed any information whatsoever considering that the imports have been made by them. DA may kindly direct the association to provide relevant information as specified in rules.
- ix. Petitioner reiterates that the numbers have been converted into Weights by the following methods- PCN wise we make the same castings or have made them before. In cases where we do not make, these have been estimated based on market information.
- x. The domestic industry was continuously facing injury since 2012 as the first petition was filed in the year 2013. Meanwhile the CVD was imposed, which is still unable to redress the injury. Authority cannot wait for the industry to be wiped off in order to see the impact of CVD imposed. Post imposition of CVD, the performance of the domestic industry has deteriorated.
- xi. ADD case was initiated on 1st February, 2016 for which the CV petition was filed on 29th July, 2016. The POI in the same petition was appropriately taken as March 2014 to April 2015. The CVD duty was imposed on 19th January, 2016. In order to see the impact of CVD duty, it was not feasible to wait when the CVD was not even imposed and the duty was not able to redress the injury being faced by the domestic industry. Nor, there is a legal obligation to take into account the effect of CVD. The only obligation is to address dual remedy issue.
- xii. The exporter has compared the figures of volume of imports given in updated petition, which was based on 2014-15 data as POI, first letter, having error, second letter, which was based on IBIS data and the POI, was April, 2014- Sept. 2015, and the third letter of 12th September, which was based on DGCI&S data.
- xiii. Petitioner has provided the comparative analysis of the DGCI&S data and the IBIS data vide 12th September, 2015. The exporter has compared the average selling price of DI with the average price of imports from China.
- xiv. DI is selling various types of products coming within the PUC; whereas majority of imports from China are coming as HUB and Main Frame. The average price of the PUC is totally misleading.
- xv. Price of imports from China in all the four submissions are varying, especially in the POI, as the data in the updated petition was based on IBIS and POI was 2014-15, whereas the data taken in the second and the third letter was based on IBIS data but the POI was April 2014 to September 2015. The third letter is based on the DGCI&S data.
- xvi. DI is producing various types of products coming within the PUC and the quantities of the PUC are misleading whereas the selling price of the PUC shows material injury.
- xvii. Designated Authority considers only injury period for determination and not consider post POI period for determination. In the matter of SBR and STPP, the Designated Authority recommended ADD despite the fact made known at the time of recommendation that the concerned domestic industry had ceased production. Authority conducted MTR subsequently and recommended withdrawal of ADD. However, the original investigation remained unaffected by cessation of production.
- xviii. If the interested parties feel that there is material change in the situation after the POI, they can seek midterm review.
- xix. There is no production of PUC in Hong Kong and the exporter from Hong Kong has admitted having exported PUC. If goods produced in China have been exported from Hong Kong, no case can be made out against Hong Kong for imposition of anti dumping duty. Authority is required to determine possible transshipment of the goods. Domestic industry is not required to provide evidence of Hong Kong.

EXAMINATION BY AUTHORITY

41. With regard to miscellaneous submissions made, Authority holds as follows:-
42. The petition for imposition of anti dumping duty on the product under consideration was filed before the present Authority way back in the year 2013. However, on being prima facie satisfied the anti dumping investigation got initiated on 1st February 2016.
43. Whereas, the anti subsidy/countervailing duty investigation was initiated on 29th May, 2014 vide notification no. 17/6/2013-DGAD pursuant to which the final finding was recommended by the Authority on 27th November, 2015 and CVD was imposed by the ministry of finance dated 19th January, 2016 vide notification No. 1/2016-Customs(CVD).
44. Authority initiated the ADD investigation based on the petition having all information for the period April 2014-March 2015. Considering it necessary to examine the data for period closer to the initiation and accordingly, for the purpose of this investigation the Authority extended the period of investigation to April 2014- Sept 2015.
45. Petitioners filed the non confidential version of the petition vide letter dated 29th September, 2015 based on IBIS data, having POI April 2014-March 2015. In due course petitioner filed the updated petition having extended POI April, 2014-September, 2015, vide letter dated 4th April, 2016, received in 4th April 2016. The said information was based on April, 2014-September, 2015 on IBIS data. However due to some calculation error in the figures of imports and return on capital employed petitioner filed a revised data on vide letter dated 4th April, 2016 which was received in DGAD on 18th April, 2016 based on IBIS data.
46. Referring to the arguments during the first public hearing regarding multiple submissions by the DI and data inconsistencies therein, the Authority asked the domestic industry to furnish a full submission containing the correct data along with a non-confidential version which will be placed in the public folder and notified to the interested parties. In response to the said mail the petitioner filed the updated data of M/s Bradken along with other information via letter dated 12th September, 2016 for the POI April, 2014-September, 2015 based on DGCI&S data.
47. Regarding argument of difference in data provided by the petitioners and that available publically, it is noted that the findings of the Authority is based on the verified data. Further, public statements do not alter the conclusion based on verified data by the Authority. The discrepancy was resolved by the petitioner vide the above mentioned letter dated 12th September, 2016 and explained the discrepancy in the data while acknowledging the error made.
48. As regards the argument of dual remedy and forum shopping being done by petitioner, the Authority notes that the purpose of anti subsidy/countervailing/anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidized imports and dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market. The CVD duty was imposed on 19th January, 2016. While levying any ADD Authority will consider the requirements under Customs Tariff Act, 1975 and no double counting will be done to the extent of export subsidies. In the event of Designated Authority making a positive determination and deciding to recommend anti dumping duty, it is clarified that the Central Govt. shall be requested to adjust the anti-subsidy/countervailing duty payable, if any.
49. Regarding the contention raised that the petitioner has given the NCV petition dated 29th September, 2015, referring to Initiation Notification issued on February 1, 2016 projecting wrong POI beneath the injury data, domestic industry accepted that this was a typographical error and that as per practice being followed in the DGAD is non-confidential version of the Petition is required to be filed after issuance of the Initiation Notification.
50. Looking at the wide range of products scope and to have a fair comparison, the Authority has considered regrouping PCN, which was communicated to the interested parties vide letter dated 25th May, 2017.
51. With regard to the contentions raised that the imports of PUC coming from Hong Kong, Hong Kong is not the subject country for the present investigation.

Market Economy Treatment (MET), Normal Value, Export Price and Dumping Margin**a. NORMAL VALUE**

52. 'Normal Value' under the Rules- Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Submissions by exporter, importer and other interested parties

53. The following are the submissions made by exporters/importers/other interested parties have made any submissions in this regard:

- i. As per the Initiation Notification, normal value has been claimed on the basis of cost of production in India, duly adjusted. This is in contravention of the requirements of law under Annexure 1(7) of the ADD Rules the Authority has relied upon the data provided by the petitioners, which is the last option provided under Rules. Authority can resort to the last option only if first two options of paragraph 7 of Annexure I are exhausted.
- ii. Methodology used for working Normal value, is vague and does not meet requirements set out In Para-7 of Annexure-I of the AD rules.
- iii. AB Report on the “Fasteners Case” has provided strong justification for China to automatically obtain the market economy status once the article 15 of protocol expires. China has been performing its obligation seriously since its accession and India must fulfill its obligation under agreements to recognize China’s full market economy status and stop using the “surrogate country” approach in anti-dumping investigations.
- iv. After 11th Dec, 2016, India has no legal basis to calculate normal value in anti-dumping investigation against Chinese products using the non-market economy methodology and any such action will be inconsistent with the GATT, 1994 and other agreements.
- v. No calculation provided as to how ex factory export price was arrived at. The calculation is unsubstantiated and highly speculative. Unclear how grade to grade comparison is made. Provide dumping margin calculation in complete and substantiated manner.

Submissions by Domestic industry

54. The domestic industry inter alia submitted as follows:

- i. China is a non-market economy country and no country has granted market economy status to China. Further none of the exporters satisfy each and every condition developed from jurisprudence to qualify for grant of market economy status. Thus, the Chinese producers’ cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.
- ii. Normal value must be “comparable price in the ordinary course of trade for the like article when meant for consumption in such market economy third country”. In order to arrive at normal value on this basis, the Designated Authority shall require complete and exhaustive verifiable information on all domestic sales made by a cooperating producer in such third country, along with its cost of production and all other associated information and evidences.
- iii. Petitioner has not been able to procure information in respect of any country and resorted to the last option as they did not have information required for an appropriate market economy third country.

- iv. The interested parties had sufficient time and opportunity since initiation of investigation to suggest an appropriate market economy third country and produce appropriate evidence for the same. There is no bar in interested parties suggesting an appropriate market economy third country.
- v. India is an appropriate surrogate country for China as it would result in access to accurate and adequate information. Further, India has been considered as an appropriate surrogate country by other investigation authorities too.
- vi. In proceedings under SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.
- vii. Article 15(b) implies that provisions of Clause 15(a)(ii) shall expire 15 years from date of China's Accession. The effect of this provision is that the DA is not considering costs and price in China in order to determine normal value.
- viii. Chinese producers should be treated as companies operating under non-market economy environment and normal value determined on the basis of Para 7 of Annexure-I till such time the investigation period includes the period up to Dec., 2016.
- ix. POI in the present case is April 2014- September 2015, the provisions of article 15 shall be fully applicable to the present investigation period. The normal value in China should be determined on the basis of Para-7 of Annexure-I.
- x. Provisions of Article 15(a) (i) are still applicable and must be considered for determination of normal value in China. There cannot be any other interpretation of the above provisions. The Designated Authority may therefore kindly direct the Chinese produces to show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product under consideration, so that the Designated Authority can use Chinese prices or costs for the industry under investigation.
- xi. The responding exporters must establish that the elements of costs referred to in the context of determination of normal value are appropriately and completely reflected in the records kept by the exporter or producer under investigation. In case some elements of costs are not appropriately and completely reflected in the records kept by the exporter or producer under investigation, the Designated Authority shall reject the claim of individual dumping margin.
- xii. The Designated Authority shall follow Para 1-6 for determination of normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined. If the responding Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Designated Authority shall reject the claim of individual dumping margin.
- xiii. Authority should determine Normal Value in China on the basis of cost of production in India, duly adjusted with selling, general and administrative expenses and considering the consumption norms of the petitioners.
- xiv. PUC is produced and sold in a number of different types/forms which differ significantly in terms of associated costs and/or prices. Therefore the petitioner has devised a PCN system which is used for identifying the product type involved in individual transactions.
- xv. PCN has been used to arrive at the dumping and injury margin.
- xvi. Export price has been determined as the weighted average import price, separately for each PCN. Export price has been calculated at the CIF level. According to the WTO Agreement on Anti Dumping and Indian Rules, comparison of normal value and export price should be done at same level of trade. Therefore, the export price has been adjusted for Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Port Expenses, Bank charges and Inland freight expenses which may have been incurred by the exporter for exporting the material to India.

Examination by the Authority- China as non-market economy

55. Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- (a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
 - (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
 - (ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- (b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
- (c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

56. Authority notes that following exporter/producers have responded and filed questionnaire response.

- a. Dalian Huarui Heavy Industry Casting Co. Ltd.
- b. Jiangsu Faw Foundary Co., Ltd.
- c. Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd.
- d. Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co., Ltd
- Changzhou Sinojit Wind Energy Tech. Co. Ltd
- Jiangyin Henghua Machinery Co., Ltd. Jiangyin City
- Jiangyin Qixing Technology Co., Ltd. Jiangyin City
- Jiangyin Changling New Energy Co., Ltd. Wuxi City, Jiangsu
- Techtone HK, Ltd

- e. Nantong Hongde Mechanical Co. Ltd
 - KOZUMI Machinery co. Ltd
 - Nantong Hongde Mechanical Co. Ltd
- f. Yeong Guan Energy Tech. Group Company Limited
 - Dongguan Yeong Guan Mould Factory Co., Ltd.
 - Jiangsu Bright Steel Fine Machinery Co., Ltd
 - Ningbo Lu Lin Machine Tool Foundry Co. ,Ltd
 - Ningbo Yeong Shang Casting Iron Co. Ltd.
 - Yeong Chen Asia Pacific Co., Ltd.

57. Except for Yeong Guan Energy Tech. Group Company Limited., China PR and its subsidiaries none of the producers/ exporters from China PR have responded to the Market Economy Treatment (MET) Questionnaire. Hence, the other, cooperating exporters have been given non-market economy treatment in the present investigation. Yeong Guan Energy Tech. Group Company Limited., China PR and its subsidiaries claimed market economy treatment and has submitted Market Economy Treatment (MET) questionnaire response.

58. Yeong Guan Energy Tech. Group Company Limited., China PR and its subsidiaries have requested for MET status. Following are the related companies-

- i. Yeong Guan Energy Tech. Group- Dongguan Yeong Guan Mould Factory Co., Ltd.
- ii. Yeong Guan Energy Tech. Group- Jiangsu Bright Steel Fine Machinery Co., Ltd
- iii. Yeong Guan Energy Tech. Group- Ningbo Lu Lin Machine Tool Foundry Co. Ltd
- iv. Yeong Guan Energy Tech. Group- Ningbo Yeong Shang Casting Iron Co. Ltd.
- v. Yeong Guan Energy Tech. Group- Yeong Ghen Asia Pacific Co., Ltd.

59. The exporter group company has submitted as follows-

- i. Each of the five subsidiaries is indirectly owned by the Company through Yeong Guan International Co., Limited (“Yeong Guan HK”), a company incorporated under the laws of Hong Kong and is wholly owned by the Company. All these companies are wholly owned by the Company, a publicly-traded company in Taiwan, and thus are 100% foreign invested subsidiaries.
- ii. The Company is a listed company in Taiwan acting as a holding company registered in the Cayman Islands. Its business operations are carried out by subsidiaries wholly owned directly or indirectly by the Company in China PR and Taiwan. During the P01, all exports of the PUC by Yeong Guan Group to India were manufactured in China PR while exporters are (i) Yeong Shang Ningbo and (ii) Yeong Chen Taiwan. The other three subsidiaries, Bright Steel Jiangsu, Yeong Guan Dongguan and Lu Lin Ningbo, manufactured the PUC in China PR, and sold the same in China PR except that they sold the same to related companies for them to resell to third countries (including India) during the POI.
- iii. As the Company is a public company, there are only two shareholders who hold at least 5% of the shares of the Company. The two shareholders of the Company are individuals and are nationals of Taiwan. Yeong Guan HK is the sole shareholder of each of the Four Subsidiaries except for the Bright Steel Jiangsu, which is partly owned by Yeong Guan HK and Yeong Guan Dongguan. The Company is the sole shareholder of Yeong Guan HK. The Company is a Cayman company, and is listed on the Taiwan Stock Exchange.
- iv. All the suppliers are private companies incorporated in China PR. The Yeong Guan Group did not purchase any raw materials from any person who is a government officer, or from any company which is governed-owned or controlled. The purchase prices of the raw materials were determined by negotiations between the parties, taking into account the market conditions, and were in line with market prices. All utilities are charged at normal rates. There is no restriction or condition on imports of raw materials used by the Company or its Five Subsidiaries.

- v. Yeong Guan Group offers selling prices of the PUC by taking into account key business considerations including market conditions, cost of production, ordered quantity and delivery schedule, and other sales terms. All selling prices are subject to direct negotiations between Yeong Guan Group and its customers, and are determined after Yeong Guan Group and customers reach an agreement. The selling prices are not subject to review or guidance from any Government.
- vi. The management of the Company is decided by its Directors. The management team does not require approval from the Government, or required to notify the Government, except that the Chief Finance Officer should be registered with the Ministry of Finance of China PR for the purpose of tax filing. The management of the Company and Five Subsidiaries is under the control of their Directors. Before they became Directors of the Company and Five Subsidiaries, they all worked for private companies. There is no restriction on use of export revenues of the Company or its Five Subsidiaries. The bank account is held under name of the Company or Five Subsidiaries as the case may be.
- vii. The employees of the Company are remunerated with salary, overtime pay, and statutory allowances once a month. Overtime pay and allowances to the employees are paid in terms of applicable laws. Compensation to the employees is paid monthly. Each of Five Subsidiaries is the final payer for its employees. According to the Chinese Labor Law, a company should contribute funds for five types of insurances and housing, which include endowment, medical, unemployment, employment injury, maternity, and housing provident fund for the employees. The Company or its Five Subsidiaries hires 2 employees with Malaysian nationality, and many of its key management is of Taiwan nationality.

60. Article 15 implies that provisions of one of the subparagraph shall expire 15 years from date of China's Accession. The provisions of this paragraph expired in 11th Dec., 2016. Since the factum of dumping causing injury to the domestic industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone is relevant, appropriate and necessary for the purpose of present investigation. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is April, 2014 to September, 2015. Since the subparagraph of Article 15 was in existence during the period of investigation, the Authority may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

61. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules.

62. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti-Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provides information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and prove to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China PR are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether: -

- a. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- b. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- c. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
- d. The exchange rate conversions are carried out at the market rate

63. In view of the above position and in the absence of rebuttal of non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proposes to proceed with para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.

Normal value determination for China PR

64. In view of the above, the Authority has determined normal value having regard to para-7 of Annexure-I for the purpose of present investigation. The normal value for the subject products imported from China PR into India has been constructed considering optimum consumption norms of the domestic industry for major raw materials, cost of raw materials as per domestic industry prices, conversion cost, interest, SGA etc. at the levels allowed for the domestic industry. Besides a margin of *** % on cost of sales excluding interest has been allowed towards reasonable profit.

EXPORT PRICE

65. The following producers/exporters groups filed exporter's questionnaire (EQ) response in the present investigation-

- a. Dalian Huarui Heavy Industry Casting Co. Ltd.
- b. Jiangsu Faw Foundary Co., Ltd.
- c. Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd.
- d. Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co., Ltd.
 - Changzhou Sinojit Wind Energy Tech. Co. Ltd
 - Jiangyin Henghua Machinery Co., Ltd. Jiangyin City
 - Jiangyin Qixing Technology Co., Ltd. Jiangyin City
 - Jiangyin Changling New Energy Co., Ltd. Wuxi City, Jiangsu
 - Techtone HK, Ltd
- e. Nantong Hongde Mechanical Co. Ltd
 - KOIZUMI Machinery co. Ltd
- f. Yeong Guan Energy Tech. Group Company Limited
 - Dongguan Yeong Guan Mould Factory Co., Ltd.
 - Jiangsu Bright Steel Fine Machinery Co., Ltd
 - Ningbo Lu Lin Machine Tool Foundry Co. ,Ltd
 - Ningbo Yeong Shang Casting Iron Co. Ltd.
 - Yeong Ghen Asia Pacific Co., Ltd.

66. After examination of the responses, the exporter's data was verified by the Authority. The DGCI&S data has been examined. The data submitted by the exporters were verified and the appendix wise response to the exporter's questionnaire was taken up for examination.

67. In view of the above, the Authority has accepted the data submitted by the producers/exporters and verified subsequently by the Authority for determination of export price and dumping margin. For the responding exporter whose export prices and price adjustments have been verified, the export price has been determined after taking into account their prices to India given in their appendix wise information and all adjustments claimed by them and verified by the Authority.

68. The Authority has determined the export price for other non-responding exporters as per the facts available on record.

69. The dumping margin thus arrived has been given group wise in the tabular form below.

Dumping Margin

70. The export price to India (net of all the adjustments claimed by the exporter and accepted by the

Authority) have been compared with the normal value to determine dumping margin. The dumping margin during the POI for all exporters/producers from subject country has been determined as provided in the table below:

DUMPING MARGIN TABLE						
Sl. No.	Producer	Exporter	Normal value US\$/MT	Export price US\$/MT	Dumping Margin US\$/MT	Dumping Margin %
1.	Dalian Huarui Heavy Industry Casting Co. Ltd	Dalian Huarui Heavy Industry Casting Co. Ltd	***	***	***	15-25
2.	Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd.	Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd.	***	***	***	15-25
3.	Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co., Ltd ➤ Changzhou Sinojit Wind Energy Tech. Co. Ltd ➤ Jiangyin Henghua Machinery Co., Ltd. Jiangyin City ➤ Jiangyin Qixing Technology Co., Ltd. Jiangyin City ➤ Jiangyin Changling New Energy Co., Ltd. Wuxi City, Jiangsu	Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co., Ltd Tectone HK, Ltd	***	***	***	15-25
4.	Nantong Hongde Mechanical Co. Ltd KOIZUMI Machinery Co. Ltd	Nantong Hongde Mechanical Co. Ltd	***	***	***	15-25
5.	Jiangsu Faw Foundary Co., Ltd.	Jiangsu Faw Foundary Co., Ltd.	***	***	***	30-40
6.	Yeong Guan Energy Tech. Group Company Limited ➤ Dongguan Yeong Guan Mould Factory Co., Ltd. ➤ Jiangsu Bright Steel Fine Machinery Co., Ltd ➤ Ningbo Lu Lin Machine Tool Foundry Co., Ltd ➤ Ningbo Yeong Shang Casting Iron Co. Ltd. ➤ Yeong Ghen Asia Pacific Co., Ltd.	➤ Ningbo Yeong Shang Casting Iron Co. Ltd. ➤ Yeong Ghen Asia Pacific Co., Ltd	***	***	***	15-25
	Residual other		***	***	***	45-55

INJURY AND CAUSAL LINK**Submissions by exporter, importer and other interested parties**

71. The following submissions were made by producers/exporters/importers/other interested parties with regard to injury to the domestic industry:

- i. DA should not have initiated the present investigation & should be accordingly terminated forthwith as the information and documents submitted by the Petitioner are incomprehensible and misleading with regard to various parameters.
- ii. Firmly rejects the allegations that there is an injury and dumping and/or that there is a threat of material injury, if measures are not imposed.
- iii. Injury suffered by the DI, *quod non*, is not attributable to imports originating in china. The losses experienced by the DI are not caused by the imports from China
- iv. POI as in the Initiation Notification is April 2014 to Sept 2015, whereas all information given in the petition pertains to April 2014 to March 2015. In absence of accurate and exact data of POI what basis Authority has initiated the investigation and has sought comments from other interested parties. Authority should instruct the DI to provide all injury parameters for the POI as in the Initiation Notification.
- v. No significant increase in the volume of imports. The evidence presented simply fails to demonstrate that imports have caused any injury to DI. Imports did not have negative effects in the prices of domestic industry and injury suffered, *quod non*, is artificially created.
- vi. The landed price has therefore increased between the two POIs despite the decrease in the customs duty levied on the subject goods from 7.5% to 5%.
- vii. Increased volume of imports does not indicate dumping of the PUC in the Indian Market nor does it indicate that any exponential growth of market share of the PUC from the Subject Country.
- viii. Demand Claimed in the Petition for CVD Investigation, Petition for AD Investigation and Final Findings issued in CVD Investigation do not match.
- ix. Price undercutting claimed by the Petitioner is incorrect.
- x. DI is performing well and growth is positive. Proforma IV (A) needs proper analysis and not to conceal information.
- xi. DI managed to increase its production, market share, capacity utilization, domestic sales and labor force undoubtedly underscores that it is a thriving industry that has not suffer any injury. Cost of production of DI has decreased.
- xii. Return of 22% on capital employed is added to the cost of production to determine NIP.
- xiii. Increase in demand of the domestic industry showing substantial increase in the sales volume and increase of about 8% in the market share of the DI in the POI
- xiv. There is no apparent handicap/material injury caused to the DI due to imports of the PUC.
- xv. Lack of correlation between the import volume and the profit of the DI. When the import volume sharply declined the DI profitability declined whereas when imports were increasing DI witnessed a positive trend.
- xvi. Increase in the number of employees during the period considered for the injury determination while the wages dropped.
- xvii. No clear methodology employed for determining injury margin and appears totally incorrect and misleading. The injury margin claimed by the petitioner is unrealistic based on the data submitted and has dramatically increased compared to the injury margin established in anti-subsidy investigation.
- xviii. Suspension of the production at the Kansbahal unit should be seen as an extraordinary expense within the meaning of Annexure III, para 4(iv) and should not be charged to the cost of production.

- xix. The troubling element in the economic factors of the Petitioner is reduction in the production capacity that is not reflected in its fixed assets.
- xx. Various inconsistencies and contradictory claims made in the Petition and the facts reported by DI in its Audit Reports.
- xxi. CESTAT in the matter of Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) Vs. DA, held that injury determination and causal link should be carried out in a convincing manner and the absence of the same may lead to setting aside of the imposed anti-dumping duty.
- xxii. No correlation between import price and DI's price movement. No reason for the DI to reduce the selling price specially during POI when the Import price increased
- xxiii. No Causal link between import prices and profitability of the domestic industry. Injury due to business strategies. Injury due to plant shut down during Period of investigation.
- xxiv. Injury due to other factors such as Imports from Hong Kong. Import price from Hong Kong is lower than of China. After imposition of CVD on China, so there is no possibility that imports from China has caused injury to the DI.
- xxv. The product sold by DI or the techniques used by them is of inferior quality. The DI fails to meet the technical specifications of the product. That is the major reason why import from the subject country is continued even after imposition of CVD. L&T's raw castings are transported to other places which takes involves more time and cost.
- xxvi. Losses due to loss in wind energy sector. The DI suffered severe losses in the same year when wind energy sector was going through losses. This cannot be a mere coincidence. Wind capacity expansion in 2013 lead to decrease in accelerated depreciation and Generation based incentives. This could be a reason of injury to the DI. So the DI suffered major losses in 2013.

Submissions made by the Domestic Industry

72. The petitioner has initially provided information for the POI, April 2014-March 2015 on the basis of the investigations were initiated by the Authority. The Authority considered it necessary to examine the data for period closer to the initiation and accordingly, period of investigation (POI) April 2014- Sept 2015 was filed by the domestic industry for the extended Period as above.

73. Petitioner has provided all revised information post initiation for the period April 2014- Sept 2015 for investigation. The injury investigation period will however, cover the period 2011-12, 2012-13, 2013-14 and April 2014- Sept 2015 (POI). The domestic industry has inter alia made the following submissions with regard to the injury and causal link:

- i. Total imports as well as the imports from the subject country have declined from the base year till the year 2012-13, further increased till the POI. The market share in demand of the subject country has remained constant.
- ii. The imports from China from 2010-11 to Post POI, 2015-16, there is a drastic increase in the import volumes even after imposition of the CVD. With regard to market share, subject country imports increased over the injury period.
- iii. The subject country imports declined due to the decline in demand in the year 2012-13 and 2013-14 due to the global recession. However, this can be seen in the light of increased market share of the subject country imports in the same year.
- iv. Decline in demand from the base year till the year 2012-13, further increased till the POI. Petitioner is having the capacity alone that can meet current and potential demand in the Country, however, not been able to do so due to continuous presence of dumped imports.
- v. Imports in relation to consumption have increased throughout the injury period and Imports in relation to production have declined from the base year till the year 2013-14 and further increased in the POI.
- vi. Landed prices of imports have been significantly below the selling prices of the domestic industry, thus resulting in significant price undercutting.
- vii. The cost of sales of the subject good has increased from the base year in the year 2012-13 and

further declined till the POI. The selling price of the subject good has declined throughout the injury period. The domestic industry was forced to reduce its selling prices far below cost resulting in price depression and significant financial losses. The imports of subject goods are significantly suppressing and depressing the prices of the domestic industry. Thus, the effect of dumped imports on the domestic industry has been adverse and significant.

- viii. Designated Authority must consider overall performance and not adopt pick & choose position.
- ix. The production of the product under consideration has declined from the base year in the year 2012-13 and further increased in the year 2013-14 and the POI despite sufficient demand in the Country;
- x. The capacity utilization of the domestic industry is suffering adversely and declined very significantly from base year to year 2012-13 and further increased till the POI.
- xi. Sales of the domestic industry have followed the same trend as like capacity utilization.
- xii. Profitability of the domestic industry has deteriorated significantly as DI is suffering significant financial losses over the injury period. The cash profits showed the same trend as profits of the domestic industry and DI is suffering significantly negative return on investment for past sometime.
- xiii. Price parameters of the domestic industry are very significantly impacted and deteriorated due to dumping of the product.
- xiv. The return of 22% has been adopted by the DI as per the usual practice of the Authority.
- xv. NFA decreased by 34% over the injury period.
- xvi. Domestic industry has reduced the selling price in order to match the price of the dumped imported goods. Also the variants of PUC are of different prices and the average price or the weighted average price may give the misleading picture.
- xvii. The growth of the domestic industry in terms of volume has been positive whereas in terms of price parameter is negative
- xviii. Given the state of affairs of the domestic industry where running the product is consistently not performing well because of persistent dumping over last few years, substantial fresh investments cannot even be imagined. The domestic industry is already holding significant capacities.
- xix. The NIP calculated by the Authority in the anti-subsidy investigation was done going beyond the law and taken the estimated capacity utilization for normation instead of actual capacity utilization.
- xx. The PUC is having various types of products, due to which the Authority has derived the PCN. The cost of production varies as per the product type produced as well as the machining done. Thus the average cost of production of the DI is misleading.
- xxi. The product under consideration is a labour-intensive product. Further, given that the petitioner is a multi product company and given the labour laws in the Country, these parameters may not show adverse effect of dumping.
- xxii. The numbers of employees increased over the injury period. The wages paid have drastically declined over the injury period. Further, wage cost per unit of production has significantly declined over the injury period. If wage cost per unit of production incurred in base year is considered for the POI, it would be seen that the losses in the POI would have been much higher.
- xxiii. The petitioner is unable to find that which audit report is being referred by the exporter. The previous domestic industry, M/S L&T was the multi-product company and the data presented thereof does not show the clear picture of the injury faced by the castings segment of the company.
- xxiv. Petitioner has not concealed anything. Designated Authority may verify and then adopt the data. Domestic industry has not sought blind acceptance of its information.
- xxv. The submission made by the exporter is wrong as there was no shut down of the plant during the POI. Only the production of the subject goods was suspended from the Kansabahal unit in the year 2013.

- xxvi. CVD imposed on China has not completely addressed the injury being faced by the domestic industry.
- xxvii. Material injury is being caused to domestic industry from dumped imports from subject country. There is no legal basis for the contention that since the domestic industry has suffered injury on account of other factors also, there cannot be injury to the domestic industry from dumped imports. The placement of the word "a" (and not "the") before causal link clearly implies that the Authority shall record a positive finding of dumping causing injury so long as dumping is "one of the causes" of injury to the domestic industry.
- xxviii. The factors identified by the interested parties do not establish that it is the other factors which have alone caused injury to the domestic industry. At the same time there is clear evidence that the price deterioration in the market is due to dumped imports.
- xxix. The recession in the wind energy sector was in the year 2012-13 and not throughout the injury period and injury faced due to withdrawal of accelerated depreciation and Generation based incentives have been already taken in account during the year 2012-13.

Examination by the Authority

74. The Authority has taken note of submissions made by the interested parties. The Authority has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Antidumping Rules and considering the submissions made by the other interested parties.

75. Rule 11 of AD Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, *"....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...."*

76. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the AD Rules.

77. Further, it is noted that while imposing anti-dumping duty the position that has to be considered is not in the context of ideal conditions but in the specific circumstances of the domestic industry.

78. As regards the submissions of absence of injury, the injury analysis carried out hereunder is self explanatory to establish that the dumping has caused injury to the domestic industry.

79. Further, public statements like annual reports of companies do not alter the conclusion that dumping of the product has contributed to injury to the domestic industry.

80. As regards the submission that separate injury analysis is required, the Authority notes that as per the Anti-dumping Rules, injury is required to be determined for the domestic industry as a whole.

81. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as below:

82. The AD Rules require the Authority to examine injury by examining both volume and price effect. A determination of injury involves an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic industry. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

83. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure II of Antidumping rules states as under:-

(iv) *The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.*

84. It is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration; while some may show improvement. The Designated Authority considers all injury parameters and thereafter concludes whether the domestic industry has suffered injury due to dumping or not. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments in the submissions.

Assessment of Demand

85. The demand of the product under consideration in India has been determined as the sum of sales of the Indian producers and imports from all sources. The Authority notes that the demand of the product under consideration has increased over the injury period.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI (A)
Sales of Domestic Industry	MT	8,079	5,133	5,908	11,242
Sales of Other Indian Producers	MT	7,368	3,076	3,201	3,321
Subject countries-Imports	MT	15,117	10,430	13,751	17,941
Other Countries-Imports	MT	1,661	502	282	2,190
Total Demand	MT	32,225	19,141	23,142	34,693

86. It is noted that the demand of the subject goods have declined from the base year to the year 2012-13 due to recession in the particular sector, though increased further throughout the injury period.

Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry

87. Annexure II (ii) of the anti dumping rules provides as under:

“While examining the volume of dumped imports the said authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the designated authority shall consider whether there has been a significant price under cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred, to a significant degree.”

i. Import volume in absolute and relative terms-

88. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. As per this data the imports of the subject goods during the injury investigation are as follows:

Imports - Volume	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI (A)
China	MT	15,117	10,430	13,751	17,941
Other Countries	MT	1,661	502	282	2,190
Total Imports	MT	16,778	10,932	14,033	20,131
Subject country Imports					
In Relation to Consumption	%	47%	54%	59%	52%
In Relation to Indian Production	%	87%	121%	129%	116%
In relation to total imports	%	90%	95%	98%	89%

89. It is noted that that

- i. The total imports as well as the imports from the subject country have declined from the base year till the year 2012-13, further increased till the POI.
- ii. Imports from subject country in relation to consumption have increased from the base year till the year 2013-14 and declined slightly in the POI.
- iii. Imports from subject country in relation to production have increased from the base year till the year 2013-14 and declined slightly in the POI.
- iv. Imports from subject country in relation to imports have increased from the base year till the year 2013-14 and declined slightly in the POI.

ii. Market Share

90. It may be seen that imports from the subject country in India have declined from the base year till the year 2012-13 and further increased till the POI.

91. The market share in demand of the subject country has increased from the base year till the year 2013-14 and further declined in the POI.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI (A)
Sales of Domestic Industry	MT	8,079	5,133	5,908	11,242
Sales of Other Indian Producers	MT	7,368	3,076	3,201	3,321
Subject country	MT	15,117	10,430	13,751	17,941
Other Country	MT	1,661	502	282	2,190
Total Demand	MT	32,225	19,141	23,142	34,693
Market Share in Demand					
Sales of Domestic Industry	%	25%	27%	26%	32%
Sales of Other Indian Producers	%	23%	16%	14%	10%
Subject country	%	47%	54%	59%	52%
Other Country	%	5%	3%	1%	6%
Total Demand	%	100%	100%	100%	100%

92. Further, so long as the domestic industry charges prices in competition to imports and comparable to imports, the domestic industry has no problems in selling the product.

Price effect of dumped imports and impact on domestic industry

93. Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price under cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

94. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

95. In order to determine whether imports from the subject country were adversely effecting the prices of Domestic industry, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level.

96. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject country have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression.

i. Price undercutting effects of dumped imports

97. The Authority has devised a PCN system (as explained in section I above) which is used for identifying the product type involved in individual transactions. As the PCN mix of imports and that of domestic sales are varied, average of all imports and domestic sales have been considered for analyzing price undercutting effects.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI-A
Landed price of imports	Rs/MT	94,417	115,838	123,971	121,024
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	50-60%	10-20%	0-10%	(20)- (10)%

ii. Price underselling

98. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from China PR. For this purpose, the NIP determined for the domestic industry has been compared with the landed price of imports for each product type. Comparison of weighted average NIP of the domestic industry with weighted average landed price of imports shows as follows:

Particulars	Rs/MT	US\$/MT
Non Injurious Price (NIP)	***	***
Landed Price	121,024	1,931
Injury Margin	***	***
Injury Margin-%	***	***
Injury Margin (Range)	15-25%	15-25%

iii. Price Suppression / Depression

99. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI (A)
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
Index		100	114	94	70
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Index		100	88	88	71

100. It is noted that

- i. the domestic industry cost of sales increased in the second year but decreased significantly thereafter.
- ii. The selling price of the subject good has declined throughout the injury period.

iii. The cost of sales and selling price have declined in sync, when compared with base year.

101. The petitioner was forced to reduce its selling prices far below cost resulting in price depression and significant financial losses. The imports of subject goods are significantly suppressing and depressing the prices of the domestic industry. Thus, the effect of dumped imports on the domestic industry has been adverse.

Economic parameters of the domestic industry

102. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that

“the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”

103. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

i. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

104. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization was as follows:

Parameters	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI (A)
Capacity	MT	30,000	30,000	30,000	30,000
Index		100	100	100	100
Production - PUC	MT	9,923	5,574	7,434	12,157
Index		100	56	75	123
Production - NPUC	MT	3,382	2,982	343	757
Index		100	88	10	22
Total Production	MT	7,907	8,556	7,778	12,914
Index		100	108	98	163
Capacity Utilization	%	26%	29%	26%	43%
Plant Utilization	%	35%	22%	26%	43%
Index		100	108	98	163
Domestic Sales	MT	8,079	5,133	5,908	11,242
Assessed Demand	MT	32,225	19,141	23,142	34,693

105. The following is noted from the above table:

- i. Domestic industry has sufficient capacity to meet current and potential demand in the Country;
- ii. The production of the product under consideration has declined during 2012-13 but increased consistently thereafter.
- iii. The decline in production is despite sufficient demand in the Country;
- iv. The capacity utilization of the domestic industry is suffering adversely. Capacity utilization has declined from base year to year 2012-13 and increased thereafter but it remained sub-optimal;
- v. Sales of the domestic industry have followed the same trend as like capacity utilization.

ii. Market Share in Demand

106. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI (A)
Market Share in Demand					
Sales of Domestic Industry	%	25%	27%	26%	32%
Sales of Other Indian Producers	%	23%	16%	14%	10%
Subject country	%	47%	54%	59%	52%
Other Country	%	5%	3%	1%	6%
Total Demand	%	100%	100%	100%	100%

107. It is noted that

- i. market share of the domestic industry has remained mostly constant during 2011-12 to 2013-14 and increased during POI.
- ii. whereas market share of the subject country has increased from the base year till the year 2013-14 and declined in the POI.
- iii. Market share of other Indian producers has declined significantly over the period.
- iv. Further, market share of other countries have also decreased from the base year till the year 2013-14 and increased in the POI.

iii. Profitability, return on investment and cash profits

108. The profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry has been analysed as follows:

Profit /(Loss)	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI (A)
Profit/(Loss)	Rs.Lacs	***	***	***	***
Index		-100	-745	-265	-76
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Index		100	-170	24	93
PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***
Index		-100	-757	-264	-75
ROCE -NFA	%	***	***	***	***
Index		-100	-1,119	-501	-151

109. The domestic industry suffered losses throughout injury period though it made cash profits during 2013-14 and POI. All parameters show worst performance during 2012-13 which improved subsequently, though overall performance is negative.

iv. Employment and Wages

110. The position with regard to employment, wages and productivity is as follows:

Parameters	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI (A)
No. of Employees	Nos	***	***	***	***
Index		100	100	105	108
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Index		100	70	43	45

111. It is noted that the employment levels of the domestic industry has remained consistent throughout the injury period whereas the wages have declined throughout the injury period.

v. Inventory

112. Inventories have been NIL during injury period. The subject goods are “make to order” product. Thus the criterion of inventory is not the proper parameter to evaluate the injury in this case.

vi. Growth

Growth year by year	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI (A)	POI*
Production - PUC	%	-	-29%	33%	42%	42%
Domestic Sales Volume	%	-	-36%	15%	60%	60%
Cost of Sales/Unit	%	-	14%	-18%	-17%	-17%
Selling Price/Unit	%	-	-12%	0%	-13%	-13%
Profit/ Loss/Unit	%	-	1073%	-69%	-56%	-56%
Return on Capital Employed (ROCE)	%	-	-16%	10%	5%	5%

113. With the rising demand of the product in the country, the growth of the domestic industry in terms of volume has been positive after 2012-13 whereas in terms of price parameter, growth was negative. Though parameter of growth in ROCE show improvement since 2013-14, it is noted that ROCE was negative throughout the injury period

vii. Ability to raise capital investments

114. The domestic industry is already holding significant capacities. In the event of consistent non-performance, substantial fresh investment cannot be envisaged.

viii. Level of dumping & dumping margin

115. The Authority notes that the dumping margin from subject country is not only more than de minimis but also very substantial. The impact of dumping on the domestic industry is significant.

ix. Factors Affecting Domestic Prices

116. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of the imported material from the subject country is below the selling price and the non-injurious price of the domestic industry, causing significant price under selling in the Indian market. Thus, the factor affecting the domestic prices is landed value of the subject goods from the subject country.

x. Causal Link

117. The Authority has examined other factors listed under the Antidumping Rules which could have contributed to injury to the domestic industry for examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry.

I. Imports from third countries

118. The Authority has examined the imports data of the subject goods from DGCI&S. In the present scenario the imports are coming from Hong Kong.

II. Contraction in demand

119. There has been rise in demand post year 2012-13, of the product concerned over the injury period. Possible decline in demand could not have caused injury to the domestic industry.

III. Changes in the patterns of consumption:

120. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any

significant change. Changes in the pattern of consumption could not have, therefore, contributed to the injury to the domestic industry.

IV. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:

121. The Authority notes that there is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

V. Developments in technology:

122. Technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.

VI. Export performance:

123. The Authority notes that Petitioner does not have exports of the product under consideration, thus claimed injury to the domestic industry is not on account of exports.

VII. Subsidization of the product:

124. The Authority notes that the product under consideration is being subsidized by the Govt. of China. Designated authority has already imposed anti subsidy/countervailing duty on the subject goods.

VIII. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry:

125. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only. Claimed injury to the domestic industry is on account of product under consideration.

xi. Factors establishing causal link

126. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated due to dumped imports from the subject country. Causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

- i. There is significant difference between the prices offered by the domestic industry and foreign producers. Resultantly, domestic industry suffered volume injury as domestic industry could not take its production and sales to the optimum level;
- ii. Resultantly, domestic industry was not able to get sufficient sales volumes. Thus, despite significant demand in India, the domestic industry was not able to utilize its capacities, which is a direct consequence of dumped imports from the subject country;
- iii. Imported product is significantly undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, the domestic industry has been forced to reduce the prices and sell the product at a price where it is suffering significant financial losses.
- iv. Negative profits and return on capital employed are directly a result of dumped imports;
- v. Production, sales and capacity utilization of the domestic industry has been significant lower than earlier achieved levels
- vi. Significant increase in imports has led to significant stock piling with the domestic industry. The domestic industry is unable to liquidate the same even after reducing the prices;
- vii. Growth of the domestic industry has become negative in respect of a number of parameters.

Magnitude of Injury Margin

127. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry determined has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during POI. The injury margin determined are as under:-

INJURY MARGIN TABLE						
Sl. No.	Producer	Exporter	NIP US\$/MT	Landed Price US\$/MT	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin %
1.	Dalian Huarui Heavy Industry Casting Co. Ltd	Dalian Huarui Heavy Industry Casting Co. Ltd	***	***	***	15-25
2.	Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd.	Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd.	***	***	***	5-15
3.	Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co., Ltd ➤ Changzhou Sinojit Wind Energy Tech. Co. Ltd ➤ Jiangyin Henghua Machinery Co., Ltd. Jiangyin City ➤ Jiangyin Qixing Technology Co., Ltd. Jiangyin City ➤ Jiangyin Changling New Energy Co., Ltd. Wuxi City, Jiangsu	Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co., Ltd Techtone HK, Ltd	***	***	***	10-20
4.	Nantong Hongde Mechanical Co. Ltd KOIZUMI Machinery co. Ltd	Nantong Hongde Mechanical Co. Ltd	***	***	***	15-25
5.	Jiangsu Faw Foundary Co., Ltd.	Jiangsu Faw Foundary Co., Ltd.	***	***	***	25-35
6.	Yeong Guan Energy Tech. Group Company Limited ➤ Dongguan Yeong Guan Mould Factory Co., Ltd. ➤ Jiangsu Bright Steel Fine Machinery Co., Ltd ➤ Ningbo Lu Lin Machine Tool Foundry Co., Ltd ➤ Ningbo Yeong Shang Casting Iron Co. Ltd. ➤ Yeong Ghen Asia Pacific Co., Ltd.	➤ Ningbo Yeong Shang Casting Iron Co. Ltd. ➤ Yeong Ghen Asia Pacific Co., Ltd	***	***	***	15-25
	Residual other		***	***	***	35-45

Post disclosure Comments

Submissions by exporter, importer and other interested parties

128. The following submissions were made by producers/exporters/importers/other interested parties

- i. Authority has failed to provide details on the methodology on the basis of which the export price has been established in the disclosure statement. The Authority has made certain adjustments as per the information provided. Authority shall provide details for each supply chain separately; the manner in which the export price was determined for each supply chain should have been recorded.
- ii. Supply chain relating to export of the subject goods by Respondent has been erroneously recorded in the table on dumping margin and injury margin provided in the disclosure statement. Nantong as the producer and exporter. Nantong Hongde has produced and exported the subject

- goods to India during the POI. Koizumi is not involved with the export of the subject goods to India and only process the semi finished product for Nantong Hongde into a finished product. In particular, Koizumi has entered into a production cooperating agreement with Nantong Hongde.
- iii. Anti-dumping margin computed should be based on adjustment for countervailing duty imposed.
 - iv. Yeong Guan Group has provided explanation/information with regard to MET claim. Authority has not rebutted/objected to information and documents/evidences provided. In absence of any objection/rebuttal on part of Designated Authority in the Disclosure Statement regarding non-market economy status of China PR against submissions made in relation to criteria specified in (a) to (d) of para 8(3) of Annexure I is grossly erroneous and presumption of NME taken is not sustainable in law and facts of the case.
 - v. The scope of the PUC has been expanded beyond request of the Domestic Industry. L&T sought initiation of investigation against import of "Castings of Wind Operated Electricity Generator" from China PR. However, the current investigation has been initiated against "Castings for Wind Operated Electricity Generators whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or part of an Equipment/ Component meant for Wind-Operated Electricity Generators". It is not appropriate on the part of the Authority to suo motu revise the scope of the PUC to include parts thereof without giving any cogent reasons for the same and without specifying and giving justification that scope of the PUC has been enhanced.
 - vi. L&T ceased to be Domestic industry and hence the investigation becomes non-est. Pursuant to conclusion of sale of Coimbatore Unit to Bradken India at the beginning of the instant investigation, L&T ceases to be Domestic Industry for the purpose of present investigation. Designated Authority has grossly erred in disregarding the submissions made on maintainability of the instant Petition and holding that both L&T and Bradken India constitute petitioner in the present case.
 - vii. Petitioner is resorting to forum shopping to eliminate any kind of competition in India which is anti-trade, anti-consumer and anticompetitive. Petition was filed without waiting for result of the CVD investigation which clearly shows impatience of the Petitioner and hurry to get rid of high quality imports of the PUC and drive out competition. Instead of giving reasonable amount of time for CVD to show impact on injury caused
 - viii. Petitioner has claimed injury margin of 40% which seems highly unrealistic as compared to the 10% injury margin on which CVD has been imposed. 30% increase in the injury margin as claimed over such short span of time considering the fact that POI in the present investigation is prior to imposition of CVD. Thus, the Petitioner has resorted to forum shopping and claiming injury on inaccurate and misleading data to eliminate competition. Designated Authority has completely ignored such submissions in the Disclosure Statement.
 - ix. Concealment of material information by L&T on sale of the Coimbatore Unit to Bradken.
 - x. Domestic industry has not suffered injury during the POI and observations of Authority on various economic parameters is completely opposite on the face of records depicted even in the Disclosure Statement in terms of demand, imports in absolute terms, price suppression/ depression.
 - xi. Material injury, threat of material injury or material retardation to L&T due to alleged dumped imports, is not established. Petitioner during the POI has been showing upward trend in production, market share, sale and capacity utilization is shown as 41%, which is not an indicator of retardation of an industry.
 - xii. With regard to the supply chain of Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co., Ltd and Nantong Hongde Mechanical Co. Ltd, the interested party has requested to the Authority to provide value of exports during the POI, export price as recorded for dumping margin and landed price as recorded for Injury margin, basis of dumping margin and injury margin computation, namely whether the drawing weight, finished weight or unfinished weight has been considered.

Submissions made by the Domestic Industry

129. The domestic industry inter alia submitted as follows

- i. The authority determined PUC as "Castings for wind operated electricity generators also known as castings for windmills or wind turbines, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component, meant for wind-operated electricity generators".
- ii. To facilitate a fair comparison, the PCN devised and regrouped and rationalized by the Authority. Petitioner does not have reservation on such regrouping, it needs to be recognized that the petitioner has sold the product in unfinished form whereas product has been imported in finished form.
- iii. The weight of the products is required to be considered on one uniform basis in order to undertake apple-to-apple comparison for the purpose of injury margin. Mere addition of finished costs to the NIP of the domestic industry is insufficient for the purpose. The weights associated are also required to be taken into account.
- iv. Since the customs classification is indicative only, the Designated Authority may kindly specify in duty table that the product under consideration should attract duty regardless of the customs classifications under which goods are being cleared by the importers and that the customs classification is indicative only.
- v. Dumping margin and injury margin determined by the Authority in disclosure statement is significantly lower than what has been determined by domestic industry.
- vi. Duty may kindly be imposed on ad-valorem basis as there are a number of different product types, having significant difference in the associated prices.
- vii. The Anti-Subsidy/countervailing Duty is already in place the product under consideration. Accordingly, anti dumping duty payable on the subject goods as per the current investigation can be subjected to the CVD already in place.

Examination by the Authority

130. The Authority has taken note of post disclosure submissions made by the interested parties. The authority notes that most of the submissions are repetitive in nature and these are already examined and addressed at appropriate places in these findings

131. With regard to the submission concerning adjustments done in the export price, since some of the information constitutes business sensitive confidential information of the interested parties, the authority is not bound to disclose such information to the other interested parties. However, the confidential workings of the Export Price and Landed Values have been provided to the exporters wherever requested

132. With regard to the submission concerning Supply chain relating to Nantong Hongde and Koizumi, Authority has taken note of the same.

133. With regard to the submission concerning adjustment of CVD in the ADD, the same has already been considered by the Authority.

134. With regard to the submission concerning dumping margin and injury margin determined by the Authority in disclosure statement is significantly lower than what has been determined by domestic industry, Authority communicated to the interested parties vide mail dated 17th July, 2017 to clarify that the weights reported by the interested parties are finished castings or raw weight of finished castings. Further, in case the interested party has reported the finished castings weight, provide the raw weight of the finished castings i.e. the weight of the unfinished castings.

135. This measure was taken to doubly check the workings and calculations made by Authority and to assure that the workings are in sync with verified data.

136. The Authority notes that the basis of indicating weight in the packing list by exporters and invoice of DI is by and large the same. Changing the weight claimed by exporters will not be appropriate as the same is duly verified from the packing list and the declaration made before Custom Authority.

Indian Industry's Interest and Other Issues

137. The Authority recognizes that imposition of anti dumping duties might affect the price level of the subject goods in India. However, fair competition in Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantage gained, by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

RECOMMENDATIONS

138. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- The product under consideration has been exported to India from the subject country below normal values.
- The domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from subject country.
- The material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country.

139. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the Rules and having established positive subsidy margins as well as injury to the domestic industry caused by such subsidized imports, the Authority is of the view that imposition of anti dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti dumping duty on imports of subject goods from China in the form and manner described hereunder.

140. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, so as to remove the injury to the domestic industry. Since, the product under consideration is already attracting anti-subsidy/countervailing duty under other notifications of Central Government. Accordingly, an amount equivalent to the difference between the quantum of anti dumping duty calculated as per Col No.8 below and the quantum of anti-subsidy/countervailing duty payable, if any, is recommended to be imposed on all imports of the subject goods originating in or exported from China.

Duty Table

SN	Subheading or Tariff Item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Duty amount as % of landed value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	84834000, 85030090, 85030010 in Chapter 84 and 85 of Customs Tariff Act	Castings for Wind Operated Electricity Generators, also known as castings for windmill or wind turbine, whether or not machined, in	China PR	China PR	Dalian Huarui Heavy Industry Casting Co. Ltd	Dalian Huarui Heavy Industry Casting Co. Ltd	18.48
2.			China PR	China PR	Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd.	Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd.	6.27
3.			China PR	China PR	Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co.,	Jiangsu Sinojit Wind Energy	14.44

		raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a subassembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators			Ltd ➤ Changzhou Sinojit Wind Energy Tech. Co. Ltd ➤ JiangyinHenghua Machinery Co., Ltd. Jiangyin City ➤ JiangyinQixing Technology Co., Ltd. Jiangyin City ➤ Jiangyin Changling New Energy Co., Ltd. Wuxi City, Jiangsu	Technology Co., Ltd Tectone HK, Ltd	
4.			China PR	China PR	➤ Nantong Hongde Mechanical Co. Ltd KOIZUMI Machinery co. Ltd	Nantong Hongde Mechanical Co. Ltd	18.64
5.			China PR	China PR	Jiangsu Faw Foundary Co., Ltd.	Jiangsu Faw Foundary Co., Ltd.	28.83
6.			China PR	China PR	Yeong Guan Energy Tech. Group Company Limited ➤ Dongguan Yeong Guan Mould Factory Co., Ltd. ➤ Jiangsu Bright Steel Fine Machinery Co., Ltd ➤ Ningbo Lu Lin Machine Tool Foundry Co., Ltd ➤ Ningbo Yeong Shang Casting Iron Co. Ltd. ➤ Yeong Chen Asia Pacific Co., Ltd.	Ningbo Yeong Shang Casting Iron Co. Ltd Yeong Chen Asia Pacific Co., Ltd	15.46
7.			China PR	China PR	Any other combination than SN 1 to 6		35.92
8.			China PR	Any	Any	Any	35.92
9.			Any	China PR	Any	Any	35.92

Note –

- Castings for wind-operated electricity generators for the purpose of the present notification implies "Castings for wind-operated electricity generators also known as castings for windmill or wind turbine, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators".
- The Anti-Subsidy/countervailing Duty is already in place on Castings for wind operated electricity generators, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a

subassembly, or as a part of an equipment/ component meant for wind-operated electricity generators.
Custom Notification NO. 1/2016-Customs (CVD) dated 19th January, 2016.

141. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

142. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

Dr.INDERJIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority